

ISSN:0975-4431
RNI:MPHIN/2009/29572



नवीन सामाजिक शोध

अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
NAVEEN SAMAJIK SHODH
International Monthly Research Journal

वर्ष-8 अंक-7 (कुल अंक-91) सितम्बर 2016
मूल्य - 100 रुपये

International Research Journal
Research Journal Useful for
Social Development



9893086017
9993673675
8085556284

एम.आई.आफसेट वर्क्स

सभी प्रकार के मल्टीकलर पोस्टर, पम्पलेट,
ब्रोशर, बैनर, दैनिक/साप्ताहिक समाचार
पत्रों एवं मासिक पत्रिकाओं
की आफसेट मशीन द्वारा
छपाई उचित दामों पर की जाती है।

एक बार अवश्य पधारें

कार्यालय 105, बजाज काम्पलेक्स, चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल

प्रधान कार्यालय : 91, रशीदिया स्कूल के पास, बरखेड़ी, भोपाल

mioffset@yahoo.com, mioffset@gmail.com

अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका

नवीन सामाजिक शोध

संस्थापक प्रधान सम्पादक
स्व.डॉ.जी.सी. सक्सेना

प्रधान सम्पादक
राजेन्द्र सक्सेना

प्रबंध संपादक
अभिजीत सक्सेना

संपादक
श्रीमती सविता सक्सेना

उपसंपादक

डॉ. संजय अग्रवाल (चिकित्सक)

डॉ. संतोष धुर्वे (समाजशास्त्री)

डॉ. विजय दुबे (वाणिज्य) ग्वा.

वरिष्ठ शोध अधिकारी
डॉ. कुसुमा भारद्वाज

शोध अधिकारी
डॉ. ममता दुबे ग्वालियर

श्रीमती स्ति मेहरा

ग्राफिक्स
तनवीर कुरेशी

सलाहकार संपादक
राजेश सक्सेना

वर्ष-8 अंक-3

(कुल अंक 87)

मई 2016

R.N.I. M.P.HIN/2009/29572

ISSN-0975-4431

संपादकीय कार्यालय : 25, रूपनगर कालोनी, जे.के. रोड,

भोपाल-462041 (म.प्र.) दूरभाष : 09300279796, 09425704990

Email : naveensamajikshodh@yahoo.com

Website : www.naveensamajikshodh.com

विदेशों में क्षेत्रीय कार्यालय : (विदेशी विषय विशेषज्ञ संपादक)

1. डॉ. राम भारद्वाज चिकित्सक

पो.बॉ. नं. 361, पोस्टल कोड नं. 319, सहम सुलतानेट ऑफ ओमान

2. प्रो. डॉ. सुधाकर कोट्य (अर्थशास्त्री)

प्रोफेसर इकोनॉमिक्स एण्ड मार्केटिंग, स्काईलाईन, युनिवर्सिटी शारजाह यूएई

3. कविता शुक्ला असिस्टेंट प्रोफेसर,

111, शेख रसीद बिल्डिंग, शेख जायद रोड, यू.ए.ई. दुबई

4. डॉ. नमिता चौहान समाजशास्त्री,
आस्ट्रेलिया

5. डॉ. प्रिन्स डेविड दंत चिकित्सक

11, ओलब्रेस्ट एवैन्यू, मार्केट स्ट्रिकल, ओकलैंड 1041, न्यूजीलैंड

6. श्री सजग चतुर्वेदी, स्टैमफोर्ड, यूनिवर्सिटी थाईलैंड

6. श्रीमती ऋति चतुर्वेदी, कनाडा

7. श्रीमती प्रतिभा, कनाडा

8. डॉ. उमेश रस्तोगी, लंदन

सहयोग राशि : देश में : साधारण अंक 100/- वार्षिक : 1000/-

आजीवन सदस्यता: 10000/-

विदेशों में : साधारण अंक : 18 डॉलर, वार्षिक : 180 डॉलर

सारे मुग्तान (मनीआर्डर/चेक/ड्रॉपट) नवीन सामाजिक शोध के नाम से किए जावेंगे। चेक से मुग्तान करने पर रु.30-अतिरिक्त भेजें।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक-राजेन्द्र सक्सेना द्वारा एम.आई आफसेट वर्क्स, 91, रशीदिया स्कूल के पास, बरखेड़ी, भोपाल-8 द्वारा मुद्रित एवं 25, रूपनगर कालोनी, जे.के. रोड, भोपाल-462023 (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक-श्रीमती सविता सक्सेना

सभी लेखों में लेखकों के अपने मौलिक विचार हैं। संपादक अथवा संपादक मंडल का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। हमारा संपादक मंडल पूर्णतः अवैतनिक एवं अत्यावसायिक है। विवाद की स्थिति में सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।

नवीन सामाजिक शोध

इस अंक में _____

1. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक का कृषि वित्त.....डॉ. दीपेश कुमार पाठक - 6
2. आतंकवाद की परिभाषा.....डा. जैनिथ जार्ज - 13
3. जैव विविधता – एक अध्ययनफातिमा बी - 23
4. पर्यावरण संरक्षण और भारतीय संस्कृति.....डॉ. एस.एस यादव - 36
5. Role of woman Entrepreneurs in rural.....Dr. Jitendra Kumar - 46
6. The Rule of Syed Qutb in the Imtiyaz Ahmad Wani - 59
7. Retail Investors : Reluctance and Necessity...Smriti Tiwari Semwal - 67
8. Primery Prevention in Dentistry Ritika Bhardwaj - 72
9. Gas as a green Growth Energy for India Udai Kumar Uprit - 83
10. "Buddhism" Introduction of Gautama Budhdha.....DR. S.K. Ojha - 92

सलाहकार मंडल

- प्रो. डॉ. आई.एस. चौहान, पूर्व कुलपति, बरकतुल्लाह एवं भोज विश्वविद्यालय, भोपाल-म.प्र. | फोन : 0755-2424777
- प्रो. डॉ. विनोद पी. सक्सेना, पूर्व कुलपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर म.प्र. | फोन : 0755-2628055
- प्रो. डॉ. संतोष कुमार श्रीवास्तव, पूर्व कुलपति, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर-म.प्र. |
- प्रो. डॉ. राजपाल सिंह, सदस्य, सलाहकार यूजीसी (उच्च शिक्षा) भारत सरकार | मो. 9425028689
- डॉ. के. के. तिवारी शिक्षाविद्, राज्यपाल अधिकृत ई.सी.सदस्य डीएवीवी इंदौर मो. 9893014415
- वरिष्ठ वकील श्री खलीलउल्लाह खान, पूर्व चेयरमेन, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग भोपाल-म.प्र. | मो. 9826225266
- श्री आई.बी. सिंह, पूर्व निदेशक, ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय, चित्रकूट-म.प्र. | मो. 9329138005
- डॉ. ललित श्रीवास्तव, नेत्र विशेषज्ञ, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश डॉक्टर्स एसोसिएशन, भोपाल-म.प्र. | मो. 9827007500

संपादक मंडल

- ❖ प्रो. संजय एस. अग्रवाल, विभागाध्यक्ष, पीपुल्स मेडीकल कालेज
- ❖ प्रो. अलका डेविड, विभागाध्यक्ष, गृह विज्ञान, शा.सरोजनी नायडू कालेज,
- ❖ प्रो. अरविंद चौहान, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल।
- ❖ प्रो.आर.शंकर, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र, भारतीदर्शन विश्वविद्यालय, तिरुचरापल्ली-तमिलनाडु (620024)।
- ❖ प्रो.परवेज अहमद अब्बासी, विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, वी.एन.एस.जी. विश्वविद्यालय सूरत गुजरात।
- ❖ डॉ० कुमारी चित्रा शर्मा संत हिरदाराम कन्या महाविद्यालय, भोपाल
- ❖ प्रो.डॉ. कामिनी जैन, प्राचार्य शास. स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, पिपरिया
- ❖ प्रो. आभा चौहान, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, जे.एण्ड के।
- ❖ डॉ. वंदना बक्शी, सहायक प्राध्यापक, अंग्रेजी विभाग एकसीलेंस कालेज, कोलार रोड, भोपाल।
- ❖ डॉ. दिनेश परमार, अनुवांशिकी विभाग, ब.वि., भोपाल।
- ❖ डॉ. सुमंगला पटेरिया, सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी विभाग। एकसीलेंस कालेज, कोलार रोड, भोपाल
- ❖ डॉ. आरती श्रीवास्वत, सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग शासकीय कॉलेज नसरुल्लागंज।
- ❖ डॉ.जितेन्द्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, फ़ैकल्टी आफ कामर्स एंड मैनेजमेंट, जी.जी.डी. एस.डी. (पीजी) कालेज, पलवल।
- ❖ डॉ. कुसुमा भारद्वाज, स.प्रा., एकसीलेंस कालेज, कोलार रोड, भोपाल।
- ❖ डॉ. विपिन व्यास, व्याख्याता, लिमनोलॉजी, ब.वि., भोपाल।
- ❖ श्री अजय बिसारिया, व्याख्याता, हिंदी विभाग, अ.मु.वि., अलीगढ़-उ.प्र.।
- ❖ डॉ. संदीप कुमार मल्होत्रा, विभागाध्यक्ष गणित शा. संजय गांधी स्मृति स्नाकोत्तर, महाविद्यालय, गंजबासोदा म.प्र.
- ❖ डॉ. विश्वनाथ मिश्रा, पूर्व प्राचार्य (समाजशास्त्र) कालीचरन पी.जी. कालेज, लखनऊ
- ❖ इंजि. रोहन गुप्ता, एम-2/5, बी.डी.ए. कालोनी, लालघाटी, भोपाल
- ❖ डॉ. अमित कुल्हार, जिला पंचायत भोपाल

सम्पादकीय

चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग अब सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन कमांड सेंटर के प्रमुख कमांडर के रूप में भी जाने जाएंगे। दरअसल सेना की वर्दी में लिपटी हुई यह नई पदवी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के ऊपर उनके मौजूदा अधिकार की पुनः पुष्टि से ज्यादा कुछ नहीं है। शी चीनी संस्थाओं पर अपने नियंत्रण को और सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी नई उपाधि मुख्य रूप से इसी तथ्य को और मजबूत करेगी कि शी उनके सर्वेसर्वा हैं। जहां पूर्व चीनी राष्ट्रपति ने कार्यकारी निर्णय लेने की शक्ति पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए को सौंप दी थी वहीं शी चाहते हैं कि कार्यकारी शक्ति भी उन्हीं के पास रहे। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के ज्वाइंट बैटल कमांड सेंटर के दौरे के दरम्यान शी ने अधिकारियों से एक कमांड प्रणाली बनाने का आग्रह किया, जो कि युद्ध जीतने में सक्षम हो। सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति में एक ऐसे बैटल कमांड की जरूरत है, जो कि अत्यधिक सामरिक तथा रणनीतिक, समन्वित, समयबद्ध, पेशेवर और सटीक हो। उन्होंने कहा कि बैटल कमांड की क्षमताओं में बढ़ोतरी के लिए हरसंभव कोशिश की जानी चाहिए, ताकि वह युद्ध लड़ने और उन्हें जीतने में सक्षम हो सके। अपनी इच्छा के अनुरूप शी ने पीएलए के बड़े पैमाने पर पुनर्गठन की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इसके लिए वह सेना के विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों को एकजुट कर रहे हैं। इसके अलावा चीनी सरकार करीब तीन लाख सेना के जवानों की छंटनी के लिए भी सक्रियता से काम कर रही है। इसके लिए दर्जनों भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है और अक्षम जवानों की पहचान कर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। पीएलए के पुनर्गठन की यह असाधारण प्रक्रिया लंबी चलने वाली है। उम्मीद है कि 2020 तक इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। 1950 के बाद पीएलए का यह सबसे व्यापक और मौलिक पुनर्गठन है। उस समय सिविल वॉर के बाद रूस ने चीन को अपनी सेना के गठन में मदद की थी। उसका मॉडल कुछ-कुछ सोवियत प्रणाली की तरह था। पुनर्गठन के बाद सेना पर सीसीपी की पकड़ मजबूत होगी और सेना पेशेवर तरीके से काम करेगी। हालांकि चीन के इस कदम से कई सवाल खड़े हुए हैं। मसलन चीनी सेना के शीर्ष नेतृत्व की संरचना में बदलाव के मायने क्या हैं? आंतरिक और बाहरी खतरों से निपटने के लिए सेना के जवानों, रिजर्व और गैर सैन्य बलों की क्या भूमिका होगी? हालांकि इससे एक बात पूरी तरह से साफ है कि चीन की भविष्य की सेना आज की मौजूदा सेना से अलग होगी। यही एशिया के देशों की चिंता का मुख्य कारण है। जहां चीन ने अपनी सेना में सुधार और उसके आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है वहीं भारत अपने रक्षा सेक्टर में सुधार के प्रति उदासीन है। दरअसल उचित संस्थागत व्यवस्थाएं एक देश को इस योग्य बनाती हैं कि वह अपनी कूटनीतिक, सैन्य और आर्थिक क्षमताओं का सफल तरीके से प्रयोग कर सके। अफसोस है कि भारत इसके प्रति निष्क्रिय नजर आता है। भारत में अधिकांश सरकारों ने इस संबंध में दीर्घकालिक रणनीतिक सोच की कमी का रोना रोया है। हालांकि किसी भी सरकार ने इस कमी को दूर करने का ठोस प्रयास नहीं किया। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को वास्तव में जो काम करना चाहिए, उसे वह नहीं करती है। अब इसे रक्षा मंत्रालय से संबद्ध कर देना चाहिए और साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ को सरकार को सिर्फ यह सलाह देनी चाहिए कि सेना को कैसे बेहतर बनाएं।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक का कृषि वित्त : एक मूल्यांकन

डॉ. दीपेश कुमार पाठक
(अतिथि विद्वान वाणिज्य)
शासकीय महाविद्यालय—आष्टा

प्रस्तावना

हमारे देश में सहकारी बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत सहकारी समितियों, शहरी सहकारी बैंक, लघु अवधि एवं मध्य अवधि ऋण के लिये राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी बैंक को सम्मिलित किया जाता है। सहकारी बैंकिंग प्रणाली का मुख्य लक्ष्य मध्यम आय वर्ग के लोगों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को ऋण की आवश्यकता पूरी करना है। इस प्रकार से अर्थ व्यवस्था की यह बैंकिंग व्यवस्था देश के वित्त ढांचे में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि तथा उससे सम्बद्ध क्षेत्र की गतिविधियों को दिये जाने वाले ऋण का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 55 प्रतिशत इस बैंकिंग प्रणाली के द्वारा दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने वाली इकाईयों में से लगभग 70 प्रतिशत के साथ ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां इस क्षेत्रों में ऋण देने वाली ऋण व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर है। सहकारी ऋण देने वाली संस्थाएँ कृषि क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋण का लगभग 55 प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराती है। ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ शहरी क्षेत्र में भी ऋण वितरण में सहकारी संस्था का योगदान है। शहरी साख बैंक अपने सदस्य को स्थाई अथवा नगद साख ऋण प्रदान करते हैं। यह ऋण सदस्यों की अचल सम्पत्ति की जमानत अथवा एक या दो बैंक के सदस्यों की अचल सम्पत्ति की जमानत अथवा एक या दो बैंक के सदस्यों की जमानत पर अथवा कृषि उपज, औद्योगिक वस्तुओं, सोने तथा चाँदी के आभूषणों, सहकारी प्रतिभूतियों, स्थायी जमा और बीमा पालिसियों की जमानत पर दिये जाते हैं। अकृषि ऋण समितियां शहरी मध्य वर्ग की बैंकिंग और साख संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करती

है तथा शोषण से उसकी रक्षा करती है। अतः यहां कृषि ऋणों के वितरण में राज्य सहकारी बैंकों की क्या भूमिका है इसके अध्ययन के लिये सोदार्थी ने मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक नर्यादित भोपाल कृषि वित्त संरचना का अध्ययन किया है।

सहकारी कृषि ऋण की संरचना का वर्गीकरण :-

भारत में सहकारिता का ढांचा पिरामिड का रूप लिये हुए है तथा यह संघीय व्यवस्था से संचालित होता है इसका आधार ग्राम स्तर पर स्थापित प्राथमिक सहकारी समितियां और जिला स्तर पर जिला सहकारी बैंक अपने अधीनस्थ सभी प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण देता है और प्रत्येक राज्य स्तर पर एक शीर्षस्थ सहकारी बैंक होता है जो कि राज्य में स्थित सभी जिलों की जिला सहकारी बैंक को ऋण प्रदान करता है और उन पर नियंत्रण भी रखता है। मध्यप्रदेश राज्य के अन्दर मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक शीर्षस्थ सहकारी संस्था के रूप में कार्यरत है। यह मध्यप्रदेश में स्थित 38 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को ऋण देता है और उन्हें नियंत्रित भी करता है तथा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया राज्य सहकारी बैंक के कोषाध्यक्ष के रूप में सहकारिता के क्षेत्र के अंतर्गत कृषि ऋण प्रदान करता है।

सहकारी कृषि ऋण संरचना :-

कृषि ऋण

अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण	दीर्घकालीन ऋण	राज्य सहकारी बैंक
राज्य सहकारी बैंक	केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक	राज्य सहकारी बैंक
केन्द्रीय सहकारी बैंक	प्राथमिक भूमि विकास बैंक	प्राथमिक अकृषि ऋण समिति
प्राथमिक सहकारी साख समितियों		

प्राथमिक कृषि ऋण समिति:-

मध्यप्रदेश राज्य की कृषि साख संस्थाओं के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक अल्पावधि, मध्यअवधि ऋण प्रदान करता है। अल्पावधि व मध्यअवधि ऋण प्रदान की व्यवस्था त्रिस्तरीय जैसे:- प्राथमिक स्तर पर ग्रामीण साख समितियों मध्य स्तर पर जिला सहकारी बैंक एवं उच्च स्तर पर मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक। दीर्घअवधि ऋण प्रदान की व्यवस्था द्विस्तरीय हैं। प्राथमिक स्तर पर जिला स्तरीय सहकारी भूमि विकास बैंक तथा राज्य स्तर पर राज्य स्तर भूमि विकास बैंक।

कृषि साख का वर्गीकरण समय, उद्देश्य, जमानत आदि के आधार पर किया जा सकता है, परन्तु इन आधारों में समय के आधार पर साख के वर्गीकरण को सर्वत्र उपयुक्त माना गया है। समय के आधार पर साख को निम्न वर्गों में रखा जाता है।

साख वर्गीकरण

अल्पकालीन साख	मध्यकालीन साख	दीर्घकालीन साख
---------------	---------------	----------------

1. अल्पकालीन साख :-

इस प्रकार की साख की अवधि प्रायः 12 महीनों की होती है। उपलब्ध साख का उपयोग किसान बीज, खाद, रासायनिक उर्वरक खरीदने तथा श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करने के लिये है। इसका सोधान का भुगतान फसल कटने के बाद कर दिया जाता है।

2. मध्यकालीन साख :-

इस प्रकार के ऋण 12 महीनों से अधिक तथा 5 वर्ष तक के लिये दिये जाते हैं। इसका प्रयोग भूमि प्राप्त करने, मकान बनवाने, भूमि सुधार करने, पशु सम्पत्ति प्राप्त करने, कृषि यंत्र एवं उपकरण खरीदने, कुओं बनवाने, खेतों में पक्की नालियाँ बनवाने के लिये किया जाता है।

3. दीर्घकालीन साख :-

दीर्घकालीन ऋण की अवधि 5 से 20 वर्ष तक की होती है। इन ऋणों को प्राप्त करने के उद्देश्य हैं- भूमि को रहन से छुड़ाना, दीर्घ अवधि कर्ज का भुगतान, ट्रेक्टर, भूमि आदि खरीदना तथा भूमि स्थायी सुधार करना। वर्तमान समय में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक अपनी 22 शाखाओं के द्वारा 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं उनकी 834 शाखाओं के माध्यम से कृषि साख की पूर्ति कर रहा है। साख को ग्रामीण स्तर पर वितरित करने का कार्य 4526 प्राथमिक सहकारी साख समितियों सफलतापूर्वक सम्पन्न कर रही है।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक के कृषि ऋण :-

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक कृषि क्षेत्र में वित्त सुविधा उपलब्ध कराने वाली प्रदेश की एक विशेष

संस्था है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों को अपनी कृषि सम्बंधी आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिये यहां से वित्त प्राप्त होता है। यह बैंक कृषि ऋणों में वृद्धि के लिये प्रयासरत है। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक के कृषि ऋण निम्नानुसार है :-

वर्ष 2014-2015 में जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से रूपये 15 हजार करोड़ के कृषि उत्पादन ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया, जिसके विरोध में 13597.88 करोड़ रु. का ऋण वितरण किया गया। मौसमी कृषि उत्पादन हेतु अल्पकालीन ऋण :-

मौसमी कृषि ऋण उत्पादन हेतु तिलहन और ऑयल पाम पर राष्ट्रीय मिशन खाद सुरक्षा मिशन के अंतर्गत दलहन, आदिवासी, जनसंख्या विकास योजना एवं अन्य फसलों के लिये जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को अल्पकालीन साख सीमा उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2014-2015 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने अपेक्स बैंक को 6600 करोड़ रूपये की साख सीमा उपलब्ध कराई तथा अपेक्स बैंक ने अपना योगदान 1612.45 करोड़ का किया। कुल मिलाकर 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को 7899.56 करोड़ का ऋण कृषि उत्पादन हेतु प्रदान किया गया।

तिलहन उत्पादन :-

वर्ष 2014-2015 में तिलहन और ऑयल पाम पर राष्ट्रीय मिशन योजना अंतर्गत अपेक्स बैंक द्वारा कुल 2628.60 करोड़ की साख सीमा स्वीकृत की गई जिसके विरोध में बैंकों द्वारा 2545.51 करोड़ रूपये का उपयोग किया गया।

दलहन उत्पादन हेतु साख सीमा :-

वर्ष 2014-2015 में दलहन उत्पादन के लिये 135.82 करोड़ की साख सीमा स्वीकृत की गई। जिसके विरोध में बैंकों द्वारा 135.67 करोड़ रु. का उपयोग किया गया।

जनजाति विकास कार्यक्रम हेतु साख सीमा :-

भारत शासन द्वारा वर्ष 1995-96 से जनजाति कृषकों के विकास हेतु प्रारम्भ किये गये कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के चयनित 19 जनजाति बाहुल्य जिलों में से 14 जिला बैंक को 877.03 करोड़ की साख सीमा स्वीकृत की गई। जिसमें 868.92 करोड़ का उपयोग किया गया।

अन्य फसलों हेतु अल्पकालीन साख सीमा :-

वर्ष 2014-15 में नावार्ड ने मौसमी कृषि उत्पादन हेतु तिलहन एवं दलहन के अतिरिक्त अन्य फसलों के लिये 3674.33 करोड़ की अल्पकालीन साख सीमा स्वीकृत की है। साथ ही शीष बैंक ने रवयं की निधियों से 896.65 करोड़ रु. की साख सीमा स्वीकृत की है। जिसका जिला सहकारी बैंक को अधिकतम 4349.46 करोड़ रु. का उपयोग किया गया।

पुनः परिवर्तन ऋण :-

22 जिला बैंकों में रबी मौसम 2014-15 में फसलें क्षतिग्रस्त होने के कारण 38.40 करोड़ रु. के अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन परिवर्तन ऋणों में परिवर्तित किया गया।

उर्वरक नगद साख सीमा :-

वर्ष 2014-2015 में 26 जिला सहकारी बैंकों को 97 करोड़ की उर्वरक नगद साख सीमा स्वीकृत की गई। बैंकों द्वारा स्वीकृत साख सीमा के विरुद्ध 96.32 करोड़ रु. का उपयोग किया गया। जबकि वर्ष 2006-2007 में 75.75 करोड़ रु. स्वीकृत किये गये थे।

उर्वरक वितरण :-

वर्ष 2013-2014 एवं 2014-15 में प्राथमिक समितियों के माध्यम से रासायनिक खाद वितरण की तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार है:-

क्र	खाद का नाम	वर्ष 2006-07 का वितरण	वर्ष 2013-14 का वितरण	वर्ष 2014-15 का वितरण
1	यूरिया	403090	1037849	980138
2	सुपर फास्फेट	180315	447007	369903
3	डी.ए.पी.	244682	649130	618178
4	इफ्को	808197	146516	133316
5	पोटाश	20466	32024	38075
	योग	956750	2312526	2139609

उपर्युक्त तालिका से दृष्टिगत होता है कि, उर्वरक वितरण में बैंक ने उत्तरोत्तर वृद्धि के प्रयास किये हैं, लेकिन वर्ष 2013-2014 के तुलनात्मक 2014-15 में यूरिया वितरण में बैंक पीछे रहा है। अन्य उर्वरक वितरण में भी वृद्धि दर संतोषजनक ही कही जा सकती है।

किसान क्रेडिट कार्ड :-

कृषकों को साख सुविधा प्रदान करने के लिये किसान क्रेडिट कार्ड योजना सम्पूर्ण प्रदेश में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। सहकारी बैंकों के माध्यम से प्रदेश में कृषकों को वर्ष 2005-06 में 26.63 लाख, वर्ष 2006-07 में 28.20 लाख कार्ड वितरित किये गये। जो वर्ष मार्च 2015 तक 51.52 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये जा चुके हैं। इन 8 से 9 वर्षों के अंतराल में किसान कार्ड वितरण की गति मध्यम रही है।

उपर्युक्त सभी कृषि ऋणों के विश्लेषणों से ज्ञात होता है कि, मध्यप्रदेश में कृषि साख सुविधा उपलब्ध कराने में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक का महत्वपूर्ण योगदान है। कुछ अपवाद स्वरूप परिस्थितियों को अलग रख दिया जाये तो मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक भोपाल का कृषि ऋण वितरण में महत्वपूर्ण स्थान है। यह बैंक कृषकों की आर्थिक उत्थान एवं जीवन स्तर सुधारने के लिये पूर्ण प्रयासरत है। और आंकड़ों से ज्ञात भी होता है कि, यह अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये अग्रसर हो रही है। प्रमुख निष्कर्ष :-

1. राज्य कृषि क्रियाओं की कुछ विचित्र विशेषता है। उत्तरी एवं पूर्वी क्षेत्र में गेहूँ पेदावार अधिक है, जबकि दक्षिणी क्षेत्र में धान की। पश्चिमी क्षेत्र में अधिकांश किसान वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन करते हैं। इस कारण उनकी वित्त आवश्यकताओं में भिन्नता पाई जाती है।
2. सरकारी क्षेत्र के द्वारा सामान्यतः राज्य की साख आवश्यकताओं की गणना केवल अल्पकालीन उद्देश्यों से की जाती है। जबकि दीर्घकालीन साख आवश्यकताओं के आगणन की कोई उचित व्यवस्था नहीं है।
3. कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता तथा पूर्व निश्चित आवंटनों के बावजूद वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा कृषि वित्तीय के मामलों में बहुत अधिक उच्चावचन पाये जाते हैं।
4. राज्य में अन्य साधनों की तुलना में सहकारी बैंकों की वित्तीय संसाधन अल्प है।
5. मध्यप्रदेश में नावार्ड का वितरण देश में कुल वितरण केवल लगभग 2 प्रतिशत है।
6. सामान्यतः सावधिक ऋण देते समय कृषि क्रियाओं में आधुनिक तकनीकी को अधिक महत्व प्रदान किया गया है।

सुझाव :-

मध्यप्रदेश कृषि साख के संबंध में विद्यमान समस्याएँ विभिन्न अध्ययनों एवं मूल्यांकनों पर आधारित है। राज्य में कृषि साख की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं :-

1. सहकारी बैंकों का साखा विस्तार कार्यक्रम इस ढंग से नियोजित किया जाना चाहिये, ताकि प्रत्येक शाखा के लिये कुछ चुने हुये गांवों का नियंत्रित क्षेत्र निश्चित हो सकें।
2. ऋण वसूली कार्यक्रम में पर्याप्त लोचकता होना चाहिये ताकि प्राकृतिक विपदाओं एवं प्रतिकूल मौसमी घटकों को ध्यान में रखकर उन्हें सरल एवं उचित रूप से पुनः नियोजित किया जा सकें।
3. किसानों को साख का पर्याप्त प्रवाह बनाये रखना एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस दृष्टि से राज्य में कार्यरत कृषि साख संस्थाओं को प्रभावी ढंग से इसका निराकरण करना चाहिये।
4. यह भी आवश्यक है कि, ग्रामीण शाखाओं में कृषि क्षेत्र के लिये तकनीकी दृष्टि से योग्य कर्मचारियों की पर्याप्त व्यवस्था हों।
5. अन्य विकसीत राज्यों के समान कृषि वित्त व्यवस्था के लिये मध्यप्रदेश में सहकारिता आंदोलन को ओर अधिक मजबूत बनाया जायें।
6. वाणिज्यिक बैंकों के साथ सहकारी बैंकों का तालमेल अनुकूल बनाये रखा जायें।

संदर्भ सूची :-

कॉनिकेल इयर बुक 2016

अमृत सहकार श्री 2007

द क्रोप्रापरेटर जुलाई 2014

सहकारिता में नवाचार 2015

शोध प्रबंध मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक की वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन का अध्ययन 2010

आतंकवाद की परिभाषा

डा. जैनिथ जार्ज

सहायक प्राध्यापक राजनीति शास्त्र

शा. पी.जी. कालेज, पिपरिया

राजनीति और आतंकवाद

आतंकवाद है वर्तमान में और ऐतिहासिक दृष्टि से किया गया है, दुनिया भर की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मुद्दा। आतंकवाद दोनों एक फायदा और नुकसान, राजनीतिक माहौल और राजनीतिक दल में प्रश्न के आधार पर किया जा सकता है। राजनीति हाल के इतिहास में विभिन्न चुनावों में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कर दिया गया है। इस में 2008 संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव (2008 United States presidential election), चार्ली ब्लैक (Charlie Black), अमेरिका के राष्ट्रपति की उम्मीद करने के लिए एक वरिष्ठ सलाहकार जॉन म्क्कां (श्रीवीद डबबंद) एक ने कहा अमरीकी धरती पर आतंकवादी हमले अपने अभियान के लिए एक खड़ा फायदा किया जाएगा।

लोकतंत्र और घरेलू आतंकवाद

घरेलू आतंकवाद और लोकतंत्र के बीच का रिश्ता जटिल है। अनुसंधान कि इस तरह के आतंकवाद को सबसे जातियों में मध्यवर्ती राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ सामान्य है और पता चलता है कि कम से कम आतंकवाद के साथ इस देश देश के सबसे लोकतांत्रिक देश देश के हैं। हालांकि, एक अध्ययन से पता चला कि आत्मघाती आतंकवाद के इस सामान्य नियम को एक अपवाद हो सकती है। सबूत आतंकवाद के इस विशेष विधि के संबंध में है कि हर आधुनिक आत्महत्या अभियान एक लोकतंत्र-राजनीतिक स्वतंत्रता का एक काफी डिग्री के साथ एक राज्य लक्षित किया है पता चलता है। इस अध्ययन से पता चला कि रियायतें आतंकवादियों के लिए 80 और 90 आत्मघाती हमलों के लिए के दौरान उनकी बारंबारता में वृद्धि से सम्मानित किया गया है।

गैर में आतंकवाद-लोकतंत्र के कुछ उदाहरण फ्रांसिस्को फ्रेंको के अंतर्गत है, शिनिंग पथ (Shining

Path) पेरू में अल्बेर्तो फुजीमोरी (Alberto Fujimori) के अंतर्गत है, कुर्दिस्तान वर्कर्स (Kurdistan Workers Party) पार्टी, जब तुर्की दक्षिण अफ्रीका में सैन्य नेताओं और (ANC) ने इस पर राज किया (ETA) स्पेन में शामिल हैं। इस जैसे लोकतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और फिलीपिंस भी घरेलू आतंकवाद अनुभवी है।

जबकि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र अन्य शासनों, इस तरह के एक राज्य के भीतर आतंकवाद के एक अर्थ नियम की तुलना में उच्च नैतिक जमीन की भावना का दावा मई नागरिक स्वतंत्रताओं espousing एक कथित दुविधा कारण हो सकता है कि क्या और इसके नागरिक स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए इस प्रकार से निपटने में निष्प्रभावी माना जा रहा जोखिम समस्याय या वैकल्पिक रूप से और इसके नागरिक स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित करने के लिए इस प्रकार नागरिक स्वतंत्रताओं का समर्थन करने के अपने दावे जोखिम उठाया इस दुविधा, कुछ सामाजिक सिद्धांतों, बहुत अच्छा अभिनय आतंकवादी (की प्रारंभिक योजनाओं में) खेल सकते हैं अर्थात्, राज्य देलेगितिमिजे को समाप्त होगी।

आतंकवाद की परिभाषा

ऐसे कम ही लोग होंगे जिन्हें अमरीका पर हुए हमलों को आतंकवादी करार देने में कोई हिचक या आपत्ति होगी।

लेकिन खुद आतंकवाद को किस तरीके से परिभाषित किया जाए, यह अब भी विवाद का एक मुद्दा है। इस संवेदनशील मामले में प्रचलित विचारधारा यह है कि किसी एक के विचार में जो आतंकवादी है, वह दूसरे के विचार में स्वतंत्रता सेनानी हो सकता है।

ऐसे में दोनों ही पक्षों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी मिलनी चाहिए। अब यूरोपीय संघ आतंकवाद की एक सर्वसम्मत परिभाषा तैयार करने पर विचार कर रहा है।

आतंकवाद के खिलाफ

इसी सिलसिले में यूरोपीय देशों के बीच मौजूदा प्रत्यर्पण संधि की जगह आतंकवादियों की गिरफ्तारी के लिए एक नया वारंट जारी करने पर विचार चल रहा है।

इसके अलावा आतंकवादियों के खिलाफ विश्व भर में लड़ाई छेड़ने और उनके नेटवर्क को तहस-तहस करने की बात तो है ही।

आतंकवादियों के खिलाफ इस लड़ाई में दुनिया के सभी देश एक-जुट नजर आ रहे हैं।

विवाद का मुद्दा

इन सभी कोशिशों के बावजूद आतंकवाद की परिभाषा अभी तय नहीं हो पाई है।

यूरोप के कुछ ही ऐसे देश हैं जिनके कानून में आतंकवाद की परिभाषा दी गई है।

ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहाँ आतंकवादी हरकतों को कानूनी तौर पर परिभाषित किया गया है। उसके मुताबिक ऐसी कोई भी हरकत आतंकवाद है जिसमें किसी सरकार पर किसी काम को करवाने के लिए गैरकानूनी तरीके से जबरन दबाव डाला जाए।

साथ ही आम जनता को राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक कारणों से धमकाना भी ब्रिटेन के कघनून के मुताबिक आतंकवादी हरकत है।

आतंकवादी हरकत

आतंकवाद की मौजूदा कघनूनी परिभाषा के मुताबिक वह हरकत आतंकवादी मानी जाएगी जिसमें—

- आम जनता के खिलाफ हिंसक कार्रवाई की गई हो
- आम जनता की जिंदगी को खतरा हो
- आम जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा को क्षति पहुँचती हो
- राष्ट्र की संपत्ति को क्षति पहुँचती हो

यूरोपीय संघ का मसौदा

अब आतंकवाद को परिभाषित करने के लिए यूरोपीय संघ द्वारा तैयार किए जा रहे मसौदे में यह प्रस्ताव है कि इसकी नई परिभाषा में निम्नलिखित को भी शामिल किया जाए—

- हत्या और अगवा करना
- आम यातायात के साधन छीनना
- जहरीले पदार्थ फैलाना
- कम्प्यूटर नेटवर्क को नष्ट करने की कोशिश करना

मसौदे की खघमियाँ

आतंकवाद की प्रस्तावित परिभाषा में आतंकवादी के उद्देश्य की चर्चा नहीं की गई है।

यानि हर हत्यारा आतंकवादी होगा, यह जरूरी नहीं, क्योंकि हर हत्या का असर व्यापक स्तर पर नहीं पड़ता, और न ही हर हत्या का उद्देश्य आतंकवाद फैलाना होता है।

लेकिन प्रस्तावित मसौदे में इस पहलू पर विचार नहीं हुआ है।

इसके अलावा कुछ देशों द्वारा आतंकवाद को खुले तौर पर बढ़ावा देने की भी मसौदे में कोई चर्चा नहीं है।

गृहमंत्री चिदंबरम के श्मगवा आतंकवादर वाले बयान पर उठा बवाल अब थोडा ठंडा पड़ गया है इसलिये कुछ चीजें लिखी जा सकती है, बवाल और आंधी के माहौल में कुछ सुनाई नहीं देता इसलिये उसके थमने के बाद ही हम चीजें साफ रख सकते है.र

भगवा आतंकवाद (अगर किसी को आपत्ति ना हो तो हम हिंदू आतंकी संगठन का मुद्दा कह सकते हैं) पहली बार सतह पर मालेगांव में दूसरी बार हुए बम धमाकों के वजह से आया. इसलिए मुझे इस पूरे मुद्दे पर कुछ बताना है. भारी दबाव और विरोध के बावजूद उस लोगों के सामने लाने में भूमिका निभाने में पहला नाम अगर लेना है तो महाराष्ट्र के पूर्व एटीएस चीफ हेमंत करकरे का लेना होगा.

उस वक्त हमने कई बार इस पर बात की थी और वो इस पूरे मामले पर क्या सोचते थे ये मुझे पता है. हेमंत करकरे की छवि पुलिस विभाग में हमेशा एक इमानदार इन्वेस्टिगेशन अधिकारी की रही है. उन्हें मीडिया का चहेता अधिकारी नहीं कहा जा सकता लेकिन चुनिंदा पत्रकारों से जरूरत के हिसाब से रुबरु होते थे.

मालेगांव धमाकों की जांच शुरू हुई तभी उन्हें ये अंदाजा हो गया था की ये किसी ऐसे आतंकी संगठन का काम नहीं है जिनके बारे में हर रोज अखबारों में छपता है और टीवी पर दिखता है. इसमें से कई रिपोर्ट सूत्रों के आधार पर होती हैं और बिना किसी छानबीन के सिर्फ जानकारी देने वाले पुलिस अधिकारी का नाम छुपाकर बेझिझक छापी जाती है. यूं कहे कि गृहमंत्री के बयान पर आपत्ति उठाने वाली पार्टियां इसे शहरा आतंकवाद कहती हैं. (सबूत की जरूरत हो तो शिवसेना का मुखपत्र सामना पढ़ सकते हैं).

पहली गिरफ्तारी (कानून की भाषा में इसे एक्यूज्ड नंबर 1 कहते हैं) थी साध्वी प्रज्ञा की. भगवा साध्वी के भेष में प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जब नासिक की जेल में लाया गया तब ये तुरंत राजनीतिक मुद्दा बन गया. अब तक बम धमाकों से जुड़े मामलों में पुलिस की हर गिरफ्तारी को सच मानकर ट्रयाल चलानेवाली मीडिया में भी इस गिरफ्तारी पर सवाल उठाये गये. अपने आपको हर एक सौ बार सेक्युलर कहने वाली महाराष्ट्र की कांग्रेस एनसीपी सरकार में भी हड़कंप मचा. दूरे सुरों में उनके मंत्री भी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे. हर चीज को राजनीतिक तरीकों से तोलने वाले महाराष्ट्र के गृहमंत्री ने पहली बार करकरे को बुलाकर पूछा कि श्आपने ये क्या कर के रख दिया है, उम्मीद करता हूं आपके पास इस सबके सबूत होंगे.

मामला यहीं नहीं रुका. इस मामले से एक ऐसे हिंदू आतंकी संगठन का खुलासा हुआ जिससे सेक्युलर स्टेट कहलाने वाले देश की नींव हिल गई. शिवसेना, बीजेपी और मीडिया के टारगेट बने करकरे मीडिया से और दूर चले गए. जिसके वजह से एक तरफा खबरों की झड़ी लग गई. एक दिन हमारे किसी एक चैनल पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चला.

जाहिर सी बात है हम भी सब काम पर लगे. बड़ी मुश्किल से मेरे एसएमएस का करकरे ने जवाब दिया, कहा श्दपतर में नहीं मिलूंगा श् तय करके हम कहीं और मिले. उनका पहला सवाल ये था मेरी गलती

क्या है? अगर जांच प्रज्ञा सिंह ठाकुर और उसके साथियों की तरफ इशारा करती है तो गिरफ्तार तो करना ही है. कानून कोई धर्म नहीं देखता. इसके आगे जो करकरे ने कहा वो सचमुच हम सबको विचार करने पर मजबूर करेगा. ये तो अच्छा है कि मैं हिंदू हूँ ऊपर से ब्राम्हण, वरना आरोप लगाने वालों को एक और मुद्दा मिल जाता..

देश भर में इस तरह के और धमाकों का प्लान करने के लिए बुलाई गई इस संगठन की बैठक र सीडी एटीएस के हाथ लगी, जिसके बाद कई आवाजें बंद हुई. यही सीडी जब टीवी टुडे नेटवर्क ने चलाई तब ऐसे विचार किस तरह से फैलाये जा रहे है और किस तरह से कुछ संगठन इनका छुपा समर्थन करती है, ये बात भी सामने आई. इसलिए गृहमंत्री को संसद में इस पर बयान देना पड़ा. अब उन्होंने क्या टर्मिनॉलॉजी इस्तेमाल की इस पर बेवजह बवाल करने से बेहतर ये होता कि इसे स्वीकार कर बीजेपी-शिवसेना इसका निषेध करती लेकिन ऐसा नहीं हुआ. नक्सलवाद को रेड टेरर, रेड कॉरिडॉर वगैरह कहने वाली हमारी संस्कृति को अब भगवे शब्द पर भी ऐतराज नहीं होना चाहिये. और एक बात अगर भगवा रंग संस्कृति से जुड़ा है तो राजनीतिक पार्टी के मंच पर भी इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिये. हर बात को राजनीतिक रंग देने के बजाय आतंकवाद के रंग पहचान कर कार्रवाई करें तो देश में आतंकवाद का निपटारा शायद जल्दी हो पायेगा.

राज्य आतंकवाद

राज्य आतंकवाद की अवधारणा विवादास्पद है. राज्यों द्वारा सैन्य कार्रवाई के दौरान युद्ध आम तौर पर आतंकवाद, तब भी जब वे महत्वपूर्ण नागरिक हताहत शामिल विचार नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष ने संयुक्त राष्ट्र काउंटर के आतंकवाद समिति का मानना है कि इस समिति इस विषय पर 12 अंतरराष्ट्रीय समझौतों के प्रति जागरूक किया गया है और उनमें से कोई भी नहीं है जो एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी अवधारणा नहीं थी राज्य आतंकवाद, को भेजा. यदि राज्यों को उनकी सत्ता का दुरुपयोग, वे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों से निपटने के खिलाफ न्याय किया जाना चाहिए युद्ध अपराधों (war crimes), अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (international humanitarian law). पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव (Secretary & General) कोफी अन्नान कि यह कथित पर बहस अलग सेट करने के लिए समय है ने कहा है कि राज्य के आतंकवाद इस राज्यों द्वारा बल का प्रयोग (use of force by states) पहले से ही पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत विनियमित है, हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि चाहे आतंकवाद की परिभाषा के प्रश्न पर सरकारों के बीच के अंतर के, क्या है और स्पष्ट है हम सब पर क्या सहमत कर सकते हैं स्पष्ट कर दिया निर्दोष नागरिकों पर किसी भी विचार पर हमला, चाहे एक के कारण की है, है अस्वीकार्य है और आतंकवाद की परिभाषा

में हो गया।

राज्य आतंकवाद सरकारी एजेंटों या बलों द्वारा आतंकवादी वारदातों का उल्लेख करने के लिए प्रयोग किया गया है। इस राज्य के संसाधनों का एक राज्य के विदेशी नीतियों, द्वारा ऐसे ने अपनी सैन्य का उपयोग करके सीधे राज्य आतंकवाद माना के अधिनियमों के प्रदर्शन करने के रूप में रोजगार के इस्तेमाल को शामिल राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर, माइकल जवीस है कि लंदन की जर्मनी की बमबारी और अमेरिका परमाणु विनाश के शामिल हैं उदाहरण cites हिरोशिमा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान. उन्होंने कहा कि आतंक रणनीति का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय संबंधों में और आम बात है कि राज्य की गई है और आतंकवाद की एक और अधिक संभावना बनी हुई है नियोजित विद्रोहियों से अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर का तर्क है। वे भी अदालत में तलब पहली हड़ताल (First strike) संकट प्रबंधन में परमाणु हथियारों का प्रयोग कर के गर्भित धमकी के साथ इस का जो बंधक दुनिया धारण एक रूप है, के रूप में बलपूर्वक कपचवसवउंबल के आतंक का एक उदाहरण के रूप में विकल्प कहते हैं कि आतंकवाद के संस्थागत रूप है कि विश्व युद्ध डालूंगा निम्नलिखित जगह ले ली परिवर्तन का एक परिणाम के रूप में हुई बहस है। इस विश्लेषण, राज्य आतंकवाद को विदेश नीति के एक फार्म के रूप में प्रदर्शित में उपस्थिति और सामूहिक विनाश के अस्त्रों का इस्तेमाल करके और आकार का था कि इस राज्य के व्यवहार के तेजी से बढ़ते स्वीकार किए जाते हैं फार्म का नेतृत्व करने के लिए इस तरह की हिंसक व्यवहार की legitimizing (माइकल स्तोहल, इस महा शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय आतंक कागज पर प्रस्तुत की इंटरनेशनल स्टडीज एसोसिएशन, अटलांटा, 27 मार्च की बैठक वार्षिक-1 अप्रैल 1984 भयानक धीरज से परे विदेश नीति राज्य आतंकवाद की. 1988 राज्य आतंकवादी के रूप में गतिशीलता सरकारी हिंसा और दमन, 1984 49).

राज्य आतंकवाद को भी सरकारी एजेंटों या बलों, ने शांति समय क्रियाओं का वर्णन करने के लिए इस बम विस्फोट के इस तरह के रूप में प्रयोग किया गया है है पैन हूँ उड़ान 103 की उड़ान (Pan Am Flight 103 flight). इस अवधारणा को भी वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है राजनीतिक दमन (political repression) सरकारों द्वारा अपने स्वयं के नागरिक आबादी के खिलाफ इस उद्देश्य के साथ डर उत्तेजित करने के लिए उदाहरण के लिए, ले जा रही है और नागरिक क्रियान्वित बंधक (hostage) या एक्स्ट्रजुडिकिअल उन्मूलन (extrajudicial elimination) अभियान सामान्यतः आतंक माना जाता है या आतंकवाद, उदाहरण के लिए के दौरान लाल आतंक (Red Terror) या महान आतंक (Great Terror), इस तरह के कार्यों अक्सर भी रूप में वर्णित हैं देमोसिदे (democide) जो राज्य आतंकवाद के बराबर होने का तर्क दिया गया है, इस है कि लोकतंत्र छोटी देमोसिदे है पाया

है पर अनुभवजन्य अध्ययन करता है।

रणनीति

आतंकवाद का एक रूप है असममित युद्ध (asymmetric warfare) और अधिक जब सीधे आम है पारंपरिक युद्ध प्रणाली (conventional warfare) या तो (भिन्नता के लिए उपलब्ध बलों में) या कारण नहीं किया जा सकता है कि नीचे के संघर्ष को हल करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है।

जिसमें आतंकवादी रणनीति का उपयोग किया जाता है कि सन्दर्भ से है अक्सर एक बड़े पैमाने पर, अनसुलझे राजनैतिक संघर्ष (conflict). संघर्ष के इस प्रकार व्यापक रूप से बदलती है ऐतिहासिक उदाहरणों में शामिल हैं

- अलगाव (Secession) एक क्षेत्र की एक नई संग्रभु राज्य बनाने के लिए
- प्रभुत्व क्षेत्र या संसाधनों के द्वारा विभिन्न जातीय समूहों (ethnic groups)
- सरकार का एक विशेष रूप है, का आरोपण जैसे लोकतंत्र, धर्मतन्त्र, या अराजकता
- एक जनसंख्या का आर्थिक हानि
- एक घरेलू सरकार या कब्जे में करने के लिए विपक्ष सेना

आतंकवादी हमलों में अक्सर डर और प्रचार को अधिकतम करने के लिए लक्षित कर रहे हैं। व आमतौर पर उपयोग विस्फोटक या जहर है, लेकिन वहां भी आतंकवादी हमलों का उपयोग करने के बारे में चिंता का विषय है सामूहिक विनाश के अस्त्रों. आतंकवादी संगठनों को प्रेम में आमतौर पर विधिपूर्वक योजना हमलों और प्रतिभागियों ट्रेन मई, संयंत्र मुखौटे/जेटों और समर्थकों के माध्यम से या फिर से पैसे जुटाने संगठित अपराध आधुनिक संचार के माध्यम से हो सकता है दूरसंचारपुराने फैशन विधियों, या के माध्यम से जैसे कूरियर एस

कारण

कई राय आतंकवाद के कारणों के विषय में मौजूद हैं। रेंज जनांकिकीय को सामाजिक (socioeconomic) राजनीतिक कारणों के लिए. जनांकिकीय कारणों और भीड़ उच्च विकास दर शामिल हो सकते हैं। सामाजिक कारणों गरीबी, बेरोजगारी और भूमि कार्यकाल समस्याओं शामिल हो सकते हैं। राजनैतिक कारण शामिल हो सकते हैं दिसेंफ्रंचिसेमेंट (disenfranchisement), जातीय संघर्ष (ethnic conflict), धार्मिक संघर्ष (religious conflict), प्रादेशिक संघर्ष (territorial conflict), संसाधन, या भी बदला लेने का उपयोग करने के लिए कारक है कि मई को योगदान आतंकवाद करने के लिए जिसने दिया

राजनीतिक दिसेंफ्रंचिसेमेंट

राजनीती, सामाजिक और आर्थिक असमानता

उच्च बेरोजगारी

अर्थव्यवस्थाओं ठंड

अतिवाद

जातीय संघर्ष (Ethnic conflict)

धार्मिक संघर्ष (Religious conflict)

प्रादेशिक संघर्ष (Territorial conflict)

ऊँचा जनसंख्या वृद्धि (population growth) दरें (इतनी-युवाओं कहलाता है)

कुछ मामलों में, एक आतंकवादी हमले के लिए तर्क अनिश्चित हो सकती है (जिसके लिए कोई समूह या व्यक्तिगत जिम्मेदारी का दावा है) या किसी भी बड़े पैमाने पर सामाजिक संघर्ष करने के लिए असंबंधित (जैसे कई हमलों में के रूप में इस टोक्यो मेट्रो पर सरीन गैस हमले (Sarin gas attack on the Tokyo subway) के द्वारा शिनरिक्यो (Aum Shinrikyo).

एक वैश्विक अनुसंधान रिपोर्ट एक समावेशी दुनिया सभी महाद्वीपों से शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने तैयार की वर्तमान दिन आतंकवाद के कारणों का विश्लेषण किया है। यह निष्कर्ष तक पहुँच गया है कि जैसे दुनिया भर में आतंकवाद के कार्य १ आर्थिक बाजार.वहाँ मांग के लिए है आतंकवादियों (terrorists) द्वारा रखा लालच (greed) या शिकायतों.पूर्ति (Supply) रिश्तेदार वंचित ट्रिपल घाटे में जिसके परिणामस्वरूप द्वारा चालित है – विकास घाटा (deficit), लोकतांत्रिक घाटे और गरिमा घाटा.आतंकवाद के अधिनियमों की आपूर्ति और मांग के बीच प्रतिच्छेदन के बिंदु पर जगह ले लो.उन लोगों ने मांग का उपयोग डाल धर्म और अन्य कमदवउपदंजवते के रूप में उन वाहनों की आपूर्ति की ओर से संबंध स्थापित करने के लिए.इस पैटर्न सभी परिस्थितियों से लेकर में मनाया जा सकता है कोलम्बिया (Colombia) को कोलंबो और फिलीपिंस इस करने के लिए फिलीस्तीन.

आतंकवाद को जवाब

भारतीय सेना (Indian Army) कर्मियों के दौरान एक खड़े गार्ड उड़ जाना इस्लामी आतंकवादियों के साथ श्रीनगर, भारत.

प्रतिक्रियाओं को आतंकवाद के दायरे में व्यापक रहे हैं। वे इस के फिर से 'सपहदउमदजे शामिल कर सकते हैं राजनीतिक स्पेक्ट्रम (political spectrum) और reassessments की मौलिक मूल्यों (fundamental values).शब्द आतंकवाद, कि यह आतंकवादी अभिनेताओं में निर्देशित है imply-

ing एक संकरा अभिधान दिया है।

प्रतिक्रियाओं के विशिष्ट प्रकार में शामिल हैं:

लक्षित कानून, आपराधिक प्रक्रिया, भेजा गया, और बढ़ाया पुलिस शक्तियाँ

इस तरह के दरवाजे पर ताला लगा या यातायात बाधाओं के रूप में जोड़ने का लक्ष्य सख्त हो,

अग्रकय या प्रतिक्रियाशील सैन्य कार्रवाई

अग्रकय या प्रतिक्रियाशील सैन्य कार्रवाई

अग्रकय मानवीय गतिविधियों

और अधिक दयालु पूछताछ और निरोध नीतियों

एक वैध उपकरण के रूप में यातना के आधिकारिक स्वीकृति

मास मीडिया

मीडिया जोखिम उन आतंकवाद से बाहर ले जाने का प्राथमिक लक्ष्य है, मुद्दों कि अन्यथा मीडिया ने नजरअंदाज कर दिया जाएगा बेनकाब करने के लिए किया जा सकता है। कुछ हेरफेर और शोषण को मीडिया के लिए इस पर विचार करें, दूसरों, एक को देखने के द्वारा व्यक्त की ही है जो अन्यथा वैकल्पिक दृष्टिकोण करने के लिए आवाज देना नहीं है एक उच्च नियंत्रित मास मीडिया, का एक लक्षण हो करने के लिए आतंकवाद पर विचार पॉल वाटसन (Paul Watson) जो क्योंकि क्या आप किसी अन्य तरीके से भर में आपकी जानकारी नहीं मिल सकता है कि नियंत्रित मीडिया आतंकवाद के लिए, जिम्मेदार है कहा गया है। पॉल वाटसन का संगठन समुद्र मचीमतक (Sea Shepherd) स्वयं किया गया ब्रांडेड है पारिस्थितिकी आतंकवादी (eco&terrorist), हालांकि यह दावा है कि कोई भी हताहत कारण नहीं है।

इस मास मीडिया अक्सर आगे और आतंकवाद को हतोत्साहित करने के लिए संगठनों को आतंकवाद में स्व (के माध्यम से-संयम या विनियमन) शामिल सेंसर करेंगे.बहरहाल, इस संगठनों आतंकवाद के जनसंचार माध्यमों में दिखाये जाने के लिए और अधिक अतिवादी कृत्यों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।

इस मौसम अंडरग्राउंड (Weather Underground) जो है, जबकि कोई हताहत कारण, विभिन्न दुनिया राजनीतिक मुद्दों के लिए मीडिया का ध्यान लाने के लिए आतंकवादी वारदातों का प्रदर्शन एक उग्रवादी संगठन अमेरिका गया था। इस मुद्दे से कई संक्षिप्त दिए गए समाचार सेवाओं द्वारा आतंकवादी वारदातों के संबंध में ही उल्लेख है।

सन्दर्भ

रोडिन, डेविड (2006). आतंकवाद ई. क्रैग (Ed-) में, रौत्लेदगे विश्वकोश दर्शनशास्त्र की लंदन रौत्लेदगे मलायी लोगों की विरोधी जापानी सेना ब्रिटानिका संक्षिप्त

डॉ० क्रिस क्लार्क, 16 जून, 2003 रोनाल्ड रीगन, राष्ट्रीय रूढ़िवादी राजनीतिक कार्रवाई करने के लिए भाषण सम्मेलन 8 मार्च, 1985. इस पर स्पार्टाकुस शैक्षिक (Spartacus Educational) वेब साइट राष्ट्रपति को पूरा अफगान अंतरिम प्राधिकरण के अध्यक्ष के साथ राष्ट्रपति चर्चा प्रगति युद्ध में आतंकवाद पर राष्ट्रीय गार्ड के लिए व्हाइट हाउस वेब साइट फरवरी 9, 2006

सुधा रामचंद्रन इराक में पहिया पीछे मौत एशियाई टाइम्स (Asian Times), 12 नवंबर 2004, विद्रोही गुटों कि उपयोग आत्मघाती हमले इसलिए उनके हमलों पसंद नहीं है आत्म-घाती आतंकवाद के रूप में वर्णित किया जाना है। वे शहीद... जैसे शब्दों का उपयोग करना पसंद करते हैं

एलेक्स पेरी कितना टिप करने के लिए आतंकवादी टाइम पत्रिका (Time Magazine), सितम्बर 26 (September 26), 2005. इस. तमिल टाइम्स, जरूर है कि टैग विवाद होता. अन्य गुरिल्लाओं और आत्मघाती हमलावरों की तरह, वे स्वतंत्रता सेनानियों की अवधि को पसंद करते हैं।

आतंकवादरु अवधारणाओं, कारण होता है और संघर्ष रेसोलुशन जॉर्ज मेसन विश्वविद्यालय (George Mason University) संस्थान संघर्ष विश्लेषण और संकल्प के लिए (Institute for Conflict Analysis and Resolution), मुद्रित को सुरक्षा खतरा कटौती एजेंसी, किले Belvoir, वर्जीनिया, जनवरी 2003 तक

थिओडोर पी. सेतो आतंकवाद की नैतिकता इस में एक सूची भी शामिल हैं बार (जपउमे) पर प्रकाशित जुलाई 23 (July 23) 1946 जो उन इरगुन द्वारा शुरू करो एक प्रमुख सदस्य है जो शुरू किया गया था सहित यहूदी आतंकवादी कार्रवाइयों, के रूप में वर्णित किया गया

BBC खबर प्रोफाइल मेनाचेम शुरू शुरू के आदेश के तहत बीबीसी वेबसाइट भूमिगत आतंकवादी समूह इरगुन हिंसा के अनेक कार्य करता किया।

जैव विविधता - एक अध्ययन

फातिमा बी

प्रोफेसर वनस्पती शास्त्र

शास. महाविद्यालय नसरुल्लागंज

इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष का केन्द्रीय विषय है 'आक्रमणकारी बाहरी प्रजातियां'। आक्रमणकारी बाहरी प्रजातियां ऐसे पादप पशु और पैथोजन्स और अन्य जीव हैं जो खास पारिस्थिकीतंत्र में पैदा नहीं हुए थे लेकिन वहां प्रवेश कर पर्यावरणीय नुकसान पहुंचा सकते हैं।

महान प्रकृतिविद चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत 'योग्यतम की उत्तरजीविता' के अनुसार प्रजातियों का विलुप्तीकरण प्राकृतिक प्रक्रिया है लेकिन आज प्रजातियों के विलुप्त होने की दर चिंताजनक है। इस कारण पारिस्थितिकी के जैविक और अजैविक घटकों का ताना-बाना बिगड़ रहा है। जिस प्रकार एक जाल का धागा खींचने या तोड़ने से सारा जाल बिगड़ जाता है, उसी तरह एक पौधे या जीव के लुप्त होने पर उस पर आश्रित अन्य जीव प्रजातियां भी प्रभावित होती हैं। इस प्रकार भोजन श्रृंखला और खाद्य जाल प्रभावित होने का असर पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर देखा जा सकता है।

पिछले पचास वर्षों में जहां मानव जनसंख्या दोगुनी हुई है, वहीं जीव-जगत और पेड़-पौधों की प्रजातियों के विलुप्त होने की गति में तीव्रता आई है। वैज्ञानिकों के अनुसार उष्णकटिबंधीय वनों के विनाश के कारण प्रजातियों का सामूहिक विलुप्तीकरण हो जाता है। विश्व के तीन समृद्ध जैव विविधता केन्द्रों अमेजन बेसिन, कांगो द्रोणी प्रवहरण के देशों तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में यह प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। एक अनुमान के अनुसार निकट भविष्य में लगभग 30,000 पादप प्रजातियां हमसे अलविदा कह देंगी।

सवाल है कि आखिर विलुप्तीकरण का कारण क्या है? और जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम दैनिक जीवन में भोजन, ईंधन, चारा, वस्त्र आदि के लिए पेड़-पौधों और उनके उत्पादों पर निर्भर हैं। अतिरिक्त दोहन के कारण अनेक वनस्पतियों के विलुप्त होने का खतरा

होता है जिसके कारण हमारी अनेक आवश्यकताओं पर असर पड़ता है। प्रजातियों के विलुप्तीकरण के दो कारण हो सकते हैं पहला प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित।

भूस्खलन, बाढ़, सूखा, वन में लगने वाली आकस्मिक आग आदि प्राकृतिक कारणों के कारण कभी-कभार किसी प्रजाति का पूरा वंश ही समाप्त हो जाता है। कीड़ों और रोगों की चपेट में आने के कारण भी कभी-कभी कोई प्रजाति विलुप्त हो सकती है और कुछ की प्रजनन क्षमता दुर्बल होने के कारण उनकी विलुप्ति की संभावना बढ़ जाती है। कभी-कभार प्रजातियों के बीच प्राकृतिक प्रतिस्पर्धा या बदले परिवेश में अपने आप को अनुकूल न कर पाना भी प्रजातियों के विलुप्त होने का कारण बनता है। हालांकि वर्तमान में पौधों की प्रजातियां विलुप्त होने के लिए मानव निर्मित कारकों का अधिक योगदान है। तथाकथित विकास जैसे सड़कों का निर्माण, कृषि एवं उद्योगों की आवश्यकता के चलते वनों के उजड़ने के कारण भी प्रजातियों को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है।

विदेशी खरपतवारों के आक्रमण के कारण भी जैव विविधता को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। उदाहरण के लिए नील नदी की मछली, नाइल पर्व को पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला गया तो वहां की सिलचिड मछलियों की दो सौ से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो गईं। इसी प्रकार गेहूं के साथ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से आयातित गाजर घास तथा शोभाकारी पौधे के रूप में मैक्सिको से लाए गए लेंटाना ने भारत की जैव विविधता के लिए गंभीर चुनौती पैदा की है।

अंतरराष्ट्रीय संस्था वर्ल्ड वाइल्ड फिनिशिंग ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि 2030 तक घने जंगलों का 60 प्रतिशत भाग नष्ट हो जाएगा। वनों के कटान से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी से कार्बन अधिशोषण ही वनस्पतियों व प्राकृतिक रूप से स्थापित जैव विविधता के लिए खतरा उत्पन्न करेगी। मौसम के मिजाज में होने वाला परिवर्तन ऐसा ही एक खतरा है। इसके परिणामस्वरूप हमारे देश के पश्चिमी घाट के जीव-जंतुओं की अनेक प्रजातियां तेजी से लुप्त हो रही हैं। एक और बात बड़े खतरे का अहसास कराती है कि एक दशक में विलुप्त प्रजातियों की संख्या पिछले एक हजार वर्ष के दौरान विलुप्त प्रजातियों की संख्या के बराबर है।

जलवायु में तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन से देश की 50 प्रतिशत जैव विविधता पर संकट है। अगर तापमान से 1.5 से 2.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है तो 25 प्रतिशत प्रजातियां पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी।

जैव विविधता जलवायु और वर्षा का कारक है जिससे पृथ्वी की सतह पर शक्ति बढ़ती है और भू-गर्भ का जलस्तर बना रहता है। खाद्य पदार्थों का सत्तर फीसद हिस्सा मधुमक्खियों व तितलियों तथा तीस फीसद चिड़ियों के परागमन से तैयार होता है। इसलिए सृष्टि में सभी जीव-जंतुओं की अपनी महत्ता

है। पृथ्वी सिर्फ छह अरब लोगों का ही घर नहीं बल्कि 28 अरब जीव-जंतुओं की भी दुनिया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जैव विविधता का मानव जीवन के अस्तित्व में अहम योगदान है।

विकास और अर्थ

जैव विविधता एक निओलोजिज्म (neologism) और सूटकेस शब्द है। (portmanteau word) से, जीव विज्ञान और विविधता विज्ञान डिवीजन के प्रकृति संरक्षण (The Nature Conservancy) एक 1975 के अध्ययन में इस शब्द प्राकृतिक विविधता का उपयोग किया है, संरक्षण प्राकृतिक विविधता की शब्द जैव विविधता पहले भी इस्तेमाल किया गया था कि जैसे संरक्षण के वैज्ञानिकों द्वारा रॉबर्ट ई. जेनकींस और थॉमस लोवेजोय (Thomas Lovejoy) शब्द जैव विविधता स्वयं विंग द्वारा त्वेमद में गढ़ा गया है मई 1985, जबकि राष्ट्रीय फोरम जैव विविधता के बारे में राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद (National Research Council)(NRC) जो 1986 में आयोजित किया जाना था द्वारा आयोजित की योजना बना है और सबसे पहले 1988 में एक प्रकाशन में जब कीटविज्ञानी E.O. विल्सन (E. O. Wilson) है कि मंच की कार्यवाही (proceedings) रूप में इसका इस्तेमाल किया दिखाई दिया, शब्द जैव विविधता और अधिक प्रभावी संचार की तुलना के सन्दर्भ में समझा गया था जैविक विविधता।

1986 के बाद से इपवसवहपेजे के बीच व्यापक उपयोग प्राप्त कर ली है शर्तें और अवधारणा, पर्यावरणवादियों, राजनीतिक नेताओं और नागरिकों का संबंध दुनिया भर में यह आमतौर पर प्राकृतिक वातावरण और प्रकृति संरक्षण के लिए एक चिंता करने के लिए समानता के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रयोग चिंता के विस्तार के ऊपर के साथ ही संयोगवश है विलुप्त होने 20 वीं शताब्दी के अंतिम दशक में मनाया।

शब्द प्राकृतिक विरासत पूर्व तिथियाँ जैवविविधता हालांकि यह एक कम अवधि के वैज्ञानिक और अधिकांश आसानी से कुछ मायनों में ज्यादा श्रोताओं संरक्षण में रुचि द्वारा comprehended है। प्राकृतिक धरोहर जब इस्तेमाल किया गया था जिमी कार्टर इस जॉर्जिया विरासत ट्रस्ट, जबकि वह जॉर्जिया के गवर्नर थाय कार्टर का भरोसा दोनों और प्राकृतिक के साथ पेश की स्थापना सांस्कृतिक विरासत (cultural heritage) ऐसा लगता है कि कार्टर ऊपर से इस शब्द का चुनाव प्रकट होगा लन्दों जॉन्सन है, जो कांग्रेस के लिए एक संदेश में 1966 में इसका इस्तेमाल किया। प्राकृतिक विरासत के विज्ञान डिवीजन के द्वारा उठाया गया था प्रकृति संरक्षण (The Nature Conservancy) जब, जेनकींस के तहत, यह 1974 में शुरू की राज्य प्राकृतिक विरासत कार्यक्रम के नेटवर्क जब इस नेटवर्क के बाहर बढ़ा दी गई संयुक्त राज्य अमरीका, शब्द संरक्षण डाटा केन्द्र गिलमो मान द्वारा सुझाव दिया गया था

और आया पसंदीदा किया जाना है।

परिभाषाएँ

सबसे सीधा परिभाषा जीवन की विभिन्नता जैविक संगठन के सभी स्तरों पर है। एक दूसरी परिभाषा है कि जैव विविधता अवयव अलग पारिस्थितिकी प्रणालियों में वर्तमान के बीच रिश्तेदार विविधता का एक उपाय है बाँधे रखता है। इस परिभाषा में विविधता और पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच तुलनात्मक विविधता एक प्रजाति के भीतर विविधता और प्रजातियों के बीच में शामिल हैं।

कि प्रायः भवसवहपेजे द्वारा प्रयोग किया जाता है एक तीसरा परिभाषा जीन, प्रजातियों की घमण्डता है और एक क्षेत्र की पारिस्थितिकी प्रणालियों इस परिभाषा का एक लाभ यह है कि यह सबसे परिस्थितियों का वर्णन करने के लिए और जिस पर जैव विविधता की पहचान की गई है पारम्परिक तीन स्तरों के एक एकीकृत दृष्टिकोण वर्तमान लगता है

आनुवंशिक विविधता (genetic diversity) – विविधता का जीन (हमदम) एक प्रजाति के भीतर वहाँ की आबादी है और एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच में एक आनुवंशिक परिवर्तनशीलता है। (यह भी देखें जनसंख्या आनुवंशिकी (population genetics))

प्रजाति विविधता (species diversity) – विविधता के बीच प्रजाति (species) एक पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता होत्सपोत (Biodiversity hotspot) प्रजाति विविधता की उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

पारिस्थितिकी तंत्र विविधता (ecosystem diversity) संगठन के एक उच्च स्तर पर – विविधता को पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) एक दी इकाई क्षेत्र में आवास की विविधता पृथ्वी पर पारिस्थितिकी प्रणालियों की विविधता के साथ क्या करने के लिए।

1992 के संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी शिखर सम्मेलन (Earth Summit) रियो डी जनेरियो में इस परिवर्तनशीलता सहित सभी सूत्रों का कहना है, से अवयव के बीच में रहने वाले के रूप में, शून्य बातों के अर्थ, समुद्री, स्थलीय तथा अन्य जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों और वे हिस्सा हैं पारिस्थितिकी परिसरा जिनमें से जैव (terrestrial) विविधता परिभाषित (marine) रू इस, प्रजातियों के भीतर विविधता शामिल हैं प्रजातियों और पारिस्थितिकी (aquatic ecosystems) प्रणालियों के बीच यह वास्तव में होता है, जैव विविधता का एक कानूनी रूप से स्वीकार किए जाते हैं परिभाषा करने के लिए सबसे नजदीक का काम है, क्योंकि इसे परिभाषा संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाई है ख्वकन्वेशन जैव विविधता पर Use Suggestion|सम्मेलन जैव विविधता पर, (Convention on Biological Diversity).

अगर इस जीन की मूलभूत इकाई है प्राकृतिक चयन (natural selection), EO विल्सन, असली जैव विविधता है आनुवंशिक विविधता के अनुसार के लिए हमदमजपबपेज (हमदमजपबपेज), जैव विविध

ता जीनों की विविधता और है जीव (organism) एसवे अध्ययन म्यूटेशनों, जीन बाजारों जैसे और यह है कि डीएनए के स्तर पर होती है और विकास उत्पन्न जीनोम डायनामिक्स प्रक्रियाओं को उत्पन्न करते हैं

माप

जैव विविधता एक व्यापक अवधारणा है, तो उद्देश्य के उपायों का एक विभिन्न प्रकार ऑर्डर करने के लिए सृजन किया गया है अनुभवजन्य (empirical)सल उपाय जैव विविधता.जैव विविधता का प्रत्येक माप के डेटा का एक विशेष उपयोग से संबंधित है।

व्यावहारिक conservationist, इस उपाय यह है कि मोटे तौर पर स्थानीय रूप से प्रभावित लोगों के बीच साझा किया जाता है एक मूल्य मात्रा ठहराना चाहिए, दूसरों के लिए, एक और अधिक आर्थिक सफाई परिभाषा की अनुमति चाहिए जारी रखा संभावनाओं के दोनों अनुकूलन और लोगों द्वारा भविष्य के उपयोग के लिए, यह सुनिश्चित करने का वादा कर पर्यावरण संधारणीयता (sustainability).

एक परिणाम के रूप में, biologists है कि इस उपाय जीन की विविधता के साथ जुड़े होने की संभावना है बहस.क्योंकि यह हमेशा हो जो जीन अधिक साबित करने के लिए, सबसे अच्छा विकल्प के लिए फायदेमंद संभावना है कहा नहीं कर सकते संरक्षण (बवदेमतअंजपवद) की जड़ता को आश्वस्त करने के लिए है मुमकिन के रूप में कई जीनों के रूप में.के रूप में यह प्रतिबंध लगा दिया ecologists के लिए, यह बाद दृष्टिकोण कभी कभी भी प्रतिबंधक, माना जाता है पारिस्थितिक उत्तराधिकार (ecological succession).

जैव विविधता आमतौर पर एक भौगोलिक क्षेत्र का वर्गीकरण समृद्धि के रूप में, एक अस्थायी पैमाने पर करने के लिए कुछ सन्दर्भ के साथ साजिश रची है। क्वित्ताकर, तीन आम मेट्रिक्स प्रजातियों को मापने के लिए स्तर पर जैव विविधता, ध्यान करने के लिए इस्तेमाल किया मदबबउचैपदह वर्णित प्रजातियों समृद्धि या प्रजातियों मअमददमे

प्रजातियों समृद्धि (Species richness) – कम से कम सूचकांकों उपलब्ध है

सिम्पसन सूचकांक (Simpson inde•))

शान्नों सूचकांक (Shannon inde•))

वहाँ पर तीन अन्य सूचकांकों है जो की एकोलोगिस्ट्स द्वारा उपयोग किया जाता है

अल्फा विविधता (Alpha diversity) विविधता के लिए एक विशेष क्षेत्र, समुदाय या पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर है और सन्दर्भित ने पारिस्थितिकी तंत्र (आमतौर पर प्रजातियों के भीतर) की संख्या की गणना के द्वारा मापा जाता है।

बीटा विविधता (Beta diversity) पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच प्रजाति विविधता है। इस जं की कि हो संख्या की तुलना शामिल है प्रत्येक पारिस्थितिकी प्रणालियों के लिए अद्वितीय (unique to each of the ecosystems).

गामा विविधता (Gamma diversity) विभिन्न पारिस्थितिकी प्रणालियों के लिए समग्र विविधता का एक उपाय का एक क्षेत्र भीतर है।

वितरण

चयन पूर्वाग्रह (Selection bias) जैव विविधता के आधुनिक अनुमान कमकमअपस करने के लिए जारी है। 1768 में गिल्बर्ट व्हाइट succinctly की मनाया अपना सेल्बोर्ने, हैम्पशायर (Selborne) Hampshire) सभी स्वभाव ऐसा है, तो भर गया है कि कि जिला जो सबसे की जांच की है सबसे ज्यादा विविधता पैदा करती है।

फिर भी, जैव विविधता के बराबर पृथ्वी पर वितरित नहीं है। यह लगातार इस में अमीर है उष्णकटिबंधीय (जलबचपवे) और अन्य स्थानीय क्षेत्रों में इस तरह के रूप में कैलिफोर्निया Floristic प्रांत (California Floristic Province) एक दृष्टिकोण ध्रुवीय क्षेत्रों एक जैसा कि आम तौर पर कम प्रजातियों ढूँढता है। वनस्पतियों और पशुवर्ग विविधता पर निर्भर करता है जलवायु (climate), ऊँचाई, मिट्टी (soil) और अन्य प्रजातियों की उपस्थिति। पृथ्वी की प्रजातियों में से 2006 औपचारिक रूप से बड़ी संख्या के रूप में वर्गीकृत किया गया वर्ष में दुर्लभ (rare) या अब खतरे में (मदकंदहमतमक) या धमकी दी प्रजातियों (threatened species)। इसके अलावा, कई वैज्ञानिकों है कि वहाँ लाखों अधिक प्रजातियों वास्तव में, जो अभी तक औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं किया गया है।

एक जैव विविधता (biodiversity hotspot) एक उच्च स्तर के साथ एक क्षेत्र है स्थानिक प्रजाति। इन जैव विविधता होत्स्पोट्स पहले डॉ० द्वारा से पहचान की गई थी नॉर्मन मायर्स दो लेख वैज्ञानिक पत्रिका में इस पर्यावरणविद् घने मानव निवास होत्स्पोट्स के अस पास होते हैं सबसे जायदा होत्स्पोट्स उष्णकटिबंधीय में स्थित है और उनमें से ज्यादातर जंगल हैं।

ब्राजील में अटलांटिक वन (Atlantic Forest) जैव विविधता का एक होत्स्पोट माना जाता है और लगभग 20000 संयंत्र प्रजातियों, 1350 रीढ़ है और कीड़े के लाखों लोगों, जिनमें से लगभग आधे कहीं और दुनिया में पाए जाते हैं। के बाद से द्वीप मुख्य भूमि अफ्रीका 65 करोड़ साल पहले से अलग अद्वितीय मेडागास्कर शुष्क पर्णपाती वन और तराई वर्षावन सहित मेडागास्कर के द्वीप है, वह जाति और पारिस्थितिकी प्रणालियों के सबसे स्वतंत्र रूप से विकसित किया है अद्वितीय प्रजातियों का निर्माण विभिन्न प्रजातियों एन्डेमिस्म (endemism) और जैव विविधता का एक बहुत ही उच्च अनुपात के अधि

कारि उन अफ्रीका के अन्य भागों में से.

उच्च जैव विविधता के कई क्षेत्रों और साथ ही उच्च (endemism) से पैदा बहुत विशेष आवास (habitat) जो असामान्य रूपांतर तंत्र की आवश्यकता होती है। उदाहरण के पीट का के लिए दलदल (इवह) उत्तरी की यूरोप और सअंत ऐसे क्षेत्रों के रूप में स्टोरा अल्वारेट (Stora Alvaret) नहीं ओलंद (व्संदक), स्वीडन मेजबान पौधों और जानवरों के एक बड़े विविधता, जिनमें से कई कहीं और नहीं मिला रहे हैं।

एवोलुशन

इस के दौरान स्पष्ट समुद्री जीवाश्म विविधता फनेरोजोइक

जैव विविधता पर पाया पृथ्वी आज 4 अरब साल का का नतीजा है (evolution). इस जीवन का मूल (origin of life) निश्चित रूप से विज्ञान द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, लेकिन कुछ सबूत है कि जीवन पहले से ही अच्छी तरह से किया गया है मई-स्थापित कुछ दस करोड़ साल के बाद का सुझाव पृथ्वी का गठन (formation of the Earth) लगभग 600 करोड़ साल पहले तक, सभी तरह के जीवन की शामिल हैं जीवाणु और इसी तरह के एक अवयव सल्लेद

इस के दौरान जैव विविधता का इतिहास फनेरोजोइक (पिछले 540 मिलियन वर्ष), इस के दौरान तेजी से विकास के साथ, शुरु कैम्ब्रियन विस्फोट-एक अवधि जो लगभग हर के दौरान जाति का मुल्टिसल्लुलर जीव पहले दिखाई दिया. अगले 400 मिलियन वर्ष या इतने में, वैश्विक विविधता है, लेकिन छोटे समग्र रुझान दिखाया आवधिक, विविधता का भारी नुकसान के रूप में वर्गीकृत द्वारा चिह्नित किया गया।

इस स्पष्ट जैव विविधता का में दिखाया गया जीवाश्म रिकॉर्ड है कि पिछले कुछ लाख वर्षों की सबसे बड़ी में जैव विविधता की अवधि में शामिल हैं का सुझाव है पृथ्वी के इतिहास लेकिन, नहीं सभी वैज्ञानिकों, इस दृष्टिकोण का समर्थन के बाद से वहाँ कैसे पुरजोर जीवाश्म रिकॉर्ड को ज्यादा उपलब्धता और संरक्षण के द्वारा पक्षपाती है करने के लिए के रूप में काफी अनिश्चितता है हाल ही में भूगर्भिक वर्गों. बहुत जैव विविधता 300 करोड़ साल पहले से अलग नहीं कुछ है कि कलात्मक नमूना के लिए सही बहस, आधुनिक जैव विविधता है। वर्तमान वैश्विक उंबतवेबवचपब प्रजातियों की विविधता का अनुमान 2 लाख 100 करोड़ प्रजातियों से, कहीं के पास 13-14 लाख के एक सबसे अच्छा अनुमान के साथ बदलती हैं, उन के विशाल बहुमत अश्रीपोद (तजीतवचवक) एसख10,

सबसे बिओलोगिस्ट्स लेकिन बात से सहमत है कि इस अवधि के बाद से मानव के उद्भव एक नया सामूहिक विलुप्त होने, का हिस्सा है होलोसने विलुप्त होने घटना (श्वसवबमदम मजपदबजपवद

मअमदज), मुख्य रूप से प्रभाव मनुष्यों के कारण पर्यावरण पर हो रही है।-ऐसा लगता है कि वह विलुप्त होने के वर्तमान दर 100 वर्षों के भीतर ग्रह पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रजातियों को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है तर्क दिया गया है।ख1,

नई प्रजातियों को नियमित रूप से औसत (पर 5-10000 नई प्रजातियों-प्रत्येक वर्ष के बीच की खोज कर रहे हैं, उनमें से ज्यादातर कीट (पदेमबज)) और कई हैं, यद्यपि की खोज की, अभी तक वर्गीकृत नहीं हैं (अनुमान है कि लगभग 90: सभी का अधीपोद (तजीतवचवक) अभी तक) में वर्गीकृत नहीं हैं।ख0, इस स्थलीय विविधता के अधिकांश पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन (जतवचपबंस वितमेज) ओ में

लाभ

वहाँ एक भीड़ हैं अन्धोपोसन्त्रिक (anthropocentric) कृषि, विज्ञान और चिकित्सा, औद्योगिक सामग्री, पारिस्थितिक सेवाओं, फुरसत में है और, सांस्कृतिक सौंदर्य और बौद्धिक मूल्य में के क्षेत्रों में जैव विविधता के लाभ।जैव विविधता भी एक करने के लिए केंद्रीय है एकोसन्त्रिक (मबवबमदजतपब) दर्शन. यह समकालीन दर्शकों के लिए जैव विविधता के संरक्षण में विश्वास करने के कारणों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। मैं इसे हम जैव विविधता से और हम जो पिछले 600 वर्षों में स्थान ले लिया है प्रजातियां विलुप्त होने का एक परिणाम के रूप में है कि खोने की बातें क्या मिल को देखने के लिए है कारणों की पहचान करने के लिए एक रास्ता क्यों हम विश्वास करते हैं। जन विलुप्त होने मानव गतिविधि के प्रत्यक्ष परिणाम है और जो अनेक आधुनिक दिन विचारकों की धारणा है नहीं प्राकृतिक घटनाएं में से एक है। वहाँ कि पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक प्रक्रियाओं से प्राप्त होते हैं अनेक लाभ हैं। कुछ पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं कि लाभ समाज वायु गुणवत्ता, जलवायु हैं (दोनों वैश्विक बब2 ऋणी की संपत्ति पर अधिकार है और क्षेत्रीय और स्थानीय), जल शुद्धीकरण, रोग नियंत्रण, जैविक कीट नियंत्रण, परागण और कटाव की रोकथाम.उन गैर सामग्री लाभ आया है कि जो और सौंदर्य मूल्यों आध्यात्मिक हैं पारिस्थितिकी प्रणालियों से प्राप्त कर रहे हैं के साथ, ज्ञान प्रणालियों और शिक्षा के मूल्य कि आज हम प्राप्त करते हैं। लेकिन, जनता को संकट की जैव विविधता बनाए रखना में अनजान बनी हुई है। जैव विविधता के जीवन को महत्व में एक देखो लेता है और पृथ्वी पर जीवन को वर्तमान खतरे की स्पष्ट समझ के साथ आधुनिक दर्शकों प्रदान करता है।

कृषि

कुछ खाना अन और अन्य आर्थिक फसलों है, पालतू प्रजाति के जंगली किस्मों के लिए पिछले (पालतू से बेहतर किस्म बनाने के लिए) प्रजातियों reintroduced किया जा सकता है। आर्थिक

प्रभाव है, आलू के रूप में सामान्य रूप में भी फसलों के लिए (जो सिर्फ एक ही किस्म के माध्यम से, नरल था वापस पदबं से लाया), एक बहुत अधिक इन प्रजातियों से आ सकते हैं विशाल है। जंगली आलू मौसम बदलाव की वजह से उनको बहुत बुक्सन होगा सलाहकार समूह अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर (CGIAR) द्वारा एक रिपोर्ट यह कह ता है की खेती में काफी गिरावट हुई है

चावल जो की मनुष्य द्वारा हजारों सालों तक सुधार गया है वह इस निति से और भी सुधार जा सकता है जिसकी वजह से उसकी पोषण बचे जा सके

फसल विविधता भी इस प्रणाली में प्रमुख है जब और बाकि फसल में कीड़े लगने का डर होता है 1846 में जो एक करोड़ लोगों को और दूसरा लाख के प्रवास की मौतों का एक प्रमुख कारन था यह इस वजह से हुआ क्यूँ की दो तरीके के आलू उगाये गए थे जो की दोनों ही खतरे में थे

जब चावल घास स्टंट वायरस (rice grassy stunt virus) 1970 के दशक में भारत के लिए इंडोनेशिया से मारा चावल के खेतों में जब 6273 किस्म पर परीक्षण किया गया। केवल एक सौभाग्य, इच्छित विशेषता के साथ एक अपेक्षाकृत कमजोर भारतीय विविधता, विज्ञान के लिए 1966 के बाद से ही जाने जाते हैं, यह अन्य किस्मों के साथ और द्विब्रदिसेद किया गया था अब व्यापक रूप से वृद्धि हुई है

1970 में, कॉफी रतुआ श्रीलंका, ब्राजील और मध्य अमेरिका में कॉफी बागान पर हमला किया। एक प्रतिरोधी किस्म इथियोपिया में पाया गया था, मोनोचुलतुरे (Monoculture), जैव विविधता का अभाव है, सहित इतिहास में कई कृषि आपदाओं, के लिए एक योगदान कारक था आयरिश आलू अकाल (Irish Potato Famine), स्वर्गीय 1800 में यूरोपीय वाइन उद्योग पतन और अमेरिका के दक्षिणी मर्क्यु के पत्तों की हानि पहुंचाना उच्च जैव विविधता भी रोगजनकों के रूप में कुछ बीमारियों के प्रसार, को अलग अलग प्रजातियों को संक्रमित करने के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता नियंत्रित करता है।

जैव विविधता मनुष्यों के लिए भोजन प्रदान करता है। यद्यपि हमारे भोजन की आपूर्ति 80 प्रतिशत संयंत्रों का सिर्फ 20 प्रकार से आती है, मानव पौधों और जानवरों के कम से कम 40000 प्रजातियों में एक दिन में उपयोग करते हैं दुनिया भर के कई लोग उनके भोजन, आवास और कपड़ों के लिए इन प्रजातियों पर निर्भर करते हैं। वहाँ मानव उपभोग के खाद्य उत्पादों की रेंज बढ़ाने के लिए अप्रयुक्त क्षमता उपयुक्त, यह है कि उच्च वर्तमान विलुप्त होने की दर को रोका जा सकता है।

विज्ञान और चिकित्सा

दवाओं का एक महत्वपूर्ण अनुपात, प्रत्यक्ष या परोक्ष, जैविक स्रोतों से व्युत्पन्न होता है, इन दवाओं

वर्तमान में एक प्रयोगशाला स्थापित करने में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है ज्यादातर मामलों में 40 : से अधिक दवायियन जो की अमरीका में जो बनाई जाते है वह पोधे जानवरों वत .सूक्ष्मजीवों से बनाये जाते है इसके अलावा, पौधों की कुल विविधता का केवल एक छोटा सा अनुपात बिलकुल नई औषधियों के संभावित स्रोतों के लिए जांच के लिये लाया गया कई दवाओं से भी प्राप्त कर रहे हैं

क्षेत्र के माध्यम से बायोनिक्स (इपवदपबे), काफी तकनीकी उन्नति जो एक समृद्ध जैव विविधता के बिना नहीं होती हुई है।

जैवविविधता का स्वर्ग

आर्द्रभूमियाँ जैव विविधता संरक्षण के लिये महत्त्वपूर्ण हैं। आर्द्रभूमियाँ बहुत सारे जीवों का ठिकाना हैं। हमारे देश की पारिस्थितिकी सुरक्षा में इन आर्द्रभूमियों की अहम भूमिका है। खाद्यान्नों की कमी और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों के बीच हमें आर्द्रभूमियों को बचाने की जरूरत है ताकि वे अपनी पारिस्थितिकी भूमिका निभा सकें। आर्द्रभूमियाँ जैवविविधता को सुरक्षित रखती हैं।

आर्द्रभूमियाँ शीतकालीन पक्षियों और विभिन्न जीव-जन्तुओं का आश्रय स्थल होती हैं। विभिन्न प्रकार की मछलियाँ और जन्तुओं के प्रजनन के लिये भी ये उपयुक्त होती हैं। इन आर्द्रभूमियों पर विशेष मौसम में कई पक्षी आते हैं।

आर्द्रभूमियाँ प्रवासी पक्षियों की पनाहस्थली के रूप में विख्यात हैं। ऐसे क्षेत्र पट्ट शीर्ष राजहंस, पनकौआ, बायर्स वॉचार्ड, ओस्रे, इण्डियन स्किम्मर, श्याम गर्दनी बगुला, संगमरमरी टील, बंगाली फ्लोरीकॉन पक्षियों का मनपसन्द स्थल होते हैं।

पक्षियों का कलरव और रंग रूप, हमेशा से ही पक्षी निहारकों को इन आर्द्रभूमियों की ओर आकर्षित करते रहे हैं। ये आर्द्रभूमियाँ जैव विविधता के मामले में बहुत धनी होती हैं। भरतपुर स्थित केवलादेव पक्षी विहार, कई प्रवासी पक्षियों की पसन्दीदा स्थल है।

आर्थिक महत्त्व

आर्द्रभूमियाँ अपट्टे आस-पास बसी मानव बस्तियों के लिये जलावन लकड़ी, फल, वनस्पतियाँ, पौष्टिक चारा और जड़ी-बूटियों की स्रोत होती हैं।

कमल, जो कि दुनिया के कुछ विशेष सुन्दर फूल होने के साथ ही भारत का राष्ट्रीय फूलों है, आर्द्रभूमियों में उगता है। आर्द्रभूमियाँ अपने आस-पास अनेक ऐसे वनस्पतियों और जीवों को आश्रय प्रदान करती हैं जो आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। आर्द्रभूमि विविधता से परिपूर्ण पारिस्थिति तंत्र का द्योतक है।

अनोखी आर्द्रभूमि-लोकटक झील

मणिपुर की लोकटक झील देशी और विदेशी सैलानियों के लिये आकर्षण का केन्द्र है। इस झील को दुनिया भर में अपनी तरह का अकेला 'तैरता वन्य प्राणी विहार' का दर्जा हासिल है। लेकिन प्रदूषण के चलते अब इसमें हानिकारक खरपतवार उग रहे हैं।

प्रकृति अपने विविध रूपों में हमारे पृथ्वी ग्रह को सुन्दर बनाए हुए है। आर्द्रभूमियाँ प्रकृति का ऐसा ही अनोखा और अनुपम रूप है। असल में आर्द्रभूमि नमी या दलदली क्षेत्र होते हैं जो अपनी अनोखी पारिस्थितिकी के कारण महत्त्वपूर्ण हैं। आर्द्रभूमियों के अन्तर्गत झीलें, तालाब, दलदली क्षेत्र, हौज, कुण्ड, पोखर एवं तटीय क्षेत्रों पर स्थित मुहाने, लगून, खाड़ी, ज्वारीय क्षेत्र, प्रवाल क्षेत्र, मैंग्रोव वन आदि क्षेत्र शामिल होते हैं। गुजरात का नलसरोहर, उड़ीसा की चिल्का झील और भितरकनिका मैंग्रोव क्षेत्र, राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दिल्ली का ओखला पक्षी अभयारण्य आदि आर्द्रभूमियों के कुछ उदाहरण हैं। पारिस्थितिकीय दृष्टि से यह झील अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस झील में एक तैरता पौधा उगता है जिसे 'बुल लामजाओ खरपतवार' या 'फुमड़ी' कहते हैं। यह पौधा केवल यहीं उगता है और कहीं नहीं। इस पौधे पर एक हिरण की प्रजाति पलती है जिसे पिगभी हिरण (संगाई) कहा जाता है। फुमड़ी पौधे की संख्या कम हो जाने से इस हिरण की संख्या भी कम होने लगी है। इनकी संख्या 100 से कम हो गई है।

आर्द्रभूमियों पर मँडराते खतरे

वर्तमान में भारत की बहुत सी आर्द्रभूमियों पर संकट के बादल मँडरा रहे हैं। आर्द्रभूमियाँ प्रदूषण के कारण संकट में हैं। तेजी से बढ़ते कंक्रीट के जंगल, उद्योग, शहरीकरण के लिये जलग्रहण क्षेत्र से छेड़खानी, हजारों टन रेत का जमाव और कृषि रसायनों के जहरीले पानी का आ मिलना आर्द्रभूमियों की बर्बादी का कारण है।

भारत में ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जहाँ आर्द्रभूमियों की बर्बादी के साथ ही जंगली जानवरों या पौधों पर संकट मँडरा रहा है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में 'दलदली हिरण' पाया जाता है। यह हिरण भी कम हो रहा है।

इस प्रजाति के हिरणों की संख्या लगभग एक हजार बची है। इसी प्रकार तराई वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली फिशिंग कैट यानी मच्छीमार बिल्ली पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इसके साथ ही गुजरात के कच्छ क्षेत्र में जंगली गधा भी खतरे में है।

असम के काजीरंगा और मानव दलदलीय क्षेत्रों से जुड़ा एक सींग वाला भारतीय गैंडा भी प्रायः विलुप्त प्राणियों की श्रेणी में शामिल है। इसी प्रकार ओटर, गैजेटिक डॉल्फिन, डुरोंग, एशियाई जलीय भैंस जैसे आर्द्रभूमियों से जुड़े अनेक जीव खतरे में हैं।

रेंगने वाले जीव जैसे समुद्री कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ, जैतूनी रिडली और जलीय मॉनीटर पर भी आर्द्रभूमियों के प्रदूषित होने के कारण संकट में डरा रहा है। जीवों के अतिरिक्त कुछ वनस्पतियाँ भी आर्द्रभूमि के संकट से प्रभावित हो रही हैं।

आर्द्रभूमियों के संरक्षण के प्रयास

कई सारी वनस्पतियों, सरीसृपों, पक्षियों और जनजातियों आदि की निवास स्थली यह आर्द्रभूमियों के बढ़ते प्रदूषण, बिगड़ती जलवायु, विकास के दुष्परिणामों आदि के कारण अपना स्वरूप खोती जा रही है। भारत में आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिये पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 1987 से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी तक 15 राज्यों में 27 आर्द्रभूमि क्षेत्र चिन्हित किये गए हैं। इनके अन्तर्गत पंजाब में कंजली और हरिके, उड़ीसा में चिल्का, मणिपुर में लोकटक, चंडीगढ़ में सुखना और हिमाचल में रेणुका क्षेत्र हैं। इन जगहों में संरक्षण और उनके बारे में जागरुकता लाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

इसके अलावा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सुन्दरवन, मनास और काजीरंगा को 'अन्तरराष्ट्रीय विरासत' का दर्जा दिया गया है। इन क्षेत्रों में देश-विदेश के मेहमान पक्षी आते हैं। इसलिये इनको बचाने के लिये अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं।

आर्द्रभूमियाँ व्यापक स्तर पर आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक आधार रही हैं। इसीलिये 2 फरवरी, 1971 को 70 राष्ट्रों ने आर्द्रभूमियों पर एक सम्मेलन ईरान के रामसर शहर में बुलाया था। इसी दिन आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिये वहाँ एक अन्तरराष्ट्रीय सन्धि हुई थी जिसे रामसर सन्धि भी कहा जाता है। अब इस सन्धि पर 163 देशों ने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

यह सन्धि विश्व के दुर्लभ व महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में चिन्हित करने के साथ ही अनेक अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिये जागरुकता का प्रसार करती है। इसीलिये 1997 से प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है जिसके अन्तर्गत व्यापक रूप से आम लोगों को आर्द्रभूमियों के महत्व और लाभों के प्रति जागरुक करना है।

वर्ष 2013 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने जल सहयोग का अन्तरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। इसलिये 2 फरवरी, 2012 को मनाए जाने वाले अन्तरराष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस का विषय भी आर्द्रभूमि और जल प्रबन्धन से सम्बन्धित रखा गया।

अभी तक विश्व भर की 2062 आर्द्रभूमियों को रामसर क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया है जो

करीब 19,72,58,541 हेक्टेयर में फैली हुई हैं। इन क्षेत्रों में से 35 प्रतिशत क्षेत्र पर्यटन सम्भावित क्षेत्र हैं। इनमें से 45 आर्द्रभूमियों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में भारत का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है।

भारत ने इस समझौते पर 1981 में हस्ताक्षर किये और यहाँ के केवल 26 आर्द्रभूमियों को रामसर संरक्षित आर्द्रभूमियों का दर्जा हासिल है। जो 6,89,131 हेक्टेयर में फैली हैं।

उड़ीसा की चिल्का झील और राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय पार्क रामसर के तहत संरक्षित होने वाले पहले दो दलदल थे। भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट भीमबन्द-कोल वेटलैंड (1512.5 वर्ग कि.मी.) केरल में है।

वैसे हमारे देश में भी आर्द्रभूमि पर्यटन पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके तहत गुजरात राज्य में पिछले तीन सालों से 'ग्लोबल बर्ड वॉचर्स कांफ्रेंस' की जा रही है। ऐसे आयोजनों का उद्देश्य यही होता है कि आर्द्रभूमियों को बढ़ते प्रदूषण, बदलती जलवायु और अनियंत्रित विकास से उत्पन्न खतरों आदि से बचाया जा सके ताकि इन क्षेत्रों में हमेशा जीवन के विविध रूप मुस्कुराते रहें।

सन्दर्भ -

एडवर्ड ओ विल्सन, संपादक, फ्रांसिस एम. पीटर, सहयोगी संपादक, जैव विविधता, राष्ट्रीय अकादमी प्रेस, मार्च 1988 ISBN 0-309-03783-2; ISBN 0-309-03739-5 (pbk.), ऑनलाइन संस्करण

विश्व जैव विविधता का आकलन. यूएनईपी, 1995, Anne & 6, शब्दकोष. ISBN 0-521-56481-6, स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता द्वारा जैव विविधता, शब्दकोष शब्द छद्म से संबंधित, बेलजियम (Belgian) समाशोधन-सभा प्रणाली, पुनः प्राप्त 2006-04-26 (2006-04-26).

केविन जे गार्स्टों जॉन मैं स्पिसर .2004.\ जैव विविधता एक परिचय, ब्लैकवेल प्रकाशन. 2 एड., ISBN 1-4051-1857-1 (pbk.)

व्हिक्ताकर, क्रा, विकास और प्रजातियों के माप विविधता, त्सों, 21, 213-251 (1972)

सफेद, सेल्बोरने के प्राकृतिक इतिहास, पत्र 8 अक्टूबर 1768.

मायर्स एन (1988), धमकी दी biotas: हॉट स्पॉट उष्णकटिबंधीय जंगलों में, पर्यावरणविद्, 8, 187-208.

मायर्स एन (1990); इस जैव विविधता चुनौती-विस्तारित गर्म स्पॉट विश्लेषण, पर्यावरणविद्, 10, 243-256.

जे अलरॉय, करोड़ एट अल.2001.फनेरोजोनिक समुद्री विविधीकरण के अनुमानों पर मानकीकरण नमूने का प्रभाव.कार्यवाही में राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, संयुक्त राज्य अमरीका 98 के 6261-6266

पर्यावरण संरक्षण और भारतीय संस्कृति

डॉ. एस.एस. यादव

सहसयक प्राध्यापक समाजशास्त्र विभाग
शास. महाविद्यालय बुधनी म.प्र.

भारतीय संस्कृति में पर्यावरण के संरक्षण को बहुत महत्व दिया गया है। यहां मानव जीवन को हमेशा मूर्त या अमूर्त रूप में पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्र, नदी, वृक्ष एवं पशु-पक्षी आदि के साहचर्य में ही देखा गया है। पर्यावरण शब्द का अर्थ है हमारे चारों ओर का आवरण। पर्यावरण संरक्षण का तात्पर्य है कि हम अपने चारों ओर के आवरण को संरक्षित करें तथा उसे अनुकूल बनाएं। पर्यावरण और प्राणी एक-दूसरे पर आश्रित हैं। यही कारण है कि भारतीय चिंतन में पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा उतनी ही प्राचीन है, जितना यहाँ मानव जाति का ज्ञात इतिहास है। भारतीय संस्कृति का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि यहां पर्यावरण संरक्षण का भाव अति पुराकाल में भी मौजूद था, पर उसका स्वरूप भिन्न था। उस काल में कोई राष्ट्रीय वन नीति या पर्यावरण पर काम करनेवाली संस्थाएं नहीं थीं। पर्यावरण का संरक्षण हमारे नियमित क्रिया-कलापों से ही जुड़ा हुआ था। इसी वजह से वेदों से लेकर कालिदास, दाण्डी, पंत, प्रसाद आदि तक सभी के काव्य में इसका व्यापक वर्णन किया गया है। भारतीय दर्शन यह मानता है कि इस देह की रचना पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटकों- पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश से ही हुई है। समुद्र मंथन से वृक्ष जाति के प्रतिनिधि के रूप में कल्पवृक्ष का निकलना, देवताओं द्वारा उसे अपने संरक्षण में लेना, इसी तरह कामधेनु और ऐरावत हाथी का संरक्षण इसके उदाहरण हैं। कृष्ण की गोवर्धन पर्वत की पूजा की शुरुआत का लौकिक पक्ष यही है कि जन सामान्य मिट्टी, पर्वत, वृक्ष एवं वनस्पति का आदर करना सीखें। श्रीकृष्ण ने स्वयं को ऋतुस्वरूप, वृक्ष स्वरूप, नदीस्वरूप एवं पर्वतस्वरूप कहकर इनके महत्व को रेखांकित किया है। भारतीय विचारधारा में जीवन का विभाजन भी प्रकृति पर ही आधारित था। चार आश्रमों में से तीन तो पूरी तरह से प्रकृति के साथ ही व्यतीत होते थे। ब्रह्माचर्य आश्रम, जो गुरु-गृह में व्यतीत होता था

और गुरुकुल सदैव वन-प्रदेश, नदी तट पर ही हुआ करते थे, जहां व्यक्ति सदैव प्रकृति से जुड़ा रहता था। वानप्रस्थ आश्रम में भी व्यक्ति वन प्रदेशों में रहकर आत्मचिंतन तथा जन कल्याण के कार्य करता था। संन्यास आश्रम में तो समग्र उत्तरदायित्वों को भावी पीढ़ी को सौंपकर निर्जन वन एवं गिरि कंदराओं में रह कर ही आत्मकल्याण करने का विधान था। जिस प्रकार राष्ट्रीय वन-नीति के अनुसार संतुलन बनाए रखने हेतु पृथ्वी का 33 प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित होना चाहिए, ठीक इसी प्रकार प्राचीन काल में जीवन का एक तिहाई भाग प्राकृतिक संरक्षण के लिए समर्पित था, जिससे कि मानव प्रकृति को भली-भांति समझकर उसका समुचित उपयोग कर सके और प्रकृति का संतुलन बना रहे। उपनिषदों में लिखा है— हे अश्वरूप धारी परमात्मा! बालू तुम्हारे उदरस्थ अर्धजीर्ण भोजन है, नदियां तुम्हारी नाडिध्यां हैं, पर्वत-पहाड़ तुम्हारे हृदयखंड हैं, समग्र वनस्पतियां, वृक्ष एवं औषधियां तुम्हारे रोम सद् श हैं। ये सभी हमारे लिए शिव बनें। हम नदी, वृक्षादि को तुम्हारे अंग स्वरूप समझकर इनका सम्मान और संरक्षण करते हैं। भारतीय परम्परा में धार्मिक कृत्यों में वृक्ष पूजा का महत्व है। पीपल को पूज्य मानकर उसे अटल सुहाग से सम्बद्ध किया गया है। भोजन में तुलसी का भोग पवित्र माना गया है, जो कई रोगों की रामबाण औषधि है। वित्त्व वृक्ष को भगवान शंकर से जोड़ा गया और ढाक, पलाश, दूर्वा एवं कुश जैसी वनस्पतियों को नवग्रह पूजा आदि धार्मिक कृत्यों से जोड़ा गया। पूजा के कलश में सप्तनदियों का जल एवं सप्तभृत्तिका का पूजन करना व्यक्ति में नदी व भूमि को पवित्र बनाए रखने की भावना का संचार करता था। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर पशुओं एवं वृक्षों का अंकन, सम्राटों द्वारा अपने राजचिन्ह के रूप में वृक्षों एवं पशुओं को स्थान देना, गुप्त सम्राटों द्वारा बाज को पूज्य मानना, मार्गों में वृक्ष लगवाना, कुएं खुदवाना, दूसरे प्रदेशों से वृक्ष मंगवाना आदि तात्कालिक प्रयास पर्यावरण प्रेम को ही प्रदर्शित करते हैं। वैदिक ऋषि प्रार्थना करता है— पृथ्वी, जल, औषधि एवं वनस्पतियां हमारे लिए शांतिप्रद हों। ये शांतिप्रद तभी हो सकते हैं जब हम इनका सभी स्तरों पर संरक्षण करें। तभी भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण की इस विराट अवधारणा की सार्थकता है, जिसकी प्रासंगिकता आज इतनी बढ़ गई है।

अपने चारों ओर के परिवेश को हमने इस कदर छोड़ा है कि बात अगर पर्यावरण की उठती है तो प्रदूषण का सवाल अपने आप ही आगे आ जाता है। हर ओर सुनी जाने वाली यह ऐसी श्वेतालदृपचीशीश है जिसमें लाशों को ढोनेवाला कोई एक विक्रम नहीं बल्कि हम सभी हैं और सही उत्तर की प्रतीक्षा में बेताल साथदृसाथ चल रहा है। बात प्रदूषण की उठे, तो लोग सांस्कृतिक या भाषायी प्रदूषण की बात भी करते हैं। सामाजिक मान्यताओं को झकझोड़ने वाली व्यवहारिक प्रदूषण के दायरों का तो कोई आकलन नहीं किंतु पर्यावरण प्रदूषण का क्षेत्र आज बढ़ता ही जा रहा है। मानव एवं सभी प्रकार के

जीवन को ढोने वाली पारिस्थितिकीवृत्त में हलचल मचानेवाली समस्या और प्रदूषण के व्यापक प्रभाव वाले क्षेत्र निम्नलिखित हैं—

- (क) विलुप्तप्राय जंतुओं का संकट
- (ख) जल प्रदूषण
- (ग) वायु प्रदूषण
- (घ) स्थल एवं मृदा प्रदूषण
- (ङ) ध्वनि प्रदूषण

जलीय, स्थलीय एवं आकाशीय क्षेत्र में निवास करनेवाले जैव तथा पादप समुदाय और निर्जीव वातावरण के बीच स्थापित परस्पर संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। समूचे पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न तत्वों के बीच अनादि काल से एक प्रकार का संतुलन स्थापित है और जब भी यह संतुलन बिगड़ा है तो विनाश की स्थिति सामने आयी है। अस्तित्व के लिए संघर्षकृसर्वोत्तम का चुनाव के सिद्धांत पर ही प्रकृति का सारा खेल टिका है। जैविक संसार में होनेवाली स्वभाविक सत्ता संघर्ष के अतिरिक्त मानव जाति ने आज अपनी आवश्यकताओं, वैज्ञानिक खोजों या मनोरंजन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र में गहरी छेड़छाड़ की है। जीवजंतुओं की कई प्रजातियां आज या तो लुप्त हो गई हैं या लुप्तप्राय हैं।

रेड बुक ऑफ वाइल्ड के अनुसार 1600 ई0 से 1990 ई0 के बीच 36 स्तनधारियों और 94 पक्षियों की प्रजातियां लुप्त हो गई हैं जबकि स्तनधारियों की 236 प्रजातियां तथा पक्षियों की 287 प्रजातियां आज लुप्त होने के कगार पर हैं। पारिस्थितिकी का आधारभूत सिद्धांत यह है कि यदि प्राणियों के 90% आवास नष्ट हो जाए तो उनमें बसनेवाली 50% जैव प्रजातियां स्वतः विलुप्त हो जाएंगी। इस सिद्धांत और उष्ण कटिबंधीय वनों के विनाश की दर के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि उष्ण कटिबंधीय वनों में निवास करनेवाली जीवों की प्रजातियां आनेवाले वर्षों में हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। स्थलीय विविधता, सक्रिय जलवायु, लंबे सागर तट तथा अनेक समुद्री द्वीपों के चलते प्रकृति ने जैव और पादप विविधता के मामले में भारतीय उपमहाद्वीप को विशेष रूप से संवारा है।

धरती के चार जैव भौगोलिक परिमंडलों में से तीन पराष्कृतटीय, अफ्रीकी और इन्डोदृहिमालयन क्षेत्र भारत में पड़ते हैं। विश्व के किसी भी राष्ट्र में दो से अधिक परिमंडलों के क्षेत्र नहीं मिलते। भारतीय भूमि क्षेत्र में निवास करनेवाली जीवजंतुओं की कुछ शानदार प्रजातियां जैसे बाघ, तेंदुआ, एशियाई सिंह, हाथी, हिम तेंदुआ, सुनहरा लंगूर, सिंह पुच्छी बंदर, गंगेय डॉलफिन, हंगुल, दलदली हिरण, जंगली गदहा, घड़ियाल, सोन चिड़िया, सफेद पंखों वाली जंगली बत्तख आदि आज संकटग्रस्त जीव जंतुओं की श्रेणी में हैं। शेर, बाघ, हाथी, मृग या कछुए जैसे वन्य जीवों के विभिन्न अंगों का अंतराष्ट्रीय

बाजारों में ऊंची कीमत गरीब देशों में अवैध कारोबार को बढ़ावा देती है। सख्त सरकारी कानूनों के अतिरिक्त वन संपदा के प्रति हमारी मानवीय चेतना की जागरूकता इस दिशा में कारगर सिद्ध हो सकती है। वनस्पति जगत के बिना प्राणी जीवन की कल्पना ही संभव नहीं। जंगली पशुदूषणियों की तो छोड़िए, आदिमानव युग से लेकर आज तक भी आदिवासी जीवन का तानाबाना वनस्पतियों के साथ जुड़ा है। ये तो बाजारू संस्कृति में जीनेवाले तथाकथित सभ्य समाज में रहनेवाले लोग हैं, जो दिनभर की अपनी दिनचर्या में पर्यावरण के लिए जहर छोड़ने के बाद शाम को किसी रेस्तरां में रखे बॉसाई के बगल में बैठकर कारखानों में हो रहे उत्पादन पर चर्चा करते हैं।

जल प्रदूषण:

जल ही जीवन है वाली कहावत और इसकी सच्चाई में अगर हम विश्वास करते हों तो जलीय पर्यावरण की पवित्रता का दायित्व भी हमारा ही है। पिछले दशकों में विश्व की जनसंख्या में हुई भारी वृद्धि, शहरी जीवन जीने के प्रति ललक तथा विकास के नाम पर जल में बहाई जानेवाली गंदगी की नालियों को साफ करने की जिम्मेदारी सरकार पर छोड़कर निश्चित हो लेते हैं। नतीजतन, समुद्री जल का बहुत बड़ा भाग और विश्व की लगभग सभी नदियां आज जीव संसार के लिए जीवन की तरलता नहीं बल्कि मौत की कठोरता लेकर बह रही है। भारत में अगर आप कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी या पटना जैसी लाखों की आबादी वाले शहर के निवासी हैं तो अब भी क्या आपका मन गंगा स्नान के लिए तरसता है? दिल्ली, आगरा या मथुरा जैसी जगहों पर अगर यमुना नदी को देख लें तो आप क्या विश्वास कर पाएंगे कि पुरानदृकाल से ही नदियों की प्रशंसा में श्लोकों की रचना करनेवाले भरतदृवंशियों ने ही पावन यमुना की ऐसी दुर्दशा की है? किसी भी जल में जीवन की संभावना होने के लिए उसमें घुले आक्सीजन की कम से कम मात्रा 5 मिलीग्राम लीटर होने चाहिए, जबकि दिल्ली में किए गए एक नमूना परीक्षण के दौरान कई जगहों पर यमुना के जल में आक्सीजन पाया ही नहीं गया वायुमंडलीय प्रदूषण या पर्ववतीय पर्यटकों द्वारा फैलाई जाने वाली गंदगी का असर यह है कि पतित पावनी गंगा या यमुना नदी का उदगम स्थल ही अत्यधिक प्रदूषित हो चुका है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के पर्यावरण वैज्ञानिक प्रोफेसर सैय्यद इकबाल हसन के बात पर विश्वास करें तो गंगोत्री ग्लेशियर के लगातार पीछे हटने से अगले 125 वर्षों में गंगा सूख सकती है। नदियों के सीमित जल को छोड़िए, यह आम मान्यता है कि अथाह जल राशि के चलते समुद्री जल को प्रदूषित करना संभव नहीं है। जबकि हालत यह है कि तैलीय रिसाव, विषैले रसायनों तथा रासायनिक एवं परमाणु कचड़ों के छोड़े जाने से समुद्र भी अब प्रदूषित हो चला है। सागर में रहने वाली मछलियां तथा अन्य कई दुर्लभ जीवों का जीवन आज संकट की ओर है। समुद्री प्रदूषण फैलाने

में विकसित राष्ट्र सबसे अग्रणी हैं। भूगर्भीय जल का अत्यधिक दोहन तथा प्रदूषण भी विश्व के अधिकांश देशों के लिए एक भयंकर समस्या है। पेय जल या सिंचाई के लिए निकाले गए भूमिगत जल की उच्च दर ने भूगर्भीय जल स्तर को काफी नीचे लाकर मरुस्थलीकरण की संभावना को बढ़ावा दिया है।

रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का कृषि में अत्यधिक प्रयोग ने स्थलीय एवं भूगर्भीय जल को सीधे तौर पर प्रदूषित करते हैं। कई स्थानों पर प्रदूषित भूमिगत जल में पाई जाने वाली लोहे, आर्सेनिक या सेलेनियम की अधिक मात्रा विभिन्न प्रकार के बिमारियों का कारण है। मौनसूनी वर्षा से जल पानेवाले भारत जैसे देशों में वर्षा जल का उपयोग एवं संग्रहण के बजाए बहुमूल्य भूगर्भीय जल स्रोत का खतरनाक तरीके से दोहन होने से उस क्षेत्र के कुएं, तालाब, जलाशय और अन्य जलीय स्रोत सूख रहे हैं। जलीय भाग से जुड़ी एक अन्य समस्या, जिसे प्रदूषण तो नहीं कह सकते लेकिन जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर मानवीय आवश्यकताओं के लिए किए जाने वाले प्रयासों के फलस्वरूप उत्पन्न होती है वह हैदू झीलों एवं जलाशयों में गाद भरने तथा अतिक्रमण के चलते जलग्रहण क्षमता का नुकसान। दुनिया के अधिकांश देशों ने शहरी जरूरतों या जल विद्युत उत्पादन के लिए प्राकृतिक झीलों का दोहन अथवा कृत्रिम जलाशयों का निर्माण किया है। तलछट के लगातार भरने से ये जलीय भाग न सिर्फ अपने उद्देश्यों को पूरा करने में विफल हैं बल्कि नदी या झील पर आधारित समूची स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र इससे प्रभावित हैं।

वायु प्रदूषण:

हानिकारक गैसों, अतिसूक्ष्म धूलकण या सूक्ष्मरूप से विसरित तरल पदार्थों ह्याैरोसोलह का वायुमंडल में उसके अपसरण की दर से ज्यादा मात्रा में छोड़ा जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसके बाह्य वातावरण में मनुष्य और उसके पर्यावरण को हानि पहुंचानेवाले तत्त्व सघन रूप में एकत्रित हो जाते हैं। मानवीय छेड़छाड़ या प्राकृतिक घटनाओं के आधार पर इसका विस्तार स्थानीय, क्षेत्रीय, महादेशीय अथवा ग्लोबल रूप में हो सकता है। जैविक या अजैविक पारिस्थिकी पर विषाक्त प्रभाव छोड़ने में वायु प्रदूषण का स्थान संभवतः सबसे महत्वपूर्ण है। कैंसर, अस्थमा और सांस की अन्य बिमारियों से लेकर अम्लीय वर्षा के चलते ऐतिहासिक इमारतों और मूर्तियों का क्षय, फसल एवं जंगलों की बर्बादी या जलीय प्रदूषण तक में वायु प्रदूषण जिम्मेदार है। अम्लीय वर्षा के लिए तो शकरे कोई और भुगते कोईश वाली कहावत चरितार्थ है। किसी एक जगह पर कारखानों या मोटरगाड़ियों से निकला धुआ, दूसरे जगह गंधकाम्ल या नाईट्रिक अम्ल की वर्षा के रूप में पेड़पौधों या ताजमहल जैसी धरोहर पर बरस कर अपना कहर बरपा जाता है।

महानगरों में बीत रही आपकी जिंदगी की हर सांस मौत का सुर सुनाती है। हालात यही रहे तो वह दिन दूर नहीं जब बाजार से शुद्ध ऑक्सीजन का पैकेट लेकर हम सांस लेते फिरेंगे। कुछ वर्ष पूर्व क्या हम यह सोचते थे कि पानी खरीद कर पीना पड़ेगा? प्रदूषण के एक महत्वपूर्ण कारक तत्व क्लोरोफ्लोरो कार्बन ह्यसीएफसीह की वायुमंडल में मौजूदगी का एक खतरनाक नतीजा ओजोन परत में कमी और फलस्वरूप पराबैंगनी विकिरणों से धरती की सुरक्षा कवच का टूटना है। ऐसा अनुमान है कि प्रकृति ने वायुमंडल की दूसरी परत में ओजोन गैसों के रूप में जीवधारियों के लिए जो रक्षात्मक आवरण दिया है उसका दस प्रतिशत इस सदी के अंत तक नष्ट हो जाएगा। पिछले 40 वर्षों में पृथ्वी के वायुमंडलीय तापमान में 2 .. 3 डिग्री की वृद्धि दर्ज की जा चुकी है और ऐसा अनुमान है कि अगले कुछ वर्षों में यह तापवृद्धि 4 से 5 डिग्री तक हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग का यह पहलू इसलिए अति-महत्वपूर्ण है कि इतनी तापवृद्धि से पृथ्वी का सूक्ष्म तापीय समीकरण बिगड़ेगा और यह जैविक संतुलन की स्थायी रचना को छिन्न भिन्न कर देगी। उदाहरणस्वरूप, ध्रुवों पर स्थायी रूप से जमी बर्फ पिघलेगी, समुद्रतल ऊंचा उठेगा और समुद्रतटीय शहर या महानगर जलमग्न हो जाएंगे। न्यूयार्क, ओस्लो या मुंबई जैसे शहर में बैठकर आप यह लेख पढ़ रहे हों तो भी भयभीत न हों- वर्तमान स्थिति की गंभीरता के प्रति अज्ञान और पर्यावरण के प्रति चेतना निरंतर नए शोध और निषेधक उपायों को अंजाम दे सकेगी। आइए, मिलकर प्रार्थना करें। हे मारुत नदन, हमारे पापों से तू हम सबकी रक्षा कर।

स्थल एवं मृदा प्रदूषण:

समाज के विकास की घड़ी की सूईयों को थोड़ा पीछे की ओर घुमा कर देखें तो कुछ दशक पूर्व स्थल प्रदूषण का कहीं कोई नामोदृनिशान नहीं था। औद्योगिक कचड़ों तथा प्लास्टिक कहे जाने चमत्कारिक वैज्ञानिक खोज ने अपना यह जलवा दिखलाया है कि शहर की कौन पूछे आज गांव में भी आप चले जाएं तो स्थल प्रदूषण की बानगी दिखाई दे जाएगी। टीन के डब्बे, प्लास्टिक, कागज, सीसे की बनी छोटी वस्तुओं से लेकर लोहे की बनी कार या ट्रक तक के कचड़ों का एक स्थान पर जमाव या बिखराव ने भूमि प्रदूषण कर जो दृश्य उत्पन्न किया है उसे देखकर निश्चय ही आप सहज नहीं महसूस कर सकते। वैसी सभी वस्तुएं जिनका कार्बनिक या अकार्बनिक तरीके से सरल तत्वों में शीघ्र अपक्षय नहीं हो सकता, भूमि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। भूमि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार तत्वों का पुनर्नवीकरण के बजाए कोई भी तरीका पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयुक्त नहीं। समुद्र में इन कचड़ों को डालने पर जलीय प्रदूषण के साथ-साथ समुद्री जीवों का आवास नष्ट होता है जबकि स्थल पर किसी निम्न भूमि प्रदेश, जो ज्यादातर दलदली भाग होते हैं, छोड़ने से उनमें रहनेवाले विशिष्ट किस्म के जीवों का

पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होते हैं।

प्लास्टिक, कागज या अन्य संमिश्र प्रकार के कूड़े को जलाने पर वायु प्रदूषण होता है। स्थलीय प्रदूषण से मिलता जुलता एक अन्य विकार है ज्ञाचद उससे कहीं घातक है, वह हैदृ मृदा प्रदूषण। हरित क्रांति या उन्नत पैदावार के लिए अपनाई गई शरासायनिक कृषि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के बजाए उसे स्थाई तौर पर बर्बाद कर रही है। हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में मिट्टी एक महत्वपूर्ण और जीवंत इकाई है। एक ग्राम उपजाऊ मिट्टी में लगभग 10 करोड़ जीवाणु और 500 मीटर के बराबर कवक के धागे होते हैं। इसके अतिरिक्त मृदा तंत्र हजारों प्रकार की शैवाल कोशिकाएं, विषाणु, आर्थ्रोपॉड एवं केंचुआ जैसे अन्य जीवों की शरण स्थली भी है। मिट्टी के पोषण शक्ति को बढ़ाने के लिए रासायनों, कीटनाशकों एवं जहरीले तत्वों का होनेवाला प्रयोग आहार चक्र के माध्यम से जानवरों एवं मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। उपजाऊ मृदा पर हो रहे नित्य नये निर्माण तथा वनों की कटाई से बाढ़ तथा मृदाक्षरण की प्रक्रिया में तेजी आई है। जनसंख्या वृद्धि के साथ बढी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 1960 के दशक में कृषि भूमि पर जापान में 7 3७ से लेकर नार्वे में 1 5७ की दर से नई आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया गया। भारत में, जहां एशिया की कुल आबादी का लगभग 27७ लोग निवास करते हैं, कृषि योग्य भूमि का स्थाई संरचनाओं से ढंका जाना तथा मृदा क्षरण दोनों की तेज दर है। भूक्षरण स्वयं ही भूमि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। 10 सेंटीमीटर ऊपरी मृदा के बनने में 100 से 400 वर्ष का समय लगता है इसलिए मिट्टी का नष्ट होना एक प्रकार से सीमित और अनवीनीकरण संपदा का नुकसान है।

ओह, मैं तो सिर्फ धरती मां की दुर्दशा पर ही चर्चा किए जा रहा हूं। क्या आप चिड़चिड़ापन, सिरदुर्द, बहन, उच्च रक्तचाप, मानसिक तनाव, नींद न आने की शिकायतों से परेशान हैं? अगर हां, तो नीचे का हिस्सा पढ़िए इलाज ढूँढने में शायद कोई मदद मिले।

ध्वनि प्रदूषण:

शहरी या औद्योगिक संस्कृति की एक अनचाही देन ध्वनि प्रदूषण है। मनुष्य या जानवरों को मानसिक या शारीरिक रूप से आघात पहुंचानेवाली किसी भी प्रकार के अनचाही और हानिकारक आवाज से संपर्क ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण वास्तव में एक गुणात्मक तथा मात्रात्मक पद है। मात्रात्मक रूप में ध्वनि प्रदूषण को उसके दबाव, उच्चता अथवा तारत्व के आधार पर श्लेसिबेल इकाई में मापा जाता है और इसकी गणना लघुगणक आधार पर की जाती है। ध्वनि का 10 डेसिबेल से 20 डेसिबेल तक के स्तर की वृद्धि वास्तव में 100 गुना वृद्धि है। ध्वनि प्रदूषण का गुणात्मक स्वरूप का संबंध स्रोत की भाषाई समझ अथवा ध्वनि की कर्णाग्रियता से है। आप अगर हिंदीभाषी हैं और मैं चीनी

या जापानी में बात करने लगू तो आप अपना सिर पीट लेंगे। हिंदुस्तानी अथवा कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत के लिए आप अगर स्नेहभाव नहीं रखते तो पंडित भीमसेन जोशी से लेकर उस्ताद फहीमुद्दीन दागर तक का नाद स्वर आपको कर्णकटु लगेंगे। शीर्ष के कुछ वर्ष आप अगर गुजरा चुके हों, तो कभी संगीत की मधुर तान सुनाई देने वाली पत्नी की बोली में आपको उच्च डेसीबेल स्तर के ध्वनि प्रदूषण का गुणात्मक स्वरूप की झलक मिल जाएगी। खैर, विज्ञान में ध्वनि प्रदूषण के साहित्यिक पहलू का कोई खास महत्व नहीं लेकिन किसी भी प्रकार के ध्वनि का मान अगर 50 डेसीबेल से ऊपर हो जाए तो मानवीय स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उसे ध्वनि प्रदूषण की स्थिति समझी जाती है। ब्यस्त यातायात या कारखानों से निकली आवाज 90 डेसीबेल स्तर की होती है। इस स्तर की ध्वनि का लगातार सुना जाना कान के श्रवण तंत्र को असंवेदनशील बना देता है और व्यक्ति बहरा भी हो सकता है। उच्च ध्वनि स्तर वाले स्थानों पर काम करने वाले लोगों में अनिद्रा, क्षीण श्रवण शक्ति, उच्च रक्तचाप या तंत्रिका तंत्र संबंधी बिमारियां पाई जाती हैं। औद्योगिकीकरण से ऊपजी इस बला को कम शोर करनेवाली मशीनों का प्रयोग, कार्यस्थल पर श्रृंखला जैसी ध्वनिरोधक यंत्रों का इस्तेमाल तथा दिवाल में ध्वनि शोषक पदार्थों का उपयोग कर काफी हद तक टाला जा सकता है।

अपने जलवायु एवं परिवेश को दूषित कर हम शांत जीवन की तलाश में पहाड़ों की ओर भागते हैं लेकिन अब तो वहां भी स्वच्छ वायु, निर्मल जल और खामोशी की अनुगूंज वाली बात बेमानी लगती है। विश्वग्राम और विकास के नाम पर फैलाई गई गंदगी का प्रभाव अब स्थानीय नहीं बल्कि ग्लोबल हो गया है। अविकसित या अर्धविकसित राष्ट्र ज्यादा औद्योगिकीकरण किए बिना भी प्रदूषण के शिकार हैं। पिछले दशकों में अपनी विकास प्रक्रिया को तेज गति देकर विकसित देशों ने वायुमंडल में विषैली गैसों का गुबार छोड़ा और जब परिणाम सामने आने लगा तो हाय तौबा मचाना शुरू किया। जवाब में विकासशील देशों का तर्क यह ठहरा कि मुझे भी उतना ही आगे आने दो फिर पर्यावरण संरक्षण की बात सोचेंगे। विकसित देश अब उपदेशक हो गए हैं लेकिन पर्यावरण को किए गए नुकसान की भरपाई के लिए किए जानेवाले प्रयासों के प्रति अपनी महती जिम्मेदारी मानने से भी पीछे भागते हैं। पर्यावरण के लिए आई अंतर्राष्ट्रीय चेतना के बावजूद आज भी अविकसित या अल्पविकसित देशों की बड़ी जनसंख्या कम आबादी वाले औद्योगिकृत राष्ट्रों द्वारा फैलाए जा रहे परमाण्विक, वायुमंडलीय या स्थलीय प्रदूषण की सजा भोगने को अभिशप्त है। जो भी हो, विकसित देशों पर दोषारोपण कर अविकसित राष्ट्र अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। प्रदूषण की समस्या न ही एक दिन में पैदा हुई है और न एक दिन में खत्म होनेवाली। पारिस्थितिकी के प्रश्न की डिबिया खुलने पर कोई जिन्त नहीं आनेवाला जो ष्या हुक्म है आकाश कहकर पलक झपकते ही समस्याओं को सुलझा दे और हम

चौन की नींद सो जाएं। पर्यावरण सुधार के लिए अगर समुचित प्रयास में हम विफल रहते हैं तो इससे अच्छा है कि प्ला अब लौट चले वाले नारे को बुलंद करें।

पर्यावरण और पारितंत्र :

पर्यावरण अपनी सम्पूर्णता में एक इकाई है जिसमें अजैविक और जैविक संघटक आपस में विभिन्न अन्तर्क्रियाओं द्वारा संबद्ध और अंतर्गुम्फित होते हैं। इसकी यह विशेषता इसे एक पारितंत्र का रूप प्रदान करती है क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र पृथ्वी के किसी क्षेत्र में समस्त जैविक और अजैविक तत्वों के अंतर्सम्बंधित समुच्चय को कहते हैं। अतः पर्यावरण भी एक पारितंत्र है।

पृथ्वी पर पैमाने (बंसम) के हिसाब से सबसे वृहत्तम पारितंत्र जैवमंडल को माना जाता है। जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें जीवधारी पाए जाते हैं और यह स्थलमंडल, जलमण्डल तथा वायुमण्डल में व्याप्त है। पूरे पार्थिव पर्यावरण की रचना भी इन्हीं इकाइयों से हुई है, अतः इन अर्थों में वैश्विक पर्यावरण, जैवमण्डल और पार्थिव पारितंत्र एक दूसरे के समानार्थी हो जाते हैं।

माना जाता है कि पृथ्वी के वायुमण्डल का वर्तमान संघटन और इसमें ऑक्सीजन की वर्तमान मात्रा पृथ्वी पर जीवन होने का कारण ही नहीं अपितु परिणाम भी है। प्रकाश-संश्लेषण, जो एक जैविक (या पारिस्थितिकीय अथवा जैवमण्डलीय) प्रक्रिया है, पृथ्वी के वायुमण्डल के गठन को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया रही है। इस प्रकार के चिंतन से जुड़ी विचारधारा पूरी पृथ्वी को एक इकाई गायख4, या सजीव पृथ्वी (सपअपदह मंतजी) के रूप में देखती है।

इसी प्रकार मनुष्य के ऊपर पर्यावरण के प्रभाव और मनुष्य द्वारा पर्यावरण पर डाले गये प्रभावों का अध्ययन मानव पारिस्थितिकी और मानव भूगोल का प्रमुख अध्ययन बिंदु है।

पर्यावरणीय समस्याएँ

ज्यादातर पर्यावरणीय समस्याएँ पर्यावरणीय अवनयन और मानव जनसंख्या और मानव द्वारा संसाधनों के उपभोग में वृद्धि से जुड़ी हैं। पर्यावरणीय अवनयन के अंतर्गत पर्यावरण में होने वाले वे सारे परिवर्तन आते हैं जो अवांछनीय हैंख9, और किसी क्षेत्र विशेष में या पूरी पृथ्वी पर जीवन और संधारणीयता को खतरा उत्पन्न करते हैं। अतः इसके अंतर्गत प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का क्षरण और अन्य प्राकृतिक आपदाएं इत्यादि शामिल की जाती हैं। पर्यावरणीय अवनयन के साथ मिलकर जनसंख्या में चरघातांकी दर से हो रही वृद्धि तथा मानव द्वारा उपभोग के बदलते प्रतिरूप लगभग सारी पर्यावरणीय समस्याओं के मूल कारण हैं।

संदर्भ

सुरेश लाल श्रीवास्तव प्रतियोगिता दर्पण, मार्च, २००६, पृष्ठ १४२३

दामोदर शर्मा आधुनिक जीवन और पर्यावरण

मधु अस्थानापर्यावरण एक संक्षिप्त अध्ययन

बासक, अनिदिता – पर्यावरणीय अध्ययन, गूगल पुस्तक, (अभिगमन तिथि 04-08-2014

Jamieson] Dale- 2007- The Heart of Environmentalism- In R- Sandler & P- C- Pezzullo- Environmental Justice and Environmentalism- (pp- 85&101)- Massachusetts Institute of Technology Press-

बासक, अनिदिता – पर्यावरणीय अध्ययन, गूगल पुस्तक, (अभिगमन तिथि 04-08-2014

सुरेश लाल श्रीवास्तव प्रतियोगिता दर्पण, मार्च, २००६

सुरेश लाल श्रीवास्तव प्रतियोगिता दर्पण, मार्च, २००६

मधु अस्थानापर्यावरण एक संक्षिप्त अध्ययन

अंग्रेजी विक्षनरी

Online etymology dictionary

सविन्द्र सिंह, जैव भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन

गाया परिकल्पना, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पर (अभिगमन तिथि 05-08-2014)

Richard Anderson] Resource depletion: Opportunity or looming catastrophe\] BBC News पर, (अभिगमन तिथि 05-08-2014)

Fred Magdoff] Global Resource Depletion: Is Population the Problem\] Monthly Review] 2013] Volume 64] Issue 08 (January), (अभिगमन तिथि 05-08-2014)

<http://hindi-speakingtree-in/spiritual&articles/science&of&spirituality/content&246889>

<http://hi-vikaspedia-in/rural&energy/policy&support/92d93e930924&915940&92a93094d92f93e935930923&92894092493f>

<http://m-jagran-com/uttar&pradesh/varanasi&city&11365556-html>

ROLE OF WOMAN ENTREPRENEURS IN RURAL INDIA

DR. JITENDRA KUMAR*

Associate Professor

Faculty of Commerce and Management

GGDSD (PG) College, Palwal

INTRODUCTION

Women's status in society can be measured in terms of educational level, income, employment as well as the role played by them in the family, society and the community. Education affects employment opportunities and the decision making role. Economic viability and education contribute either singly or jointly to women's emancipation. In fact, education and employment of women are the prerequisites not only for improving the status of women but also for moving towards gender equality.

ABOUT WOMEN ENTREPRENEURS:

Women owned business are highly increasing in the economies of almost all the countries. Women entrepreneur is a person who accepts challenging role to meet her personal needs and become economically independent with their skill, knowledge and adaptability in business, Women entrepreneur has strong desire to contribute values in both family and social life, Women who previously were known as job seekers are turning into job creators, They are flourishing as designers, interior decorators, exporters, publishers, manufacturer in urban areas and as producer farmers and small entrepreneurs in agriculture and allied sectors.

The emergence of women entrepreneur and their contribution is quite visible in India. The number of women entrepreneur has grown over a period of time especially in 1990s. They provide the society with different solution to management organization and business problems as well as to the exploitation of employment opportunities.

Women entrepreneurs may be defined as the woman or a group of women who initiate, organize and operate a business enterprise. In the Indian context, entrepreneur is more the adapter and imitator than a true innovator, as has been defined by Schumpeter.

*Faculty of Commerce & Management Studies, Maharishi Dayanand University,
G.G.D.S.D (P.G & Research) Centre, Palwal (Haryana)

As per Government of India, a woman entrepreneur is defined as an enterprise owned and controlled by a woman and having a minimum financial interest of 51 percent of the capital giving and at least 51 percent of the employment generated in the enterprise to the women.

ROLE OF RURAL WOMEN ENTREPRENEURS

Rural women play an important role to create employment in rural economy like India. In most countries averages earnings of women are lower than those of men. Empowerment of the women with resource support and information is crucial to ensuring sustainability in food production and consumption. Women occupied a central role in food production, food processing and consumption. They often participate in the cultivation of food crops and are active managers and users of resources in the most cases. However, they do not own land and therefore lack collateral assets, which could give them access to credit thus imploring to take the decision on what should be produced. Various studies have revealed that when women control the household income, they generally spent on entire household, while men spent more on its items for themselves. One of the studies in Jamaica showed that compare with the male headed households, female headed household consume food of higher nutritional quality. Women make food choice to nutrient the family and, therefore, empower them with resources to make decision in food production is essential.

Regarding farm labour, female workers contribute significantly to household income across all farm sizes and their earnings are found -crucial for landless and small farm households.

The status of female agricultural workers in decision-making is very poor. Female workers

belonging to big farm households have a better say as compared to others. The ownership of land is almost nonexistent for female workers from small and landless households. They usually surrender their earned income to the family pool and they have no freedom to spend their earned money. Female agriculture workers contribute significantly to household but they lack education, health and other support services and often, do not have access to economic resources. Moreover, they are not integrated into the mainstream of the development process. As revealed by Tuteja, in the rural areas despite being backbone of the village economy, the strategy adopted by the government to increase women welfare during the past decade has not yielded adequate results.

For centuries, women have been victim of social prejudices and discrimination. Even today, parents prefer male child to female. As a result, men and women enter organization with different skill sets. Women are taught to depend upon others, to limit their ambition and to avoid exposure and risk. Such orientations and role prescriptions inhibit development of self-confidence, innovativeness, achievements motivation and risk taking ability which is essential for an entrepreneurial career.

FUNCTIONS OF WOMEN ENTREPRENEURS

The main functions of the women entrepreneurs are as follows:

- o Explore the prospects of starting new enterprises.
- o Undertaking of risks and the handling of economic uncertainties.
- o Introduction to innovations.
- o Coordination administration and control.
- o Routine supervision.

GROWTH OF WOMEN ENTREPRENEURSHIP:

In recent years, women have made their mark in different walks of life and are competing successfully with men despite the social, psychological and economic barriers. This has been possible due to education, political awakening, urbanization, legal safeguards, social reforms, etc. In the business, the entry of women is a relatively new phenomenon. In India, women entrepreneurs constitute a negligible proportion of the total entrepreneurs. Attitudinal constraints, social traditions and kinship system inhibit the emergence of women entrepre-

neurs." The typical women enterprises are the extension of kitchen activities, i.e., 3 Ps, viz., pickles, powder (Massala) and pappad, or the traditional cottage industries of basket making, etc." In India women have contributed mainly in household industries due to the less technical know-how required and little competition from men in these industries. With the spread of the education and the growing awareness among woman entrepreneurs have entered into engineering, electronics, energy and many other industries. The phenomenon of woman entrepreneurship is largely confined to metropolitan cities and big towns in India. However, women entrepreneurs are found in the rural areas also. A rural woman entrepreneur is a woman or a group of women who undertake to organize and run an enterprise in a rural area. Reasons for the emergence of various categories of women enterprises are stated below

- o Woman who take to entrepreneurship because of dire economic needs
- o Woman who take to entrepreneurship because they had the family background /tradition in a same skill or trade. Hence, they would like to have extra money for themselves and their families.
- o Woman who take it up because they have certain personality characteristics such as need for achievement, need for power and influence, etc.
- o Women who take it up as a leisure time activity, and
- o On official advice and guidance.

In order to assist and develop rural women entrepreneurship, women at grass root level should be involved through the women's organizations. Such organizations can be instrumental in identifying women for income generating activities. The small industries service institute and voluntary organizations should organize special programs for prospective women entrepreneurs in villages. Under the integrated rural development program (IRDP), special sub-schemes can be undertaken for development of women entrepreneurs in rural areas. There exists a congenial climate for women entrepreneurship in the countries which stand at the threshold of industrialization. These countries are placing great stress on the development of small scale and cottage industries. In these countries capital is scarce and investors are cautious, markets are very limited because of the low purchasing power and

the entrepreneurs are inexperienced. These are the sound reasons for the promotion of self-employment.

In order to understand the background which produces the best women entrepreneurs and the type of action accentuating their emergence, two hypo-theses may be examined. First, women entrepreneurs are produced by the environment and the direct action on the part of government and/or other agency. Secondly, women entrepreneurs can best be developed out of the women folk, with an aptitude for an experience in entrepreneurship. There is ample evidence to show that the government efforts to promote entrepreneurship either by training or by granting loans to women without aptitude have failed miserably. While examining the factors that have been active in molding entrepreneurship, it is, therefore, necessary to look into the two aspects of the issue viz., (1) personal profile of women entrepreneurs and their socio-economic background, and (2) the extent of contact at the higher social and government levels through her husband and other family members.

SOCIO-ECONOMIC ISSUES OF THE 'FARM WOMEN' :

Greater inequalities have the largest impact on women and it has wider detrimental impact on development. When the creative abilities and personal contributions of half of the population are subjected to constant, subjugation, economic progress is bound to be adversely affected. Within the household, women have less entitlement to household goods and poorer command over a range of other productive resources including education, land, information, and financial resources and the labor to help them to undertake economically gainful activities. This in turn prevents women from building up their skills and resources. Beyond the direct effect on their ability to generate income, these factors adversely affect the decision-making capacity within the family. Women play a crucial role in all societies. However their low socio-economic status in a historical perspective is largely based on the myth that women are inferior agents of production. Much of the labor contributed in the domestic chore and outside is not usually considered as productive, even though where work is equally essential for the smooth functioning of the economy whether at the community, farm or at household level. In the recent past, the world women conference was held at Nairobi(1985) as drawn attention to the productive nature of domestic work done by women and de-

manded that proper valuation should be made of such work. If the domestic work is paid, it would account for as of national income.

The women farmers have multidimensional role as mother, housewife, producer and entrepreneurs. Therefore, it is essential to adopt multidimensional technology approach for women covering essential four spaces namely psycho-space related to her mental makeup and attitude, social space attached to her house and society, techno-space related to her productive aspects and eco space related to credit aspects. Because of the responsibilities of household and children, women prefer to have house based enterprises. Agribusiness is considered to be a sub-sector governed by women, however credit gap and quality control are the major problems faced women entrepreneurs.

Modernization and advancement of the technology has not benefited women. In fact, in many areas women have been displaced from their traditional jobs because the technology necessities training, up gradation of knowledge and skills which are out of their reach. Improved agriculture and technology accompanied by partial mechanization had affected women from all socio-economic background positively, either by revealing the women cultivator who were form higher socio economic strata having large land holding or by increasing employment of women who were from lower socio-economic strata. Full mechanization of agriculture had to relieve the women of high socio economic strata and it have negatively affected the women from lower cast and lowest income groups by reducing the demands for employment in peak session.

PROBLEMS FACED BY RURAL WOMEN ENTREPRENEURS:

India is multifaced society where no generalization could apply to the entire nation's various regional, religious, social, economic, organizational and technological constraints. Nevertheless certain broad circumstances in which Indian women live, affect the way they participate in the economy. They faced many problems. The problems were categorized into four groups namely Situation Problems: lack of irrigation facilities, lack of marketing facilities, less cultivable land, lack of motivation by family member etc, Economic Problems: inadequate finance, lack of time technique advice, inadequate training facilities and Organizational Problems: non-availability of input, time, non-availability of timely information's about

various schemes.

¢ Indian culture restricts women's access to work. When family recovers from an economic crisis, women may keep at home as demonstration of the family's morality and as a symbol of its financial security, In India, women face various forms of wage discrimination. Women tend to hold lower level position than even when they have sufficient skills to perform higher jobs.

¢ The female agricultural labor is paid 40 to 60 percent of male wage. It creates the low status of women in the economy. Female employment does not insure economic independence in the economy. If a woman is employed, she may not have control over the money she earns, though this money often plays an important role in the maintenance of the household. They can't spend the money at their own choice.

¢ Many women are untrained and illiterate. When a new technology is introduced to automate specific manual labor, women lose their jobs, because are often responsible for the manual duties.

¢ Many women are uneducated in rural area because the relationship between women education and work is not straight forwards, while in 2011 35 percent women are still illiterate in India.

¢ For men as level of education rises, the share that of main workers generally increase. The effect of the education on employment status of women is not straight forwards. Higher levels of education for women do not directly translate in to higher proportion of main workers.

¢ Employment rates for women are very low in our country. States with proportionally larger rural population typically having higher employment rates because most of people throughout India are engaged in agriculture.

¢ Women faced some problems of sexual harassment in the economy. It is not uncommon for women to be subjected to bodily searcher or fired for refusing sexual abuse. Other form of flexible work particularly in agriculture, also make it difficult for women to organize against such abuse. These young women may be doubly affected by an industrial hierarchy that reinforces based discrimination.

Problems of women who seek employment at later stage without previous experience, primarily for economic reason, loss of financial support, due to Widowhood from husbands makes their need for employment more acute

Women are employed in large number in rural area like irrigation works, agriculture operations, forestry operations, and domestic operations etc. they are subjected to brutal exploitation at places of work by contractors and middlemen who recruit them. They do not make full pay for their working hours.

Some Specific Problems of Rural Women are :

- ☞ Marginality of attention and service to them in rural and agriculture development.
- ☞ Low productivities and narrow occupation choices.
- ☞ Low level of participation in decision-making.
- ☞ Inadequate finance and expert guidance for promoting socio- economic activity of rural women and their participation.
- ☞ Inadequate monitoring of women's participation in different sectors.
- ☞ Low health and nutrition status.
- ☞ Low level of standard of rural women.
- ☞ Low saving in their area.

PROBLEMS FACED BY WOMAN ENTREPRENEURS IN GENERAL:

Women entrepreneurs face special problems and constraints. These are literacy, lack of vital information, fear to take risks, lack of experience and training, feeling of insecurity, etc. in addition, there are structural constraints in the form of inequality, limited purchasing power, condemnation by local elite, etc. they have also to face competition from the urban entrepreneurs who make more attractive and cheaper products due to modern technology and commercial production.

1. Superiority of Male Members: The greatest deterrent to women entrepreneur is that they are women. In a male dominating society male member think it is a big risk financing the ventures run by women. According to UNIDO report despite evidences that women's loan higher than men's, women still face more difficulties in obtaining credit due to discriminatory attitude of banks and informal lending groups.

2. **Shortage of Finance :** Woman and small entrepreneurs always suffer from inadequate financial resources and working capital. They are lacking access to external funds due to absence of tangible security and credit in the market.
3. **Insufficient Arrangement of Marketing and Sale:** For marketing their products woman entrepreneurs are often at the mercy of the middle men who pocket the chunk of profit. This problem is all the more serious in the case of food productions and processing ventures.
4. **Shortage of Raw Materials :** Woman entrepreneurs find it difficult to procure raw materials and other necessary inputs. The price of many raw materials is quite high.
5. **Stiff Competition :** They have to face severe competition for organized industries and male entrepreneur.
6. **High Cost of Production :** Another problem with undermines the efficiency and restricts the development of woman enterprises in the high cost of production. Government assistance in the form of grants and subsidies to some extent enables them to tide over this difficulty.
7. **Low Mobility:** One of the biggest handicaps for women entrepreneurs is mobility or traveling from place to place.
8. **Family Responsibilities:** In India, it is mainly a woman duty to look after the children and other members of the family. Her involvement in the family leaves little energy and time for business. The development of kindergartens, day nurseries and creches and family planning have to some extent helped woman entrepreneurs to carry on business without affecting the social prestige of their husbands.
9. **Social Attitudes :** In rural areas woman face resistance not only from males but also from elderly females who have accepted inequality. Rural woman have the potential but they are not properly trained. In a male dominated society woman do not get equal treatment and male ego puts barriers in her progress.
10. **Low Ability to Bear Risk :** Woman has comparatively a low ability to bear economic and other risks because they have led a protected life.
11. **Lack of Education :** In India literacy among woman is very low Due to lack of edu., majority of woman are unaware of technological developments, marketing knowledge etc.

12. Lack of Self-confidence : Woman lack self confidence and risk bearing capacity. They always feel that they may be not be successful and hence hesitate to take risks.
13. Psychological Factors : Woman always feels that she is "woman" and less efficient then man and hesitate to take risk,
14. •Lack of Practical Knowledge : She lacks practical knowledge and hence hesitates to establish her own venture
15. Problem of Marketing : Their marketing knowledge will be less and lack marketing skills as compared to men.

Woman entrepreneurs should be provided the following type of assistance.

1. Promotional Help : Preparation of project report, registration and licensing help etc,
2. Training: Achievement motivation training and training in the particular industry should be provided.
3. Selection of Machinery and Technology : Suitable assistance in the choice of appropriate machinery and equipment should be provided. A 'machine and the process bank' may be created to provide data about machinery and technology transfer.
4. Finance : Necessary credit for fixed and working capital should be given.
5. Marketing Assistance : Sufficient data and marketing intelligence should be made available to woman entrepreneurs.

AREA OF RURAL WOMEN ENTREPRENEURSHIP :

Agriculture Horticulture, sericulture, Dairying and Animated Husbandry, Fisheries, Home based industries like manufacturing of agarbati, papad, pickle, apparels, stationery, packaging material, handicrafts and bed sheets, tailoring, garments industries, Pottery, blacksmith industry, bee keeping, dollmaking, food processing, beauty parlours boutiques tutorials classes etc.

ROLE OF WOMEN ENTREPRENEUR'S ASSOCIATION:

With the growth of women entrepreneurs, a few, associations of women entrepreneurs have been set up both at international and national levels. The main purpose of these association is to create a congenial environment for developing women entrepreneurship in rural and urban areas. These association seek to achieve the following objective:

1. To provide a meeting ground for women entrepreneurs;
2. To promote and develop feelings of unity and brotherhood among the entrepreneurs;
3. To develop self-confidence and hope among female entrepreneurs;
4. To present the problems of women entrepreneurs before the concerned authorities for consideration and redressal.
5. To secure various concessions, subsidies and assistance for women entrepreneurs;
6. To conduct entrepreneurial development programmes for women;
7. To organize seminars and conferences on entrepreneurship with the help of other national and international bodies;
8. To secure wider dispersal of entrepreneurship among women;
9. To establish useful contacts for promoting women entrepreneurship;
10. To perform other activities to improve the operational efficiency of women entrepreneurs, etc.

Some of the women entrepreneurs in India and abroad are described below:

1. Women entrepreneurs Wing of NAYE
2. Indian Council of Women Entrepreneurs
3. FICCI Ladies Organization (PLO)
4. National Commission on Self Employed Women in the Informal Sector
5. World Association of Women Entrepreneurs (WAWWE)
6. Association Country women of the World (ACWW)

GOVT. EFFORTS TO EMPOWER RURAL WOMEN ENTREPRENEURS:

Various government and non-government. Schemes have been introduced from time to time to help the rural women. These schemes have been beneficial for empowering the women in rural area where reservation is made for the women folk.

- ¢ Training of Rural Youth for Self Employment(TRYSEM).
- ¢ Integrated Rural Development Program (IRDP).
- ¢ Development of Women and Children in Rural Areas (DN, VCRA).
- ¢ The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS),
- ¢ Swam jayanti Gram SWAROJGAR YOJNA(SGSY).

- ¢ Rural Infrastructure and Development.
- ¢ Bharat Nirman.
- ¢ The Sarva Shiksha Abhiyan(SSA).
- ¢ Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya(KGBVS).
- ¢ National Programme for Education of girls at Elementary Level (NPEGEL).
- ¢ Janani Suraksha Yojna(JSY),
- ¢ Integrated Child Development Services(ICDS),
- ¢ Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls(RGSEAG).
- ¢ The Rajiv Gandhi National Creche Scheme for Children of Working Mothers(RGNCSCWM).
- ¢ Integration Child Protection Scheme(ICTS).
- ¢ Support to training and Employment program to women (STEP).
- ¢ National Mission for empowerment of women(NMEW).

CONCLUSION:

Women entrepreneurs are a vital group for the country's economic development. Proper attention and adequate support has not been provided to this group. In terms of gender equality index India's rank is 122 out of 168 countries having Index value 0.748 which shows the gender disparities in the areas of empowerment, labour force participation and reproductive health, The gender index indicates high degree of gender discrimination in India compare to countries like China and Sri Lanka. Programs for women entrepreneurs should Focus on two major areas. First, social attitude and discrimination against women need to be removed. Secondly, adequate facilities should be provided to widen entrepreneurial base among women. Women entrepreneurs on their part should adopt modern management concepts and improve their part competitive strength. Women entrepreneurship movement in India is still in transitory stage and has a long way to go. Women should realize their power and reach out for new areas and new responsibilities. Thirdly, the existing limit for obtaining working capital from banks without collaterals should be raised as women find it difficult to provide collaterals. And the future will, no doubt, see more women venturing into rural areas traditionally occupied by men.

REFERENCES:

Books / Journals

- " Aga Anita, 2008 Indian Women Works and Development G: yan Publishers pp. 330-332. Economic Survey 2010-2011, Govt. Of India Oxford University Press pp 291, 300-319. Kaur Ma/kit. 1988: Rural Women and Technological Advancement, Discovery Publishing house, New Delhi pp. 103-105.
- " Singh D.P. 2005 Women Workers In Organized Sector, Deep And Deep Publication pp 38. Verma S.B. Singh M. Rural Women Entrepreneurs Edited By Verma S.B., Tuka Ram
- " P.Y., Khetan S.D. :2005 Rural Entrepreneurial And Employment "Indus Valley Publications Jaipur - New Delhi, pp. 1-3, 94-103, 107-111.
- " Wasnik KR 2006 : Women In Apiculture Kalpaz Publication New Delhi pp. 12-16 Gopalan Radha 2011 Sustainable Food Production And Consumption Agenda For Action, Economic And Political Weekly ,36914 & 15) pp. 1207-1225.
- " Iyoti K. S. Gray And Suga Prakash C.P. 1999, Evolvement And Decision Making By Rural Women An Economic Study Karnatka Indian Journal Of Agricultural Economics, 53(3) p. 308.
- " Marup Tashi Not A Fleding Any More, Kurukshetra, Ministry Of Rural Development June 2010, Vol.-58(8) pp. 14-15,
- " Patel Amit Empowerment Of Rural Women, Kurukshetra, Ministry Of Rural Development June 2010, Vol-58(8) pp. 4-5.
- " Trateja usha 2012 Contribution of Female Agriculture Workers in Family Income and Their Status in Elagana, Indian Journal of Agricultural Economics 55(2) (32-67).
- Web sites:
www.Score.Org/Topics/womens
www.Managementparadise.com/TOI Aug 18, 2014
www.Article Times of India.com

The rule of syed Qutb in the educational reformation of Egypt.

IMTIYAZ AHMAD WANI

Research scholar,

Department of Arabic

Barkatullah university Bhopal (M.P)

Syed Qutb (1906-1966) was an eminent Egyptian literary personality. He is best known as an educator, Islamist radical, poet, journalist, author and the leading member of the Egyptian Muslim Brotherhood. He had a bright academic career and has been working in various capacities in the ministry of education. Syed was a great teacher and influential educational thinker, who developed the new concept of true education. He viewed that every human being has a right to an education that will enable him to develop his faculties and live a full human life. He has played key role in promoting advanced education system in Egypt. He suffered and sacrificed his lives so hat better education system could prosper in Egypt. He was a true- hearted critic of Egyptian education system. His faith in the power of education to bring about radical social change formed the core of his teaching. In short, he was a source of inspiration and course for the Egyptian society.

Syed Qutb has performed a number of important services for Egyptian education system. His articles often contained numerous references to the importance of education. He felt that education is the solution of Egyptian problems. He was essentially concerned with the basic educational problem of shaping of hearts and minds of Egyptian people. He af-

firmed in his writing that ministry of education should make plans for the creation of a new mind and a new character for which right education is more important than the other developments. To raise literacy rate of Egypt he has co-operated with the govt. on anti-illiteracy campaigns. Syed has wrote many articles for the reformation of Egyptian education system. In order to light the lamp of knowledge in every family he has gave stress on new trends and techniques in education. It is the fruit of his reformation movement that In 1971 the Egyptian constitution has established the following fundamental frame work for education system in Egypt :-

- " Education is a basic right for all Egyptian citizens (article no. 1
- " The Egyptian state is responsible for education and it supervises it to guarantee equity (article no. 19) .
- " Education in all education institutions in Egypt is free in its various stages (article no. 20) [1]

The aim of education, as syed saw it, wasn't simply to read and write or to impart knowledge, whether religious or secular. Rather he sought in education the achievement of a comprehensive moral edification and the shaping of fully those personalities whose manners, way of thinking and sense of moral duty were defined entirely in accord with the Islam.

He was a staunch critic of Egypt's educational system, citing it as a principal reason for his country's modern troubles , backwardness and weakness relative to the west. He observed that high qualified personalities of Egypt lacked very fundamental knowledge of their cultural traditions. According to Qutb Egypt has no major accountability infrastructures. School buildings and their respective surroundings are not clean. School do not promote cleanliness or good hygiene. To remedy this, he felt that our educational system required a complete curricular and spiritual overhaul .He sought to create an educational method that would develop Egyptian society into sincere believers, equipped mentally, physically and spiritually to carry out the work of Islamic reform and revival. He is against the concept of that curriculum which ranged from the broadest scope to include a students entire learning experience to the nar-

lowest domain of simply referring to educating text books and materials. In our curriculum there must be the central structure that frames what and how a student acquires skills and knowledge.[2]

Syed Qutb has tried his level best to reform education system of Egypt. He fought for the development of Egypt's education system and wrote many articles to change its boring syllabus, teaching methodology and pattern of examinations. He says that it is best for secondary department that we should teach them two books of each knowledge; one must be on spiritual studies and other on any literary or scientific topic. By doing so students can take benefit and literary taste of reading and studying and they can also attain soul food.[3] These changes have been made with an eye on unfruitful system of Egypt since from medieval Egypt. He has wrote an article against the dangerous method of study that reduces Egypt's education system. In which he says that the first target of our present education system is to turnoff the student's independent ability of study. In this system students fully trust upon teachers. Teachers depend on the course book, not on detailed and comprehensive sources. In order to prepare students for examinations they make small summaries of each lesson or a pamphlet and delivers lectures from the said sources. Why they do so? They do so only to attain more pass percentage![4]

When syed Qutb has appealed ministry of education to change this undue system. They replied " okay we will abolish examinations." in response to their comment Qutb told them that badness is not in our ministry or in examinations but in the examination pattern.[5]

Qutb supports play way method of teaching and condemns corporal punishment which is common practice in Egyptian schools.[6] Punishment seems to be in affective, dangerous and unacceptable method of discipline as it brings negative rather than positive impacts to students. The positions of the teacher must be raised to that which it is used to occupy in Egypt, so that to sit in the teacher's chair will be a badge of social honor. His work must be seen as belonging to the great Teaching Department in the govt. of our world and his relations with his peoples must be a copy of the relation between a master and his disciples. Love, protecting and elevating on the one side must be met with love, confiding and trustful.

Punishment must disappear. The school must be a centre of good and joyous influences. Punishment is one of the main obstacle in our literacy rate. Syed Qutb, such a geneous personality had left the school due to severe punishment of his gym master to his students in the primary school of Egypt as Qutb says that all this caused such an overwhelming fear that each day that he was to come seemed like the Day of Judgment, whose terror turned the children's hair white. Our child heard so much from his older cousin about this devil- the gym master- that what he heard was one of the many things that made him uneasy about the school in spite of all its attractions.[7]

Syed Qutb has encouraged literature, literary personalities and great educators and facilitators in his educational reformation movement. As he says that the body of living literature which revives artistic taste is formed by odes, poems, fictions, novels, researches and studies and other genres of literature. Therefore it is mandatory for the ministry of education that they should encourage above mentioned forms of literature instead of weary eloquence in secondary schools. During the revisions of syllabi interests of the students, difficulty of their age group and sequence should be used as criteria to decide the subjects and subject matter to be taught at secondary levels.

In view of his academic and administrative excellence, the Ministry of Education sent Syed Qutb to America ostentatiously to study, evaluate and analyze the American educational and upbrining system. [9] Another aim of this tour was to transform his vision, corrupting him with western culture and mobilizing him to the service of the Egyptian ruling class through western indoctrination and cultural decadence. In short, it was to enlist him into becoming an agent of the Egypt's government but this goal was definitely not realized. Over a two-year period(1948-1950) he worked and studied in the famous universities and colleges of America: Wilson Teachers Collage in Washington, D.C., Colorado State Collage For Education in Greeley and Stanford University.[10] Qutb was impressed by American technology but appalled at what he considered the low moral and cultural state of its people.[11] His reaction to the western world was decidedly negative; he found western society hopelessly materialistic, corrupt, morally loose and ridden with injustice. Although he ac-

knowledge the economic and scientific development of America. In short, he was critical of things, he had observed in the USA: Its civilization[12] materialism, individual freedoms, brutal boxing, the American view of death,[13] The feelings of Americans towards religion and sex[14]. He was distressed by the disrespect shown to Arabs in America and the overwhelming support of its inhabitants for Israel.[15]

Egyptian govt. was in favor of American education and upbringing system. They want to follow American and communist ideas instead of Islam. Syed Qutb did not put any bars or holds on the acquisition of any kind of knowledge, provided it is for common good of the society. For this he has no objection to follow America in science and technology. He wanted to create a scientific temperament among his society and to make the modern knowledge of science available to them. The knowledge on the laws of behavior of physical matter developed in science and technology does indeed form an important portion of education. However for equitable distribution and appropriate utilization of resources and benefits brought about by technological advancement education that develops morality and character is the foremost need of the time. As Qutb Says that there is a strong relationship between faith and all those sciences which deal with the universe and natural laws, such as astronomy, biology, physics, chemistry and geology. All these sciences lead man towards God.[16] He championed the cause of modern education at a time, when Egyptian society considered it a sin to get modern education. He says that the sphere of knowledge is not limited to articles of faith, religions obligations or laws about what is permissible and what is forbidden; its sphere is very wide. it includes all these and also the knowledge of natural laws and all matters concerning man's delegated role before God. He condemns the imitation of America in education and moral training, because it is not worth in the scale of human values as he says: "I fear that a balance may not exist between America's material greatness and the quality of its people. And I fear that the wheel of life have turned and the book of time will have closed and America will have added nothing, or next to nothing, to the account of morals that distinguishes man from object and indeed, mankind from animals".

His general message to Egypt's govt. is to follow Islam in each and every aspect of life particularly in education. He considered all systems of education other than Islam are unfit and unreasonable for Egyptian society. He is totally against those societies in which God's existence is denied and human history is explained in terms of intellectual materialism and scientific socialism becomes its system. And also that society in which God's existence is not denied, but his domain is restricted to the heaven and His rule on earth is suspended, In the society people are permitted to go to mosques, churches and synagogues. Yet it doesn't tolerate peoples demanding that the shari'ah of God be applied in their education system. These societies should remember that the source of learning is God from Him man receives all his knowledge, past, present and future. From him man learns any secret revealed to him about this universe, life and himself. He is the one who creates, originates and teaches. Whatever man learns and whatever experience and knowledge he acquires come originally from God. He has taught man what he did not know.[18] It clearly shows that Egyptian cultural and civilizational psychology will never accept American Education System.

According to Syed Qutb, the objective of education is to develop a righteous person and to create a righteous society in support of his vision Gandhi has said that education is the all round drawing out of the best in child and man's body, mind and soul.[19] In order to achieve the said objectives, Syed Qutb however believes in an all inclusive and holistic education as he called for the integration of Islamic emphasis and Islamic philosophy of education in the national curriculum instead of the Zionist western and un-Islamic educational systems.[20] On many occasions he attempted to reform the ministry of education, establish a special professional department that would overhaul the entire educational system and its curricula but all in vein. In nutshell, Syed Qutb's proposals and programmes were pearls of wisdom and gems of thought to Egyptian society but unfortunately Jamal Abdul Nasir has rejected his proposals to reform educational system of Egypt. because he was an opponent of communism. In its view, the most fundamental needs of a human beings are those which are common with the animals. So, Qutb realized that Jamal has adopted problematic aspect of modernization, which leads to psychological, social and cultural stresses.

Therefore ministry of education is not prepared to institute the Islamist program for the Egyptian society and resigned from ministry of education in October 1952 and criticized its policies by saying this that the Islamic educational system is the only divine way of education which brings out the noblest human characteristics, developing and using them for the construction of human society. Our system has remained unique in this respect till the age. Those who deviate from this system and want some other system, are truly enemies of mankind! They do not want man to develop those noble characteristics which have been given to him by his Creator, nor do they wish to see a human society benefit from the harmonious blending of all those capabilities, experiences and characteristics which have been developed among the various races of mankind.

References

- [1] National Center for Educational Research and Development, Education Development ,cairo, Egypt, 2001, p8
- [2] Al-Risal, p 799 ,No.941, 16/7/1951 (Journal)
- [3] Umeri Sallahu al Deen ,syed qutb aak adeeb, aak sahafe, Arwra Printers and Computer Center ,Shadra, Delhi , p 93
- [4] Al-Risala (magazine), no.941, 16/7/1951
- [5] syed qutb aak Adeeb, Aak Sahafe, p 95
- [6] <https://en.m.wikipedia.org/.../Education> date 23/4/2016
- [7] Qutb Syed, Tifl min-al qaryah, manshurt-al jaml , Germany , 1428A.H, p 11
- [8] Al-Risala (magazine), no.941, 16/7/1951
- [9] Al-azm Yousf, Al-shaheed syed qutb, Dar-ul qalm, Damacus , Baruit, 1980, p 34
- [10] Encyclopedia Of World Biography, 2004
- [11] Calvert John and Shepard , A Child From The Village, Syracuse University Press ,New York, 2004, p xix
- [12] Qutb Syed, The America I Have Seen: In the Scale of Human Values (Amrika allate Raietu) Translated by Tarek Masoud and Ammar Fakeeh, Kashf -ul Shubuhah Publications, Portland Staye University, p 2

- [13] The America I Have Seen: In the Scale of Human Values P 7
- [14] The America I Have Seen: In the Scale of Human Values P 9-13
- [15] Calvert John, "The world is an Undutiful Boy :sayyid Qutbs American Experience
Islam and Christian -Muslim Relations,vol.2,p 87-103
- [16] Qutb Syed ,Milestone,USA:SIME journal(<http://majalla.org>)2005 p 81
- [17] Qutb Syed,The America I Have Seen :In the Scale of Human Values , p 2
- [18] Qutb Syed,Fi Zilal al-Qurqan,, Dar-al Sharook Cairo ,vol.6, p 4339
- [19] Kumar Satish and Ahmad Sajad,Meaning,Aims And Process Of Education,p 2
- [20] Qutb Syed ,AL Adalah al-ijtimaiyyah fi al-islam, Beirut:Dar al-shuruk, 1978,p 249-
250
- [21] Qutb Syed ,Milestone,USA:SIME journal(<http://majalla.org>)2005 p 29

Retail Investors: Reluctance and Necessity

Smriti Tiwari Semwal

Assistant Professor

Department of Management Studies

Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal

Abstract

The penetration in Indian capital markets is very low. Out of 1.1 Billion people in India, only about 0.25 Million people invest in stock markets, directly and indirectly, when capital markets are the only option where retail investors can beat the soaring inflation and provide liquidity at the same time. This paper attempts to highlight this discrepancy and discuss the underlying reasons for low retail participation in India.

Keywords

Retail investors, Indian capital markets, investments

Introduction

It is no news that Indian capital markets are underpenetrated. The Indian markets have been transformed by the economic and financial liberalization that happened in the early 90s. The S&P BSE Sensex, known as the pulse of the Indian stock markets, rose gradually from its first four digit hit in July 1990 and crossed the 30,000 mark in 2015, clocking 30 times return in 15 years, a return on investment which is difficult to mimic. This would usually lead to the assumption that there should be a correlated increase in the number of investors in capital markets as well. However, this has not proved true in the Indian context.

Low retail participation in the Indian Capital Markets

The retail participation in India has been hovering around low levels since long. The definition of the 'retail investor' in India has changed over time in congruence with the changing economic scenario. Today the SEBI defines, and includes in SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations), a retail investor as an individual investor applying for securities worth Rs. 2, 00,000 or less. The number of retail investors in India is close to 2.02 million according to a 2011 study from the Indian School of Business (De, 2015), which is only about 0.22 percent of the country's population, found using the number of retail investors who engaged in at least one trade between January 1, 2005 and June 30, 2006 on the NSE.

Apart from the natural cyclicity of the markets, the Indian markets have performed quite well in the last decade. The Sensex gave a return of 17% compounded annually between August 2004 and August 2014. This return is almost twice as much as the return Indians earn from one of their most trusted mode of financial services, the fixed deposits. Yet the proportion of retail turnover to total turnover actually declined from over 80 percent in 2003 to under 35 percent in 2013 according to a report by Bloomberg.

Why the reluctance?

Attempts to understand this reluctance of the retail investors is essential. Evidently, retail investors lose money on an average because of incorrect 'timing the market'. The market specialists unanimously hold the view that buy decisions must be made when the market is falling and sell decision must be made when the market rises. However, the behavior of retail investors is Contrarian (Constable). "Net inflows to equity funds tend to rise with stock prices, and net outflows tend to occur when stock prices fallout."

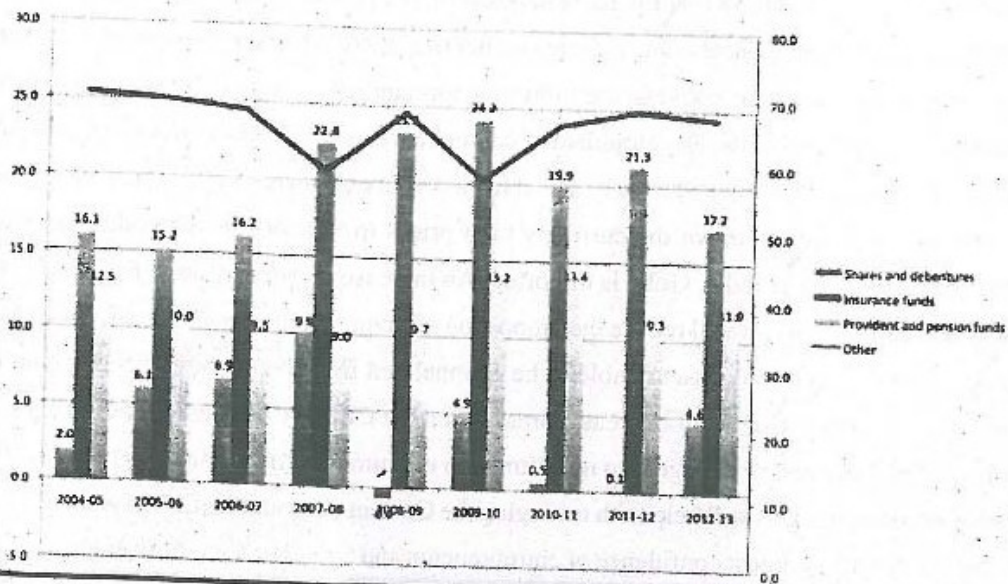
This means that the retail investors buy when the stock prices have already reached a high level, and sell when the stock prices have reached a low level, thereby losing out as compared to the average return. Another reason for reluctance in retail participation could be that the primary market, the market for Initial Public Offerings, which usually attracts retail participation, has not performed up to the mark in India. According to a Bloomberg analysis of 394 IPOs between 2003 and 2014, only 164 companies were trading over their offer.

price. Thus, 60 percent of investors lost money over a decade. A third reason of reluctance in retail investor participation could be the perception that a few big players manipulate India's stock markets. The stock market scams like Harshad Mehta scam, Ketan Parekh scam, the recent Sahara issue have fuelled this perception over the years. The widespread and infamous corruption in the country across domains doesn't help the perception either, resulting in retail investors shying away from a 'legalized gamble'.

The growing importance of increased retail participation and market development

India's GDP per capita for FY 16 stood at close to \$2.20 Trillion. The market capitalization in the financial year 2015-16 was \$ 1413.81 Billion USD according to BSE, around 60% of India's GDP. This money which is put into the capital markets benefits the Indian economy tremendously. It goes to the companies and helps in creating jobs, developing products and providing services. India needs about \$1 Trillion new investment in the current five year plan to develop infrastructure as per the Planning Commission. Making this kind of money available is not easy, given that proportion of India's financial saving into capital markets is low.

Distribution of Household Financial Savings (%)



Source:

Central Statistical Organization, National Accounts Statistics, available at www.Mospi.nic.in. What is important to us is the proportion of financial savings that the investors have chosen to park in instruments directly or indirectly linked to the stock market as this is the household saving that has entered the stock markets. As shown by the chart above, from the period 2004-05 to 2012-13, around 70 per cent of household savings in financial assets was in the category "Other", consisting of currency, bank and non-bank deposits or claims on government, the exception being in two years 2007-08 and 2009-10. From this we can infer that the instruments that expose the households to the capital markets directly or indirectly viz. Shares and debentures, Insurance funds and Provident and pension funds have, largely, on average accounted for between 30 and 33 per cent of household financial savings during this period.

This low percentage of financial saving that gets channeled into capital markets does not help in making available sufficient capital for the development of the economy in general. A widening of the capital markets hence becomes essential.

Capital market is the only place an investor can beat inflation. The widely popular and middle income household's favorite Bank deposits offer a post tax return that is less than the inflation. Investment in Real estate requires higher ticket size which creates an entry barrier for small savers. In stock markets, the minimum amount required to carry out a first ever trade is only in three digits. Development of capital markets may reduce investment in real estate. Real estate sector may hence be saved from speculation investment which will eventually help in bringing down the currently high prices in the sector. The other favorite investment avenue of India, Gold, is imported. An increase in proportion of financial savings into capital markets will reduce the proportion of savings that goes into gold, which has largely been a hold-only asset unable to be channelized into the economy. Since gold is imported in India, love for gold creates pressure on the Current Account Deficit. Hence a shifting of the investment in gold to investment in instruments linked directly or indirectly with the stock markets will help with managing the Current Account Deficit as well. Development in markets boost confidence of entrepreneurs and Small and medium enterprises as

well which will lead to growth of the Indian economy as well as society in general. Learning from the markets in developed countries have shown that as per capita income increases, so does the incomes and surpluses in the hands of the middle income and upper middle income households, which increases their financial savings as well. It is inevitable thus that gradually, the retail investor presence will deepen on its own as well as the per capita income rises in future. However, deliberate steps by the regulator to increase the retail investor presence in Indian capital markets are the need of the hour.

Conclusion

It is clear from the above discussion that the retail investors in India have been shying away from the capital markets which are a crucial component of Indian economy. A widening and deepening of markets is required if India is to reap fully the benefits of liberalization and grow economically as well as socially. Such maturing of markets is imperative as India moves further as a developing economy and deliberate steps have to be taken to educate and entice the retail investors towards this goal.

References :

- Bloomberg View. (2015, April 8). Retrieved May 23, 2016, from [www.bloomberg.com: http://www.bloomberg.com/view/articles/2015-04-09/india-stock-rally-needs-more-domestic-retail-investors](http://www.bloomberg.com/view/articles/2015-04-09/india-stock-rally-needs-more-domestic-retail-investors)
- Constable, S. (n.d.). Retail Investors Fleeing US Stocks is a Buy Signal. Retrieved september 8, 2015, from www.thestreet.com: https://www.thestreet.com/story/13200921/1/retail-investors-fleeing-us-stocks-is-a-buy-signal.html
- De, S. N. (2015). Behavioral biases, investor performance, and wealth transfers between investor groups.
- Investment in Infrastructure. (n.d.). Retrieved may 24, 2016, from [www.planningcommission.nic.in: http://planningcommission.nic.in/plans/mta/11th_mta/pdf/14_-_Investment_in_Infrastructure_-_29-04-2010\[1\]gupthaji.pdf](http://planningcommission.nic.in: http://planningcommission.nic.in/plans/mta/11th_mta/pdf/14_-_Investment_in_Infrastructure_-_29-04-2010[1]gupthaji.pdf)
- Markets. (n.d.). Retrieved May 23, 2016, from www.bseindia.com: http://www.bseindia.com/markets/keystatics/Keystat_maktcap.aspx?expandable=0

PRIMARY PREVENTION IN DENTISTRY

RITIKA BHARDWAJ

Undergraduate Student At :

**Rishiraj College of Dental Sciences and
Research Centre. Bhopal (Madhya Pradesh)**

Introduction

In the year 2000, in the Executive Summary of the Surgeon Generals Report on the "Oral Health in America," some of the major challenges facing American dentistry were listed.^{1,2} It is appropriate to abstract a number of these problem areas in order to better understand the role that prevention can play in their solution.

1. Tobacco: This is a major societal health problem with very strong relationships to dentistry. Smoking has a very devastating relationship to periodontal disease and oral and pharyngeal cancer, while the use of chewing tobacco is associated with oral cancer as well as root decay.

2. The statistics of dental need:

Children

a. Dental caries is the most common chronic childhood disease.

b. Over 50% of 5- to 9-year-olds have at least one cavity or filling; by age 17, the percentage has increased to 78%.

c. As a part of childhood, children have many injuries to the head, face, and neck. d. Twenty-five % of the children have not seen a dentist before entering kindergarten. e. More than 51 million school hours are lost each year to dental-related illness.

Adults

a. Most adults show signs of periodontal or gingival diseases. Severe periodontal disease

[measured as 6 millimeters of periodontal attachment loss (pockets)] affects about 14% of adults aged 45 to 54. b. Employed adults lose more than 164 million hours of work each year because of dental disease and dental visits.

c. A little less than two-thirds of adults report having visited a dentist in the past 12 months. Older adults

a. Twenty-three % of 65- to 74-year-olds have severe periodontal disease (characterized by 6 millimeters or more of periodontal attachment loss). At all ages, men are more likely than women to have more severe disease.

b. About 30% of adults 65 years and older are edentulous, compared to 46% 20 years ago.

c. Oral and pharyngeal cancers are diagnosed in about 30,000 Americans annually. Nine thousand die from these diseases each year. Prognosis is poor.

d. At any given time, 5% of Americans aged 65 and older (currently some 1.65 million people) are living in long-term care facilities where dental care is problematic. a United States Public Health Service.

Throughout the entire Surgeon General's report, there is major emphasis on the great disparity between those who get dental care and those that do not have access to a dental facility. These are the people who are poor, are mentally handicapped, those that are disabled, children, and those without dental insurance. There are others living in underserved geographical areas, and still others who do not have access to dental care because of disease, culture, or race. To address these problems a national program and guidelines of dental care is needed that will include these dentally neglected groups. The questions then become, "What kind of a national program should it be? Is it possible to take care of so many people with so few dental health professionals?"

It is the goal of the dental profession to help individuals achieve and maintain maximum oral health throughout their lives. Success in attaining this objective is highlighted by the decline of caries throughout the Western world,¹⁷ and the dramatic reduction of tooth loss among adults in the United States. This progress has been mainly attributed to the use of water fluoridation and fluoride-containing products toothpastes and mouthrinses and the growing acceptance and practice of primary preventive care. Yet, dental caries remains a major pub-

lic-health problem. Untold millions of research hours and money have been invested in reaching our present capability to control the ravages of the plaque diseases. Effective strategies that can markedly reduce the number of carious teeth and better control of periodontal disease are now available. They only need to be used.

All health professions emphasize that patients should seek entry into well-planned preventive programs. For dentistry, lack of prevention results in more restorations, periodontal treatment, extractions, and dentures. The changeover in priority from treatment to prevention will require active leadership and health promotion by the dental profession, consumer advocates, public health educators, and health-policy planners. Public-health delivery systems, such as the military, national and state public-health services, and industrial organizations that provide benefits to their personnel, have usually been in the forefront of such change because of the economic advantages accruing to the provider and health benefits to the recipients. For example, in 1989, a report by Malvitz and Broderick¹⁹ recounted the results following the change of focus toward a maximum emphasis on prevention for dental services by the Indian Health Service in the Oklahoma City area. The total number of visits increased by 10%, yet the number of dental personnel remained constant. The percentage of preventive services increased, along with a decrease of restorative procedures.

Benefits of Primary Preventive Dentistry to the Patient For the patient who thinks in terms of economic benefits and enjoyment of life, prevention pays. Many studies document the prevalence of dental disease, but behind these numbers there is little mention of the adverse affects on humans caused by dental neglect. One study points out that 51% of dental patients have been affected in some way by their oral health, and in 8% of the cases, the impact was sufficient to have reduced their quality of life. If preventive programs are started early by the patient (or, preferably, by the parents of young children) long-range freedom from the plaque diseases is possible a sound cost-benefit investment. After all, the teeth are needed over a lifetime for eating. Speech is greatly improved by the presence of teeth.

A pleasant smile enhances personality expression. Teeth also contribute to good nutrition for all ages. At rare times, teeth have even provided a means of self-defense. On the other hand, the absence of teeth or presence of broken-down teeth often results in a

loss of self-esteem, minimizes employment possibilities and often curtails social interaction.

Benefits to the Dentist

Possibly the first benefit of preventive dentistry is the fulfillment of the moral commitment to the Hippocratic Oath that was taken by health professionals at graduation "to render help to those in need, and to do no harm." Through ethics and training, the dentist should derive a deep sense of satisfaction by helping people maintain their oral structures in a state of maximum function, comfort, and aesthetics.

A well-balanced practice that actively seeks to prevent disease but is also able to care for those individuals where prevention has failed should purpose. Patients can be outstanding public relations advocates if they are convinced that their dentist and staff are truly interested in preventing disease.

If for no other reason, a dentist should consider prevention to avoid possible legal problems.

A now strongly supported law for medicine, but to a lesser extent for dentistry, requires that prior to treatment, all options preventive as well as treatment should be explained to secure informed patient consent. This discussion should include a comparison of health benefits and hazards, as well as the economic and the oral-health benefits of prevention. Long-term patients, the lawyers and the court system are taking a more unsympathetic attitude toward practitioners who have permitted a disease to progress over many years without having taken some accepted primary preventive actions to have slowed, or halted its progress. Patients no longer tolerate supervised professional neglect.

What is Primary Prevention?

When discussing primary prevention, we must first define a few key words. Health is what we want to preserve, and it is defined as a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. For instance, some individuals may actually be in excellent health but believe, for some reason logical to them, that they have oral cancer. Such individuals do not have an optimum mental well-being and will continue to worry until they are somehow convinced otherwise that they are indeed healthy. Another person may be functionally healthy, although facially disfigured, and as such be socially shunned throughout life. Thus, health can at times be what the patient thinks and

not the actual condition of the body. Even the terminology "preventive dentistry" has different connotations to different people. As a result, preventive dentistry can be arbitrarily classified into three different levels. 1. Primary prevention employs strategies and agents to forestall the onset of disease, to reverse the progress of the disease, or to arrest the disease process before secondary preventive treatment becomes necessary.

2. Secondary prevention employs routine treatment methods to terminate a disease process and/or to restore tissues to as near normal as possible.

3. Tertiary prevention employs measures necessary to replace lost tissues and to rehabilitate patients to the point that physical capabilities and/or mental attitudes are as near normal as possible after the failure of secondary prevention .

primary prevention, specifically focuses on primary prevention as it applies to the control of dental caries and periodontal disease. On the other hand, it must be recognized that primary prevention often fails for many reasons. When such failure occurs, two actions are essential to contain the damage:

(1) early identification of the disease (diagnosis) and (2) immediate treatment of the disease.

Categories of Oral Disease

For planning purposes, dental diseases and abnormalities can be conveniently grouped into three categories: (1) dental caries and periodontal disease, both of which are acquired conditions, (2) acquired oral conditions other than dental caries and periodontal disease (opportunistic infections, oral cancer, HIV/AIDS), and (3) craniofacial disorders which would include a wide variety of conditions ranging from heredity to accidents. For instance, the ordinary seat belt and the air bags in a car exemplify how a simple preventive measure can greatly reduce the facial injuries of car accidents. Looming in the not-too-far distant future is the very real possibility that many acquired health problems will be corrected or ameliorated for total populations by use of vaccines, genetic engineering, or specifically targeted drugs. Strategies to Prevent the Plaque Diseases Before providing an overview of methods used to implement primary prevention programs, it is important to point out that both dental caries and periodontal disease are transmissible diseases. If a child is considered at high risk for caries, one of the parents usually the mother can usually be identified as high risk; if a child

has periodontal problems, usually one of the parents is also afflicted. Any infectious (acquired) disease can only begin if the challenge organisms are in sufficient numbers to overwhelm the combined manmade and body defenses and repair capabilities. For this reason, all strategies to prevent, arrest, or reverse the ravages of the plaque diseases are based on (1) reducing the number of challenging oral pathogens, (2) building up the tooth resistance and maintaining a healthy gingiva, and (3) enhancing the repair processes. In general, periodontal disease is a disease that involves the soft tissue and bone surrounding the affected teeth. Caries involves the demineralization and eventual cavitation of the enamel and often of the root surface. If the incipient lesions (earliest visible sign of disease) of caries and periodontal disease are recognized at the time of the initial/annual dental examination, they can often be reversed with primary preventive strategies. For caries, the visible incipient lesion is a white spot, which appears on the surface of the enamel as a result of subsurface acid-induced demineralization. For periodontal disease, the visible incipient lesion is gingivitis an inflammation of the gingiva that is in contact with the bacterial plaque. Not all "white spots" go on to become caries, nor do all cases of gingivitis go on to become periodontal disease. In both cases, i.e., caries and periodontal disease, it should be noted that if dental plaque did not exist, or if the adverse effects of its microbial inhabitants could be negated, the decrease in the incidence of the plaque diseases would be very dramatic. Based on these facts, it is understandable why plaque control is so important in any oral-health program.

To control the plaque diseases with available methods and techniques, strong emphasis has been directed to four general strategies to reduce caries and two administrative requirements:

General Strategies

1. Mechanical (toothbrush, dental floss, irrigator, or rinse) 2. Chemical plaque control. Use of fluorides to inhibit demineralization and to enhance remineralization; use of antimicrobial agents to suppress cariogenic bacteria.

3. Sugar discipline.

4. Use of pit and fissure sealants, when indicated, on posterior occlusal surfaces Administrative

5. Education and health promotion.

6. Establish access to dental facilities where diagnostic, restorative, and preventive services are rendered, and where planned recalls based on risk are routine. The use of fluorides has provided exceptionally meaningful reductions in the incidence of dental caries. Because of water fluoridation, fluoride dentifrices, and mouthrinses, dental caries is declining throughout the industrialized world. Historically, the injection of fluoride into water supplies in the mid-20th century resulted in a decrement of approximately 60 to 70% in caries. Since that time, fluoride has been introduced into proprietary products such as dentifrices and mouthrinses. As a result, the caries decrement directly attributable to water fluoride over the past years has declined. Yet, the placement of fluoride into communal water supplies still results in an estimated 20 to 40% reduction in coronal caries, and a similar 20 to 40% decrease in root caries.

Sugar and Diet

The development of dental caries depends on four interrelated factors: (1) diet, (2) inherent factors of host resistance, (3) the number of challenge bacteria located in the dental plaque, and (4) time. Without bacteria, no caries can develop. For the bacteria in the plaque to live, they must have the same amino acids, carbohydrates, fatty acids, vitamins, and minerals that are required for all living organisms. Because these nutrients are also required by the cells of the body, the food that is ingested by the host or that which later appears in the saliva in a metabolized form, provides adequate nutrients for bacterial survival and reproduction. With three well-balanced meals per day, however, the usual plaque bacteria probably would not release a sufficient quantity of metabolic acids to cause caries development. But, as soon as sugar and sugar products are included in the diet of the host, bacterial acid production markedly increases in the plaque. This release of acid end-products is the major cause of the initiation and progression of caries. Of even greater importance than the total intake of refined carbohydrates is the frequency of intake and the consistency of the sugar-containing foods.⁴³ The continuous snacking of refined carbohydrates that characterizes modern living results in the teeth being constantly exposed to bacterial acids. For example, the prolonged adherence of sugar products to the teeth, such as that experienced after eating taffies

and hard candies; results in prolonged production of the plaque acids that are in direct contact with the tooth surface. Thus, if caries incidence is to be reduced, all three factors total intake of sugar, consistency of the cariogenic foods, and especially frequency of intake should be considered.

Pit and Fissure Sealants

Approximately 90% of all the carious lesions in the mouth occur on the occlusal surfaces of the posterior teeth. These surfaces represent only 12% of the total number of tooth surfaces, so that occlusal surfaces with their deep pits and fissures are approximately eight times as vulnerable as all the other smooth surfaces. The availability of sealants offers an alternative to a restoration. With the use of sealants, a thin layer of a plastic, called Bis-GMA, is flowed into the deep occlusal pits and fissures of teeth not having open carious lesions. This action effectively isolates these areas from the oral environment. Since no cavity preparation is necessary, no pain or discomfort accompanies sealant placement. Following the placement of the sealant in the deep fissures, the newly created fossae can be effectively cleaned with a toothbrush.

Access to Comprehensive Dental Care

This factor is probably the most important of all preventive options. Without the benefit of a routine periodic dental examination, it is difficult for individuals to realize that they are vulnerable to oral disease. The first indication of a dental problem is pain, which is the wrong starting point for prevention.

Prognostic and Diagnostic Tests

Several methods for preventing the onset or progress of caries and periodontal disease have been discussed. Because it is impossible to apply vigorously all the preventive procedures to all the people all the time, it would be desirable to have some tests to indicate the extent of caries and periodontal disease risk of an individual at any given time. This need is highlighted by the fact that an estimated 60% of all carious lesions in schoolchildren occur in 20% of the students. It would save much time to be able to identify this 20% group of high-risk students without having to examine an entire school population. Although no tests are 100% correlated with the extent of caries activity or periodontal disease, several test proce-

dures are sufficiently well correlated with either condition to be of interest. To be successful, such screening tests should be simple to accomplish, valid, economical, require a minimum of equipment, be easy to evaluate, and be compatible with mass-handling techniques. Laboratory methods exist for counting the number of bacteria in the saliva. If the caries-causing mutans streptococci or lactobacilli counts are high, the individual from whom the sample was derived can be presumed to have a higher risk for dental caries, whereas a low count permits the opposite assumption.

Summary

Primary prevention is of great importance in dentistry. Yet, strategies now exist that with patient knowledge and cooperation, could greatly aid in preventing, arresting, or reversing the onset of caries or periodontal disease. The six general approaches to the control of both caries and periodontal disease involve (1) plaque control, (2) water fluoridation and use of fluoride products for self-care and for professionally initiated remineralization procedures, (3) placement, when indicated, of pit and fissure sealants, and (4) sugar discipline. Supporting these measures are (5) public and private enterprise financed media distributed programs extolling the benefits of oral health and proprietary products for family prevention; and (6) access to a dental facility where diagnosis, comprehensive preventive, restorative treatment, and planned recall and maintenance programs are available. The zeal and thoroughness with which these preventive measures should be prescribed and used are indicated by the information obtained from the clinical and roentgenographic oral examination, dietary analysis, patient history, and laboratory tests. Proper primary prevention can bring a great revolution in the field of dentistry.

References :

1. Edelstein BL. Evidence-based dental care for children and the age 1 dental visit. *Pediatr Ann.* 1998;27:569-574.
2. Newacheck PW, Hughes DC, Hung YY, Wong S, Stoddard JJ. The unmet health needs of America's children. *Pediatrics.* 2000;105:989-997.
3. Caufield PW, Griffen AL. Dental caries. An infectious and transmissible disease. *Pediatr Clin North Am.* 2000;47:1001-1019, v.

4. U.S. Department of Health and Human Services. Oral Health in America: a Report of the Surgeon General. Rockville, Md: USDHHS, National Institute of Dental and Craniofacial Research; 2000;Pub No 00-4713.
5. Vargas CM, Crall JJ, Schneider DA. Sociodemographic distribution of pediatric dental caries: NHANES III, 1988-1994. J Am Dent Assoc. 1998;129:1229-1238.
6. Ismail AI, Sohn W. A systematic review of clinical diagnostic criteria of early childhood caries. J Public Health Dent. 1999;59:171-191.
7. Kaste LM, Selwitz RH, Oldakowski RJ, Brunelle JA, Winn DM, Brown LJ. Coronal caries in the States, 19primary and permanent dentition of children and adolescents 1-17 years of age: United 88-1991. J Dent Res. 1996;75 Spec No:631-641.
8. Mouradian WE, Wehr E, Crall JJ. Disparities in children's oral health and access to dental care. JAMA. 2000;284:2625-2631.
9. Kaste LM, Drury TF, Horowitz AM, Beltran E. An evaluation of NHANES III estimates of early childhood caries. J Public Health Dent. 1999;59:198-200.
10. Brown LJ, Wall TP, Lazar V. Trends in untreated caries in primary teeth of children 2 to 10 years old. J Am Dent Assoc. 2000;131:93-100.
11. Edelstein BL , Young children. Dental Care Considerations of Disadvantaged and Special Care Populations. In: Bonito AJ, Cooper LY, (Eds). Rockville, MD: Bureau of Health Professions, Health Resources and Services Administration; 2001.
12. Sheiler B, Williams BJ, Lombardi SM. Diagnosis and treatment of dental caries-related emergencies in a children's hospital. Pediatr Dent. 1997;19:470-475.
13. U.S. Surgeon General's Report: Part II. (2000). What is the status of oral health in America, 35-39.
14. Evans, C. A., & Kleinman, D. V. (2000). The Surgeon General's report on America's oral health: Opportunities for the dental profession. JADA, 31:1721-28.
14. Milgrom P., & Reisine, S. (2000). Oral health in the United States: The postfluoride generation. Annu Rev Public Health, 21:403-36.
15. Watt, R., & Sheiham, A. (1999). Inequalities in oral health: A review of the evidence and recommendations for action. Br Dent J, 187:6-12.5. Locker, D. (2000). Deprivation

- and oral health. *Community Dent Oral Epidemiology*, 28:161-9.
16. Marcias, E. P., & Morales, L. S. (2001). Crossing the border for health care. *J Health Care Poor Underserved*, 12:77-87.
17. Waldman, H. B., & Permeh, S. P. (2001). Community-based dental services for patients with special needs. *NY State Dent J*, 67:39-42.
18. Waldman, H. B., & Perlman, S. P. (2000). Providing general dentistry for people with disabilities; a demographic review. *Gen Dent*, 48:566-9.
19. Cho, I. (2000). Disparity in our nation's health: Improved access to oral health care for children. *NY State Dent J*, 66:34-7.
20. Mouradian, W. E., Wehr, E., & Crall, J. J. (2000). Disparities in children's oral health and access to dental care. *JAMA*, 284:2625.
21. Gilchrist, J. A., Brumley, D. E., & Blackford, J. U. (2001). Community status and children's dental health. *JADA*, 132:216-22.
22. Newacheck, P. W., Hughes, D. C., Hung, W. R., Wong, S., & Stoddard, J. J. (2000). The unmet needs of America's children. *Pediatrics*, 105:989-97.
23. Warren, J. J., Cowen, H. J., Watkins, C. M., & Hand, J. S. (2000). Dental caries prevalence and dental care utilization among the very old. *JADA*, 131:1571-9.
24. Stearns, S. C., Slifkin, R. T., & Edin, H. M. (2000). Access to care for rural Medicare beneficiaries. *J Rural Health*, 16:131-42.
25. Hicks, M. J., Flaitz, C. M., Carter, A. B., Cron, S. G., Rossman, S. N., Simon, C. L., Demmler, G. J., & Kline, M. W. (2000). Dental caries in HIV-infected children: a longitudinal study. *Pediatr Dent*, 22:359-64.
26. Gilbert, G. H., Foerster, U., Dolan, T. A., Duncan, R. P., & Ringelburg, M. L. (2000). Twenty-four month coronal caries incidence: The role of dental care and race

GAS AS A GREEN GROWTH ENERGY FOR INDIA A CRITICAL REVIEW

Udai Kumar Uprit
Research Scholar, Hamidia College,
Barkatullah University, Bhopal (MP) (INDIA)

Abstract

This paper deals with the review based on in-depth knowledge of Gas as Fuel for India, its existing and future aspects in the context of Indian economy, Indian energy sector and its impact on the consumers and lifestyle. This paper touches about the major drivers for the Gas energy and catalyst which supports the logic. It critically analyses its issue based retardants and a possible outlook under the purview of Domestic Market, government regulations, economy and WTO norms.

Introduction

India's energy sector has huge deficit wherein growth of the demand is organic with growing population. Starting from every home to every industry, energy is a must. While energy is a must and so is the manner in which is consumed and exhausted. Today energy contributes maximum budget deficit to Indian economy which is majorly due to huge import bills either from petrol, oil or even gas. Since energy is widely used in development of infrastructure which is must for any economy to grow, it is imperative for us to understand the right solution mix. Fuel energy is also direct input to the production of fertilizers which is essential for the agriculture based economy like India. Today with growing global concerns on the Pollution level, global warming, green ecosystem which impacts every human life, India

needs to have an energy option which leads supports green initiatives and works towards a better healthier life in India.

Issue is particularly concerning for India wherein most of the metro cities which have dense population has pollution level crossing beyond normal level. A recent World Health Organization (WHO) study ranks India as one of the most polluted countries in the world. India is home to 13 of the world's 20 most polluted cities, with air pollution impacting more than half the population by reducing its lifespan by three years on average. This is affecting everybody human life and possible difficult life in India.

This grave concern needs to be serious thought process that India needs to adopt measure to have green energy fuel which boost economy, environment and yet supports budget by lower cost and higher availability.

Discussion

Indian economy in spite of running into growth figure of 7 % has huge deficit on its budget coming from growing energy needs of country. India imports 70% of the oil wherein there is no price fixed for a long term. Variation of the Oil price is daily and it further attenuated by having fluctuating currency. At no point of time India can fix or plan its year budget for Energy sector. It is leading to an uncertain budget which means deviation in growth and growing deficit on the Indian economy.

Indian is an agricultural based economy wherein the most common form of energy is generated thru Coal or wood based which is by far the cheapest and widely available compared to any other forms of fuel or energy. But certainly this Coal based fuel gives rise to pollution which is making things and impacts every day's life. Today, India does not qualify to WTO norms as it does not meet the Green Environment grades. Recently Indian Government has committed to Green Initiatives but this needs to be well supported by the polices and framework towards achieving it. This will help us getting more trade, business agreement and possible growth in our exports

An Agriculture based economy has fertilizers the main input component. Energy is must for the production in the fertilizer industries. So energy is growth for India. India is also becoming hub for producing products at the better cost and so there is an ever growing increase in

the consumption of the energy need.

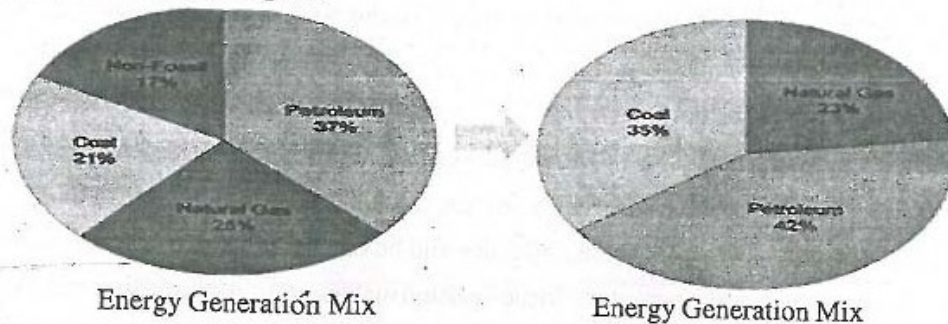
Energy is an infrastructure and infrastructure is needed to make the country grow and produce more. It also leads to better life. Like any other country, India needs the un interrupted energy supply at the remotest of locations while the reality is that even the capital of India has power cuts which clearly leads to loss of the business and growth of economy.

India is price sensitive country where in cheap products are sold and used often as long as they the end objective. In India, for all the energy needs at home, cheapest and widely available forms of energy is the wood coal which is widely used in the rural areas. In the major cities, there is an even balance between the emission made by the vehicles compared trees planted leads to an ecosystem which is highly polluted.

Indian Government wants to promote the consumption of Gas and use it as alternative to fuel for Automobile and cooking. There has been major big finds in gas exploration which further support government initiatives. However there are some issues in the area of pricing, distribution and volume of production of gas between the Public and Private sector companies.

Certainly India needs a cleaner, greener, widely available and better cost option for the energy which can largely be met by the local production.

India is typical agriculture based economy which is equally supported by the Coal based fossil energy which runs the rural India. India has the largest coal reserve in the world and equally so that it is the cheapest energy resource to its citizens. On the same side Coal based energy produces the maximum pollution but certainly cost has been ruling the case. Below states shows confirm the figure.



Energy sector touches the human thru out his life span. Direct and visible benefits of energy are from Light, Fuel, Cooking and power while there is huge list of indirect cost that comes from everyday products that are produced from factories that run by energy. It is important also to understand as at what cost we are getting this energy other than prices. Energy needs to be produced from eco-friendly resources or thru the sources which do not disturb the living style and natural resources by polluting thru emissions.

Indian conventional energy mix clearly suggest that we are leading to become one of the most polluted country in the world in the times to come.

Alternatives

Alternatives for the cleaner energy are the fuels like oil, gas and non-fossil .The jig saw to choose a fuel which meets the condition which are favorable to nation interest. Factor which govern to meet the above with a comparison on each of the alternative as below

1. Availability and & Supply

Energy is Scarce, critical and important resource for the whole world. Clearly demand is much higher than the supply.

Oil is by far the most common supplier of energy in the world but its presence is limited to few countries and those countries are governed by few nations. So the supply and availability is depending upon the world dynamics and there is not much India can control there.

Non- fossil is a resource which is available largely but its supply depend upon the nature and this makes it a non-continuous energy source.

Gas is resource which is more widely available than Oil and its availability is also quite intense. Important for Gas as option is its supply or the distribution infrastructure which demands high investments

2. Cost and price fluctuation

Since the Energy resources are scarce and its cost & price fluctuates depending upon the political scenario of the world economy. All the resources have cost and price fluctuation. Important is for India to contribute, influence and be one of the supplier in any of the resource to have equal or informed say in the decision making. Gas resource in India is higher than Oil resources and recent discovery in KG basis establishes the fact that we can have

more substantial resources in the future.

3. Emissions and Green Initiatives

Every energy is generated and used at the cost of some emission of gases. Now it is important to choose an option which has the lowest impact on the emissions and makes the life better for its citizens. India by far due to agricultural driven country has lot at stake due high usage of Coal based energy. This source generates maximum emissions and there needs to be a resource which can replace it thru wide availability and cheaper. Refer to the above pollution matrix, other than non-fossil, gas is only the resource which reduces or contributed lesser to pollution than the energy it produces for the nation.

Gas a Green Fuel for Growth

India is uses conventional and non-conventional energy resource for Gas production. There are identifies Gas finds and also areas wherein Coal Bed Methane technology is widely explored by Public and private companies in India.

There is an optimism in gas production due to recent find of large Gas basin in Krishna Godavari in addition to main on shore fields. States of Assam in the northeast, Gujarat in the west and Tamil Nadu and Andhra Pradesh in the south are traditional gas fields. However there are some challenges due to natural reason like surface complexity and internal issues on the pricing, domestic consumers.

Natural gas has a relatively small share (6%) of the domestic energy mix. Optimism about the pace of expansion, fuelled by some large discoveries in the early 2000s, has been dashed by lower than expected output from offshore domestic fields.

While challenges are and will be there but there is certain and distinct plus points which gas possess over options as below

- ☐ Less Pollution and Emission norms
- ☐ In house resources - KG Basin
- ☐ Promotes Fertilizers and agriculture Industry lifeline for India
- ☐ Lower Import Lower deficit
- ☐ WTO norms meeting would encourage trade with the world
- ☐ Better Supply large piped infra-structure in and outside country

¢ Low costing is cheaper for the consumers and better for life

Step Forward

All the above speaks volumes about the benefits but certainly, any reaping of benefits requires actions at the behest of the country. Few of the steps which can certainly act as catalyst to achieving the objective are discussed as below

¢ Auto Industry Alignment

Today, India is fastest growing auto market in the world and there is potential of more 60% of the market still un-tapped. This means that we need to take steps now to ensure once the % Auto penetration reaches to 60%, the pollution level of the country still remains under control to do this , government needs to bring policies which guides the Auto manufacturers to prioritize the sale of gas vehicles over petrol and diesel.

¢ Industrial supply

India is growing and becoming major manufacturing hub especially with Government encouraging schemes like Make in India. It is important to make guideline for the new and upcoming manufacturing units to certain minimum % of their energy required should be from gas .This will encourage the industry by having lower energy cost and in turn will help them achieve their Corporate social responsibilities of the better living and green initiatives.

¢ Availability and distribution

India has Gas distribution infrastructure mainly on Piped Network and other one distributed Sub Station models. GAIL being one of the leading gas provider holds 80% of Piped gas infrastructure while private players are working on the substation based distribution model. One obvious reason for the private players is that piped gas required huge capital initial investments while they still await a clear supportive policy on the pricing and distribution on the gas to consumers. But certainly Gas availability with any of the model needs to be expanded to be made available.

¢ Global Pipeline project

In addition to developing in house production of gas, there has to be model which assures balance distribution of in house and import of gas. This is in line with using your own limited energy resources for the longer run. Contracts and dependencies with Other Gas

providers of the world like Iran, Qatar by mutually building infrastructure to ensure secured business / revenue for them and continuous supply to us .This would require un interrupted supply of the gas thru global pipe line which can be done mutual consortium and agreements.

€ Government Policies

India has unearthed one of the biggest gas in in the KG basin blocks and RIL has it. However the price at which RIL can give to consumers is controlled by Government and influenced by PSU. This does not encourage competition and the benefit to the consumers. Clarity needs to be expedited. Government also needs to agree and clear the policy on the global pipe gas project from Iran with other neighboring countries. Government has roll guidelines for the minimum percentage of vehicles produced needs to be on Gas fuel.

Conclusion

India is the third largest emitter of greenhouse gases, after China and the US. A recent World Health Organization (WHO) study ranks India as one of the most polluted countries in the world. India is home to 13 of the world's 20 most polluted cities, with air pollution impacting more than half the population by reducing its lifespan by three years on average. It's disturbing that more than half of India's energy supply needs are met by coal-fired plants. Among the various causes of pollution - burning of firewood, fuel adulteration, vehicle emissions - are coal-based power plants. They release particulate matter, sulphur dioxide, nitrogen oxides (NOx), and volatile organic compounds and trace metals like mercury into the air, which affect health adversely.

A long-term and feasible solution to control air pollution is to switch to natural gas for power generation. A higher share of natural gas in the installed capacity of energy from 9% in 2014 to 20% by 2030 is an imperative. Gas-based power stations have no particulate emissions and much lower NOx emissions.

Use vehicles that run on compressed natural gas (CNG). Over the past few years, CNG became the most popular fuel due price difference and a large number of petrol cars have been retro-fitted to run on CNG. Studies have shown that CNG is much more environment friendly in terms of carbon emissions and pollutants like SO₂. Running car on green fuel

will help to keep a check on air pollution in city like Mumbai, where the use of vehicles are primarily responsible for deteriorating air quality.

Overall, we have a viable and feasible solution of moving the Gas as the main energy resource replacing coal and this can be achieved by taking the right quick steps we discussed above.

References :

- Joshi, S.; Jung, N. (2008) 'Natural Gas in India' in Stern, J. (ed) Natural Gas in Asia: The Challenges of Growth in China, India, Japan and Korea; Oxford University Press
- All India Electricity Statistics: General Review, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, New Delhi, 2008.
- Annual Report; Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India, 2007. Available at: http://petroleum.nic.in/jsp/annual_report.jsp.
- Basic Statistics on Indian Petroleum and Natural Gas, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Economic Division Government of India, 2009.
- Gas Price Hiked: Power, CNG Prices to Go Up', The Indian Express, 20 May 2010.
- LNG re-gasification capacity will reach 20 MMTPA by 2012', Business Line, 23/3/ 2010.
- '37 power plant proposals on hold for want of gas', India E-News, 10 September 2009.
- RNRL joins race for power plant near Dabhol', The Financial Express, 17 June 2009.
- EGOM decision regarding commercial utilisation of gas produced under NELP', Press Information Bureau, Government of India, 16 November 2009.
- Government asks Reliance to supply KG gas first to urea plants', Business Line, 25 June 2008.
- Decision regarding sale of Natural Gas by NELP contractors and order of Priority to supply gas from RIL's kg D6 field', Press Information Bureau, Government of India, 25 June 2008.
- ¢ Central Electricity Authority www.cea.nic.in
- ¢ Planning Commission <http://planningcommission.nic.in/>
- ¢ Ministry of Power www.powermin.nic.in
- ¢ Ministry of Petroleum and Natural Gas <http://petroleum.nic.in/>
- ¢ ILO Statistics Database <http://laborsta.ilo.org/>

- ¢ Federal Reserve of Cleveland, World Inflation Database www.clevelandfed.org/research/data/world-inflation/index.cfm
- ¢ Petroleum Planning and Analysis Cell, Ministry of Petroleum, Government of India www.ppac.org.in/
- ¢ Ministry of Coal, Government of India <http://coal.nic.in/>
- ¢ Tongia, R. (2003). The Political Economy of Indian Power Sector Reforms. Working Paper No.4, Program on Energy and Sustainable Development, Stanford University.

"Buddhism" Introduction of Gautama Budhdha

DR. S.K. Ojha

Asso. Prof. And Head Dep. Of History

Faculty of Social Science,

M.M.V. Vishwavidyalaya, Karaundi, Katni, M.P.

Abstract : Buddhism is a religion and dharma that encompasses a variety of traditions, beliefs and spiritual practices largely based on teachings attributed to Gautama Buddha, commonly known as the Buddha ("the awakened one"). According to Buddhist tradition, the Buddha lived and taught in the northern part of the Indian subcontinent, sometime between the 6th and 4th centuries BCE in the ancient Magadha kingdom. He is recognized by Buddhists as an awakened, divine, or enlightened teacher who shared his insights to help sentient beings end their suffering through the elimination of ignorance and craving. Buddhists believe that this is accomplished through the direct understanding and perception of dependent origination and the Four Noble Truths.

Introduction : Two major extant branches of Buddhism are generally recognized by scholars: Theravada Buddhism (Pali: "The School of the Elders") and Mahayana Buddhism (Sanskrit: "The Great Vehicle"). In Theravada Buddhism, the ultimate goal is the attainment of the sublime state of Nirvana, achieved by practicing the Noble Eightfold Path (also known as the Middle Way), thus escaping what is seen as a cycle of suffering and rebirth. Theravada has a widespread following in Sri Lanka and Southeast Asia.

Mahayana Buddhism, which includes the traditions of Pure Land, Zen, Nichiren Buddhism, Shingon, and Tiantai (Tendai) is found throughout East Asia. Rather than Nirvana, Mahayana instead aspires to Buddhahood via the bodhisattva path, a state wherein one remains in the cycle of rebirth to help other beings reach awakening. Vajrayana, a body of teachings attrib-

uted to Indian siddhas, may be viewed as a third branch or merely a part of Mahayana; Tibetan Buddhism, which preserves the Vajrayana teachings of eighth century India, is practiced in regions surrounding the Himalayas, Mongolia and Kalmykia. Tibetan Buddhism aspires to Buddhahood or rainbow body.

Buddhist schools vary on the exact nature of the path to liberation, the importance and canonicity of various teachings and scriptures, and especially their respective practices. Buddhism denies a creator deity and posits that mundane deities such as Mahabrahma are misperceived to be a creator. Instead, the foundations of Buddhist tradition and practice are the Three Jewels: the Buddha, the Dharma (the teachings), and the Sangha (the community). "Taking refuge" in the triple gem has traditionally been a declaration and commitment to being on the Buddhist path, and in general distinguishes a Buddhist from a non-Buddhist. Development along the Buddhist path is generally accomplished by practicing some or all of the Ten Meritorious Deeds; however, the threefold practice of generosity, virtue, and meditation (including samatha and vipassan?) is often given special emphasis. Other practices include the study of scriptures; cultivation of higher wisdom and discernment; renouncing conventional living and becoming a monastic; devotional practices; ceremonies; the Mahayana practices of bodhicitta, invocation of buddhas and bodhisattvas, and the Vajrayana practices of Generation stage and Completion stage.

Buddhists number between an estimated 488 million and 535 million, making it one of the world's major religions.

Life of the Buddha : This section may lend undue weight to certain ideas, incidents, or controversies. Please help to create a more balanced presentation. Discuss and resolve this issue before removing this message.

"The Great Departure", relic depicting Gautama leaving home, first or second century .

This narrative draws on the Nid?nakath? of the Jataka tales of the Theravada, which is ascribed to Buddhaghosa in the 5th century CE. Earlier biographies such as the Buddhacarita, the Lokottarav?din Mah?vastu, and the Sarvastivadin Lalitavistara Satra, give different accounts. Scholars are hesitant to make unqualified claims about the historical facts of the Buddha's life. Most accept that he lived, taught and founded a monastic order, but do not

consistently accept all of the details contained in his biographies. According to author Michael Carrithers, while there are good reasons to doubt the traditional account, "the outline of the life must be true: birth, maturity, renunciation, search, awakening and liberation, teaching, death." In writing her biography of the Buddha, Karen Armstrong noted, "It is obviously difficult, therefore, to write a biography of the Buddha that meets modern criteria, because we have very little information that can be considered historically sound... [but] we can be reasonably confident Siddhatta Gotama did indeed exist and that his disciples preserved the memory of his life and teachings as well as they could."

The evidence of the early texts suggests that Siddh?rtha Gautama was born in a community that was on the periphery, both geographically and culturally, of the northeastern Indian subcontinent in the fifth century BCE. It was either a small republic, in which case his father was an elected chieftain, or an oligarchy, in which case his father was an oligarch. The Vajrashila, where Gautama sat under a tree and became enlightened, Bodh Gaya, India, 2011.

According to this narrative, shortly after the birth of young prince Gautama, an astrologer named Asita visited the young prince's father, Suddhodana, and prophesied that Siddhartha would either become a great king or renounce the material world to become a holy man, depending on whether he saw what life was like outside the palace walls. ?uddhodana was determined to see his son become a king, so he prevented him from leaving the palace grounds. But at age 29, despite his father's efforts, Gautama ventured beyond the palace several times. In a series of encounters-known in Buddhist literature as the four sights-he learned of the suffering of ordinary people, encountering an old man, a sick man, a corpse and, finally, an ascetic holy man, apparently content and at peace with the world. These experiences prompted Gautama to abandon royal life and take up a spiritual quest. Dhamek Stupa in Sarnath, India, where the Buddha gave his first sermon. It was built by Ashoka. Gautama first went to study with famous religious teachers of the day, and mastered the meditative attainments they taught. But he found that they did not provide a permanent end to suffering, so he continued his quest. He next attempted an extreme asceticism, which was a religious pursuit common among the aramaas, a religious culture distinct from the Vedic

one. Gautama underwent prolonged fasting, breath-holding, and exposure to pain. He almost starved himself to death in the process. He realized that he had taken this kind of practice to its limit, and had not put an end to suffering. So in a pivotal moment he accepted milk and rice from a village girl and changed his approach. He devoted himself to anapanasati meditation, through which he discovered what Buddhists call the Middle Way (Skt. madhyama-pratipad): a path of moderation between the extremes of self-indulgence and self-mortification.

Gautama was now determined to complete his spiritual quest. At the age of 35, he famously sat in meditation under a *Ficus religiosa* tree now called the Bodhi Tree in the town of Bodhi Gaya and vowed not to rise before achieving enlightenment. After many days, he finally destroyed the fetters of his mind, thereby liberating himself from the cycle of suffering and rebirth, and arose as a fully enlightened being (Skt. samyaksa?buddha). Soon thereafter, he attracted a band of followers and instituted a monastic order. Now, as the Buddha, he spent the rest of his life teaching the path of awakening he had discovered, traveling throughout the northeastern part of the Indian subcontinent and died at the age of 80 (483 BCE) in Kushinagar, India. The south branch of the original fig tree available only in Anuradhapura Sri Lanka is known as Jaya Sri Maha Bodhi.

Life and the world

Within Buddhism, samsara is defined as the continual repetitive cycle of birth and death that arises from ordinary beings' grasping and fixating on a self and experiences. Specifically, samsara refers to the process of cycling through one rebirth after another within the six realms of existence, where each realm can be understood as physical realm or a psychological state characterized by a particular type of suffering. Samsara arises out of avidya (ignorance) and is characterized by dukkha (suffering, anxiety, dissatisfaction). In the Buddhist view, liberation from samsara is possible by following the Buddhist path.

In Theravada Buddhism there can be no divine salvation or forgiveness for one's karma, since it is a purely impersonal process that is a part of the makeup of the universe. [citation needed] In Mahayana Buddhism, the texts of certain Mahayana sutras (such as the Lotus Sutra, the Aagulimslysa Satra and the Mahsysna Mahaparinirvaea Satra) claim that the reci-

tation or merely the hearing of their texts can expunge great swathes of negative karma. Some forms of Buddhism (for example, Vajrayana) regard the recitation of mantras as a means for cutting off of previous negative karma. The Japanese Pure Land teacher Genshin taught that Amitabha has the power to destroy the karma that would otherwise bind one in samsara.

Rebirth refers to a process whereby beings go through a succession of lifetimes as one of many possible forms of sentient life, each running from conception to death. The doctrine of anattā (Sanskrit anātman) rejects the concepts of a permanent self or an unchanging, eternal soul, as it is called in Hinduism and Christianity. According to Buddhism there ultimately is no such thing as a self independent from the rest of the universe. Buddhists also refer to themselves as the believers of the anatta doctrine-Nairatmyavadin or Anattavadin. Rebirth in subsequent existences must be understood as the continuation of a dynamic, ever-changing process of pratītyasamutpāda ("dependent arising") determined by the laws of cause and effect (karma) rather than that of one being, reincarnating from one existence to the next.

Each rebirth takes place within one of five realms according to Theravadins, or six according to other schools.

1. Naraka beings: those who live in one of many Narakas (Hells);
2. Preta: sometimes sharing some space with humans, but invisible to most people; an important variety is the hungry ghost.
3. Animals: sharing space with humans, but considered another type of life;
4. Human beings: one of the realms of rebirth in which attaining Nirvana is possible;
5. Asuras: variously translated as lowly deities, demons, titans, or anti-gods; not recognized by Theravada tradition as a separate realm.
6. Devas including Brahmās: variously translated as gods, deities, spirits, angels, or left untranslated.

The above are further subdivided into 31 planes of existence.[web 4] Rebirths in some of the higher heavens, known as the Buddhavasa Worlds or Pure Abodes, can be attained only by skilled Buddhist practitioners known as anāgāmis (non-returners). Rebirths in the form-

less realms can be attained by only those who can meditate on the arapajhanas, the highest object of meditation.

According to East Asian and Tibetan Buddhism, there is an intermediate state (Tibetan "bardo") between one life and the next. The orthodox Theravada position rejects this; however there are passages in the Samyutta Nikaya of the Pali Canon that seem to lend support to the idea that the Buddha taught of an intermediate stage between one life and the next.

Noble Eightfold Path

Main articles: Noble Eightfold Path and Buddhist Paths to liberation

The Dharmachakra represents the Noble Eightfold Path

The Noble Eightfold Path—the fourth of the Buddha's Noble Truths—consists of a set of eight interconnected factors or conditions, that when developed together, lead to the cessation of dukkha.[45] These eight factors are: Right View (or Right Understanding), Right Intention (or Right Thought), Right Speech, Right Action, Right Livelihood, Right Effort, Right Mindfulness, and Right Concentration.

Ajahn Sucitto describes the path as "a mandala of interconnected factors that support and moderate each other." The eight factors of the path are not to be understood as stages, in which each stage is completed before moving on to the next. Rather, they are understood as eight significant dimensions of one's behaviour—mental, spoken, and bodily—that operate in dependence on one another; taken together, they define a complete path, or way of living.

Statue of Buddha in Wat Phra Si Rattana Mahathat, Phitsanulok, Thailand

While he searched for enlightenment, Gautama combined the yoga practice of his teacher Kalama with what later became known as "the immeasurables".[dubious - discuss] Gautama thus invented a new kind of human, one without egotism.[dubious - discuss] What Thich Nhat Hanh calls the "Four Immeasurable Minds" of love, compassion, joy, and equanimity[full citation needed] are also known as brahmaviharas, divine abodes, or simply as four immeasurables. Pema Chödrön calls them the "four limitless ones". Of the four, mettā or loving-kindness meditation is perhaps the best known. The Four Immeasurables are taught as a form of meditation that cultivates "wholesome attitudes towards all sentient beings."

This section does not cite any sources. Please help improve this section by adding citations

to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.

Monks debating at Sera Monastery, Tibet Buddhist scholars have produced a number of intellectual theories, philosophies and world view concepts (see, for example, Abhidharma, Buddhist philosophy and Reality in Buddhism). Some schools of Buddhism discourage doctrinal study, and some regard it as essential practice.

The concept of liberation (nirvasa)-the goal of the Buddhist path-is closely related to overcoming ignorance (avidya), a fundamental misunderstanding or mis-perception of the nature of reality. In awakening to the true nature of the self and all phenomena one develops dispassion for the objects of clinging, and is liberated from suffering (dukkha) and the cycle of incessant rebirths (sastra). To this end, the Buddha recommended viewing things as characterized by the three marks of existence.

Three Marks of Existence

The Three Marks of Existence are impermanence, suffering, and not-self.

Impermanence expresses the Buddhist notion that all compounded or conditioned phenomena (all things and experiences) are inconstant, unsteady, and impermanent. Everything we can experience through our senses is made up of parts, and its existence is dependent on external conditions. Everything is in constant flux, and so conditions and the thing itself are constantly changing. Things are constantly coming into being, and ceasing to be. Since nothing lasts, there is no inherent or fixed nature to any object or experience. According to the doctrine of impermanence, life embodies this flux in the aging process, the cycle of rebirth (sa's'ra), and in any experience of loss. The doctrine asserts that because things are impermanent, attachment to them is futile and leads to suffering.

Suffering (is also a central concept in Buddhism. The word roughly corresponds to a number of terms in English including suffering, pain, unsatisfactoriness, sorrow, affliction, anxiety, dissatisfaction, discomfort, anguish, stress, misery, and frustration. Although the term is often translated as "suffering", its philosophical meaning is more analogous to "disquietude" as in the condition of being disturbed. As such, "suffering" is too narrow a translation with "negative emotional connotations" that can give the impression that the Buddhist view is pessimistic, but Buddhism seeks to be neither pessimistic nor optimistic, but realistic. In

English-language Buddhist literature translated from P?li, "dukkha" is often left untranslated, so as to encompass its full range of meaning.

Angkor Thom in Cambodia : Not-self is the third mark of existence. Upon careful examination, one finds that no phenomenon is really "I" or "mine"; these concepts are in fact constructed by the mind. In the Nikayas anatta is not meant as a metaphysical assertion, but as an approach for gaining release from suffering. In fact, the Buddha rejected both of the metaphysical assertions "I have a Self" and "I have no Self" as ontological views that bind one to suffering.[note 10] When asked if the self was identical with the body, the Buddha refused to answer. By analyzing the constantly changing physical and mental constituents (skandhas) of a person or object, the practitioner comes to the conclusion that neither the respective parts nor the person as a whole comprise a self.

Dependent arising

The doctrine of pratyasamutpada, (Sanskrit; Pali: paticcasamupp?da; Tibetan Wylie: iten cing 'brel bar 'byung ba; Chinese:) is an important part of Buddhist metaphysics. It states that phenomena arise together in a mutually interdependent web of cause and effect. It is variously rendered into English as "dependent origination", "conditioned genesis", "dependent relationship", "dependent co-arising", "interdependent arising", or "contingency". Mahayana Buddhism received significant theoretical grounding from Nagarjuna (perhaps c. 150-250 CE), arguably the most influential scholar within the Mahayana tradition. Nagarjuna's primary contribution to Buddhist philosophy was the systematic exposition of the concept of aanyat?, or "emptiness", widely attested in the Prajñaparamit? sutras that emerged in his era. The concept of emptiness brings together other key Buddhist doctrines, particularly anatta and dependent origination, to refute the metaphysics of Sarvastivada and Sautrantika (extinct non-Mahayana schools). For Nagarjuna, it is not merely sentient beings that are empty of atman; all phenomena (dharmas) are without any svabhava (literally "own-nature" or "self-nature"), and thus without any underlying essence; they are "empty" of being independent; thus the heterodox theories of svabhava circulating at the time were refuted on the basis of the doctrines of early Buddhism. Nagarjuna's school of thought is known as the M?dhyamaka. Some of the writings attributed to Nagarjuna made explicit

references to Mahayana texts, but his philosophy was argued within the parameters set out by the agamas. He may have arrived at his positions from a desire to achieve a consistent exegesis of the Buddha's doctrine as recorded in the Canon. In the eyes of Nagarjuna the Buddha was not merely a forerunner, but the very founder of the M?dhyamaka system.[58] Sarvastivada teachings-which were criticized by Nagarjuna-were reformulated by scholars such as Vasubandhu and Asanga and were adapted into the Yogacara school. While the M?dhyamaka school held that asserting the existence or non-existence of any ultimately real thing was inappropriate, some exponents of Yogacara asserted that the mind and only the mind is ultimately real (a doctrine known as cittamatra). Not all Yogacarins asserted that mind was truly existent; Vasubandhu and Asanga in particular did not. These two schools of thought, in opposition or synthesis, form the basis of subsequent Mahayana metaphysics in the Indo-Tibetan tradition.

Besides emptiness, Mahayana schools often place emphasis on the notions of perfected spiritual insight (prajñāparamit?) and Buddha-nature (tath?gatagarbha). There are conflicting interpretations of the tath?gatagarbha in Mah?y?na thought. The idea may be traced to Abhidharma, and ultimately to statements of the Buddha in the Nikayas. In Tibetan Buddhism, according to the Sakya school, tathagatagarbha is the inseparability of the clarity and emptiness of one's mind. In Nyingma, tath?gatagarbha also generally refers to inseparability of the clarity and emptiness of one's mind. According to the Gelug school, it is the potential for sentient beings to awaken since they are empty (i.e. dependently originated). According to the Jonang school, it refers to the innate qualities of the mind that expresses themselves as omniscience etc. when adventitious obscurations are removed. The "Tath?gatagarbha Sutras" are a collection of Mahayana sutras that present a unique model of Buddha-nature. Even though this collection was generally ignored in India,[59] East Asian Buddhism provides some significance to these texts.

Liberation

This section focuses too much on specific examples without clearly discussing its abstract general subject. Please help by consulting secondary sources for general statements made about the subject and improving this section by adding more general information. (March

2016)

Mahabodhi temple in Bodhgaya, India, where Gautama Buddha attained Nirvana under the Bodhi Tree (left)

Main article: Nirvana (Buddhism)

Nirvana (Sanskrit; Pali: "Nibbāna") means "cessation", "extinction" (of craving and ignorance and therefore suffering and the cycle of involuntary rebirths (saasara)), "extinguished", "quieted", "calmed"; it is also known as "Awakening" or "Enlightenment" in the West. The term for anybody who has achieved nirvana, including the Buddha, is arahant.

Bodhi is a term applied to the experience of Awakening of arahants. Bodhi literally means "awakening", but it is more commonly translated into English as "enlightenment". In Early Buddhism, bodhi carried a meaning synonymous to nirvana, using only some different metaphors to describe the experience, which implies the extinction of raga (greed, craving), dosa (hate, aversion) and moha (delusion). In the later school of Mahayana Buddhism, the status of nirvana was downgraded in some scriptures, coming to refer only to the extinction of greed and hate, implying that delusion was still present in one who attained nirvana, and that one needed to attain bodhi to eradicate delusion:

An important development in the Mahayana [was] that it came to separate nirvana from bodhi ('awakening' to the truth, Enlightenment), and to put a lower value on the former (Gombrich, 1992d). Originally nirvana and bodhi refer to the same thing; they merely use different metaphors for the experience. But the Mahayana tradition separated them and considered that nirvana referred only to the extinction of craving (passion and hatred), with the resultant escape from the cycle of rebirth. This interpretation ignores the third fire, delusion: the extinction of delusion is of course in the early texts identical with what can be positively expressed as gnosis, Enlightenment.

Therefore, according to Mahayana Buddhism, the arahant has attained only nirvana, thus still being subject to delusion, while the bodhisattva not only achieves nirvana but full liberation from delusion as well. He thus attains bodhi and becomes a buddha. In Theravada Buddhism, bodhi and nirvana carry the same meaning as in the early texts, that of being freed from greed, hate and delusion.

The term parinirvana is also encountered in Buddhism, and this generally refers to the complete nirvana attained by the arahant at the moment of death, when the physical body expires.

References :

- " " Lopez, Donald. "Buddha: Founder of Buddhism". Encyclopedia Britannica. Retrieved 6 March 2016.
- " " Guang Xing (2005). The Three Bodies of the Buddha: The Origin and Development of the Trikaya Theory. Oxford: Routledge Curzon: pp.1 and 85
- " " Gethin 1998, pp. 27-28, 73-74.
- " " White, David Gordon (ed.) (2000). Tantra in Practice. Princeton University Press. p. 21. ISBN 0-691-05779-6.
- " " Powers, John (2007). Introduction to Tibetan Buddhism (Rev. ed.). Ithaca, New York: Snow Lion Publications. pp. 26-27. ISBN 978-1-55939-282-2.
- " " "Candles in the Dark: A New Spirit for a Plural World" by Barbara Sundberg Baudot, p305
- " " Powers, John (2007). Introduction to Tibetan Buddhism (Rev. ed.). Ithaca, New York: Snow Lion Publications. pp. 392-3, 415. ISBN 978-1-55939-282-2.
- " " Shults, Brett (May 2014). "On the Buddha's Use of Some Brahmanical Motifs in Pali Texts". Journal of the Oxford Centre for Buddhist Studies 6: 119.
- " " Williams, Paul. Buddhist Thought. Routledge, 2000, pages 131.
- " " Williams, Paul. Mahayana Buddhism: The Doctrinal Foundations 2nd edition. Routledge, 2009, pg. 47.
- " " Guang Xing. The Concept of the Buddha: Its Evolution from Early Buddhism to the Trikaya Theory. 2004. pp. 65-66 "Several scholars have suggested that the Prajñāpāramitā probably developed among the Mahasamghikas in Southern India, in the Andhra country, on the Krsna River."



Instruction for contributors/Authors

The journal "*Naveen Samajik Shodh*" publishes original articles, original research articles focusing on research which is useful societal development. It may include research from multiple disciplines like Medical, Engineering, Social Sciences, Tribal Areas and various other but should have some research component for societal developments. The official language is Hindi. Articles can be accepted in English with Hindi abstract.

All manuscripts/articles sent to the "*Naveen Samajik Shodh*" must be submitted solely to this journal, should not have been published in any substantial form in any other publication, professional or lay and will become property of the publishers. All manuscripts must be accompanied by the following written statement signed by all authors. The Undersigned authors certifies that the article is original, is not under considered by any other journal and has not been previously published. All copyright ownership of the manuscript entitled (Title of article) is hereby transferred to the publishers of the *Naveen Samajik Shodh*.

The editorial board of *Naveen Samajik Shodh* follows the protocol. The editors with the help of members of the editorial board review all materials in accordance with strict policy as the journal is a critically referred journal and is used as a resource by researches in various faculties. Authors will be given total freedom of communication in case their article/manuscript requires interaction with the editorial board. Decision of Editorial board will be final and is to be accepted by the submitting authors.

All statements, opinions expressed in the manuscript are those of the authors and not those of the editor(s) or publishers. The editor(s) and publishers will not take any responsibility for such materials.

The editor(s) and publishers also do not guarantee, warrant or endues any product or service advertised in the journal nor do they guarantee any claim made by manufacturer of such product or service.

Instructions for Preparing Manuscripts-

The manuscript/Article should be submitted on CD on PageMaker or M. S. Word to the editor. However 2 copies of the manuscript/Article on Hard Copy Size A4 Pages should be sent along with the CD.

Length of Article-

The article/manuscript submitted for publication should not exceed the limit (8 typed pages for review article, 6 typed pages for original article, 4 pages for case report or summary document and 2 pages for short communications including Book Reviews)

International Research Journal

अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका

ISSN-0975-4431

नवीन सामाजिक शोध

ISSN No. 0975-4431

25 रूप नगर कालोनी, जे. के. रोड, भोपाल

RNI No. MPHIM/2009/29572

मासिक शोध पत्रिका का वार्षिक/आजीवन सदस्य बनने हेतु

सदस्यता फार्म

नई सदस्यता

मवीकरण

वार्षिक 1000/-

आजीवन 10000/-

श्री/श्रीमती जन्मतिथि
पता
पोस्ट तहसील जिला राज्य
पिनकोड सदस्यता शुल्क रुपये (शब्दों में)
बैंक/डी.डी./मनीऑर्डर क्र.
बैंक दिनांक मोबाइल फोन ईमेल

प्रदायकर्ता

नवीन सामाजिक शोध

ISSN No. 0975-4431

25 रूप नगर कालोनी, जे. के. रोड, भोपाल

RNI No. MPHIM/2009/29572

For annual and Lifetime membership

New membership

renewal

annual . 1000/-

Lifetime 10000/-

Mr./Mrs/Ms Date of Birth.....

Address.....

Post..... Tehsil..... District..... State..... Pin.....

Membership fee Rs. (in words)

cheque/DD/moneyorder No..... Bank.....

Date..... Mo..... Ph..... E-mail.....

Rs.

Provider



9893086017
9993673675
8085556284

एम.आई.आफसेट वर्क्स

सभी प्रकार के मल्टीकलर पोस्टर, पम्पलेट,
ब्रोशर, बैनर, दैनिक/साप्ताहिक समाचार
पत्रों एवं मासिक पत्रिकाओं
की आफसेट मशीन द्वारा
छपाई उचित दामों पर की जाती है।

एक बार अवश्य पधारें

कार्यालय 105, बजाज काम्पलेक्स, चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल

प्रधान कार्यालय : 91, रशीदिया स्कूल के पास, बरखेड़ी, भोपाल

mioffset@yahoo.com, mioffset@gmail.com



TAKSHSHILA COLLEGE

Gram - Jhirniya, Post-Mugaia Hat, Parwaliya Sadak, NH-12, Bioara Road, Bhopal

SINCE 1996

Recognised by M.P. Govt. Coll. of Madya Pradesh & Affiliated to Bharatiya Mahavidyalaya Bhopal, M.P. Board of Sec. Education (M.P.)

Admission Through
Online Counseling



Courses Offered

Under Graduate Programs

B.Com. (Plain, Computers, Tax Procedure & Practice)

B.Sc. (Mathematics, I.T., CS, Electronics, Chemistry, Physics, Zoology, Botany, Microbiology, Bio-tech)

B.C.A. (Computer Application)

B.A. (History, Economics, Political Science, Hindi/English Literature, Sociology)

B.B.A.

Post Graduate Programs

M.Sc. (Computer Science, Chemistry)

M.Com. (Tax, Management)

M.C.M.

P.G.D.C.A.

B.Ed., D.Ed./D.El.Ed.



Facilities

- Govt. Scholarship facility available.
- Bilingual Teaching faculty (Hindi, English).
- Well Experienced & Qualified staff.
- College Bus Facility.
- Well equipped laboratory of all practical subject.
- Internet & Wi-Fi Campus.
- Huge Digital Library.
- Training & Placement Cell.
- Canteen facility.
- Personality development classes.
- Indoor and Outdoor Games facility.

College level
Scholarship for
Deserving Students

M.P. Online
Kiosk Facility
Available

Admission Helpline No. : 9893014415, 9893421526, 7771049449



SINCE 1996

तक्षाशिला कॉलेज

ग्राम झिरनिया, पोस्ट-मुनालिया हाट, परवलिया सड़क, एनएच-12, ब्यावरा रोड, भोपाल

(राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली एवं म.प्र. शासन से मान्यता प्राप्त तथा नरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से संबद्ध)

Courses Offered

Under Graduate Programs

B.Com. (Plain, Computers, Tax Procedure & Practice)

B.Sc. (Mathematics, I.T., CS, Electronics, Chemistry, Physics, Zoology, Botany, Microbiology, Bio-tech)

B.C.A. (Computer Application)

B.A. (History, Economics, Political Science, Hindi/English Literature, Sociology)

B.B.A.

Post Graduate Programs

M.Sc. (Computer Science, Chemistry)

M.Com. (Tax, Management)

M.C.M.

P.G.D.C.A.

B.Ed., D.Ed./D.El.Ed.

1995 से लगातार

दिनांक 18 वर्षों से जब शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित अध्यापिका

इयना नगर भोपाल से ग्राम झिरनिया, पोस्ट-मुनालिया हाट, परवलिया सड़क, एनएच-12, ब्यावरा रोड, भोपाल नवीन एवं विशाल भवन में स्थानांतरित

प्रदेश
Online Counseling



Admission Helpline No. : 9893014415, 9893421526, 7771049449